चिंतन

स्कूलों में बेटियों को मिले गरीमामय वातावरण

किसी भी लोकतांत्रिक समाज की असली पहचान यह नहीं होती कि वह कितने कानून बनाता है, बल्कि यह होती है कि वे कानून आम नागरिक खासकर सबसे कमजोर वर्ग के जीवन में कितना बदलाव ला पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लड़कियों को मुफ़्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं, लड़के-लड़कियों के अलग शौचालय हों और दिव्यांगों के अनुकूल टॉयलेट बनाए जाएं, इसी बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि यह स्वीकारोक्ति है कि अब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था बेटियों की बुनियादी ज़रूरतों को समझने में असफल रही है। स्कूलों में बेटियों को गरीमामय वातावरण दिया जाना जरूरी है। यदि किसी स्कूल में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं हैं, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है और यदि मासिक धर्म के दौरान उन्हें बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं नहीं मिलतीं, तो यह अनुच्छेद 21, यानी जीवन और गरिमा के अधिकार पर चोट है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन संसाधनों की कमी और सामाजिक चुप्पी ने इसे शर्म और बाधा का विषय बना दिया। यही वजह है कि आज भी लाखों लड़कियां पीरियड्स के दिनों में स्कूल छोड़ने को मजबूर होती हैं। सोशल वर्कर जया ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका और पिछले चार वर्षों से चल रही सुनवाई इस सच्चाई को उजागर करती है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से नजरअंदाज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्पष्ट करता है कि अब इसे केवल नीति या योजना कहकर टालने की गुंजाइश नहीं है। आज भी देश के कई हिस्सों में लड़कियां मासिक धर्म के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूलों में न तो मुफ्त पैड उपलब्ध हैं और न ही इस्तेमाल किए गए पैड के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था। नतीजा यह होता है कि पढ़ाई प्रभावित होती है, आत्मविश्वास टूटता है और धीरे-धीरे स्कूल छोड़ने की नौबत आ जाती है। हाल के दिनों में 'पीरियड-शेमिंग' के खिलाफ जो गुस्सा सामने आया है, वह इसी दबे हुए दर्द का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की टिप्पणी इस सोच को उजागर करती है कि शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर मासिक धर्म को लेकर जो व्यवहार होता है, वह एक परेशान करने वाली मानसिकता को दर्शाता है। यह सिर्फ लड़कियों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा है। यह आदेश केवल स्कूल प्रबंधन या सरकारी तंत्र के लिए नहीं है। यह उन कक्षाओं के लिए है, जहां कोई बच्ची मदद मांगने से झिझकती है। यह उन शिक्षकों के लिए है, जो सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में विवश हैं। यह उन माता-पिता के लिए भी है, जो अक्सर चुप्पी साध लेते हैं, बिना यह समझे कि उनकी चुप्पी उनकी बेटी की शिक्षा पर कितना भारी पड़ सकती है। मासिक धर्म के दौरान सम्मानजनक सुविधा देना कोई एहसान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक और मानवीय जिम्मेदारी है। अब जरूरत है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आदेश को कागजों तक सीमित न रखा जाए। स्कूलों की मान्यता को इससे जोड़ना एक सख्त, लेकिन जरूरी कदम है। यह फैसला एक शुरुआत है उस बदलाव की, जहां शिक्षा के रास्ते में मासिक धर्म अब बाधा नहीं बनेगा, बल्कि समझ और संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया जाएगा।

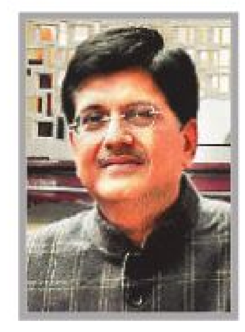

दृष्टिकोण
पीयूष गोयल

भविष्य का रोडमैप है भारत-ईयू एफटीए

> भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे तथा भारतीय युवाओं और किसानों के लिए व्यापक अवसरों का सृजन होगा। विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह एफटीए इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक है। वास्तव में यह व्यापार समझौते से ज्यादा व्यापक है। यह कृत्रिम मेधा (एआई), रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने वाली विस्तृत साझेदारी है। इस एफटीए से भारत के हर क्षेत्र और नागरिक तथा खास तौर से निर्धन तबकों को लाभ पहुंचेगा।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इससे लाखों रोजगार पैदा होंगे तथा भारतीय युवाओं और किसानों के लिए व्यापक अवसरों का सृजन होगा। इसके साथ ही लगभग 2 अरब की उस आबादी के लिए धन पैदा होगा, जो मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक-चौथाई भाग है। विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यह एफटीए इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक है। वास्तव में यह व्यापार समझौते से ज्यादा व्यापक है। यह कृत्रिम मेधा (एआई), रक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने वाली विस्तृत साझेदारी है। इस एफटीए से भारत के हर क्षेत्र और नागरिक तथा खास तौर से निर्धन तबकों को लाभ पहुंचेगा।

यह एफटीए नियम आधारित व्यापार और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करता है जिससे भारत स्वदेशी और विदेशी निवेश के लिए और ज्यादा आकर्षक बनेगा। यह छोटे व्यवसायियों, स्टार्टअप संस्थाओं और कामगारों के लिए अनेक अवसर पैदा करेगा। विश्व ने प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा की सराहना करते हुए इस एफटीए को सभी समझौतों से बड़ा बताया है। यह वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में स्थिरता को मजबूत करता है। यह भारत और यूरोपीय संघ को मुक्त बाजार, पूर्वानुमान क्षमता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध भरोसेमंद साझेदारों के रूप में स्थापित करता है। भारत ने व्यापार मूल्य के हिसाब से यूरोपीय संघ में अपने 99 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात के लिए अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्राप्त की है जिससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बल मिलेगा। इस एफटीए से कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, चमड़ा, फुटवियर, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरी सामान और ऑटोमोबाइल जैसे श्रमसाध्य क्षेत्रों को निर्णायक मजबूती मिलेगी। इस समझौते से लगभग 33 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर 10 प्रतिशत तक टैरिफ खत्म होगा। इससे कामगारों, हस्तशिल्पियों, महिलाओं, युवाओं तथा सूक्ष्म, छोटे और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) का सशक्तिकरण होगा। वैश्विक मूल्य श्रृंखला से भारतीय व्यवसाय ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। यह समझौता व्यवसायियों और पेशेवर तबके के लिए दूसरे देशों में जाने को आसान बनाते हुए शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और कंप्यूटर जैसे सेवा क्षेत्रों में अवसरों के नए द्वार खोलता है। इन प्रतिबद्धताओं से उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसरों के खुलने के साथ ही प्रतिभा, नवोन्मेष और संवहनीय आर्थिक विकास के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होती है।

व्यापार समझौते गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने की मोदी सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। इस रणनीति में क्रांतिकारी सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत

करना तथा सभी पक्षों के लिए लाभकारी समझौते के उद्देश्य से विकसित और पूरक अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत शामिल है। यह रणनीति भारत को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने और उन लाभकारी बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाती है जो कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हुए श्रमसाध्य क्षेत्रों में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। विकसित देशों के साथ व्यापार समझौते भारतीय उद्योगों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करते हैं और उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। मोदी सरकार ने ऐसे समझौते किए हैं, जिनमें टैरिफ में कमी धीरे-धीरे की जाती है। इससे उद्योगों को उचित नीतिगत समर्थन के साथ अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण का केंद्र है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के पूरी तरह अनुरूप है। यह भारत को वैश्विक मंच पर एक गतिशील, विश्वसनीय और दूरदर्शी भागीदार के रूप में स्थापित करता है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए समावेशी, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार विकास की नींव रखता है। मोदी सरकार ने सिर्फ़ विकसित देशों के साथ ही व्यापार समझौते किए हैं, जो कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, और हस्तशिल्प जैसे भारत के प्रमुख रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। यह यूपीए शासन से बिल्कुल उल्टा है उन्होंने प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के साथ समझौतों में जल्दबाजी की और अक्सर भारत को मिलने वाले लाभ की तुलना में कहीं अधिक रियायतें दीं। मोदी सरकार ने अर्थशास्त्रियों, औद्योगिक निकायों, विशेषज्ञों और कई सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद ही मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। परिणामस्वरूप, मोदी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक व्यापार समझौते को उद्योगों से व्यापक सराहना मिली है। मोदी सरकार द्वारा संपन्न प्रत्येक मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों पक्षों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं और भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार किया है। इन समझौतों ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनने की दिशा में उसकी यात्रा को तेज किया है।

यूपीए के कार्यकाल के दौरान, यूरोपीय संघ सहित विकसित देशों की भारत में रुचि कम हो गई थी, क्योंकि आर्थिक विकास धीमा हो गया था, मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई थी और व्यापार का माहौल निराशाजनक था। तब भारत ने ऐसे लाभप्रद व्यापार समझौतों के मूल्यवान अवसर गंवा दिए, जो विकास को गति दे सकते थे और रोजगार पैदा कर सकते थे। मोदी सरकार द्वारा संपन्न अन्य व्यापार समझौतों के साथ, भारत-ईयू एफटीए, ढुलमुल और निर्णायक नेतृत्व के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। जहाँ पहले की सरकारें हिचकिचाती थीं और घुटने टेकती थीं वहीं मोदी सरकार ने बदलाव लाने वाला एक ऐसा समझौता किया है जो बाजारों का विस्तार करने के साथ साथ रोजगार पैदा करता है और भारत के मुख्य हितों की रक्षा करता है। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक स्पष्टता नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है, जो देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकते हैं।

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

आरक्षण
शशि शेखर

यूजीसी डैमेज कंट्रोल, पर असल नुकसान किसका

राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता और कोई भी मुद्दा वर्षों बाद जाकर फलीभूत होता है। जैसे, लोकपाल का मुद्दा हो या विधायिका में महिला आरक्षण का मुद्दा। ऐसे में, यह कयास लगाना गलत नहीं होगा कि यूजीसी नियमों के बाद, अब एक और पुरानी मांग निजी क्षेत्र में आरक्षण जोर पकड़ेगा। वैसे तो सर्वोच्च अदालत ने यूजीसी नियमों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन, इन नियमों के बाद अब यह कारवां निजी क्षेत्र में आरक्षण तक पहुंचेगा। तब किसका नुकसान ज्यादा होगा, किसका नुकसान कम और ऐसा क्यों और कैसे होगा, आइये, इस पर एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण से नजर डालते है। सर्वप्रथम, यूजीसी के बाद क्या हो सकता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में वोटर्स के हेड काउंट किए जाते हैं। जाहिर है, कोइ भी राजनीतिक दल ज्यादा वोट पाना चाहता है तो वह किसे ज्यादा तरजीह देगा? इसी सोच ने यूजीसी के नए नियमों को भी जन्म दिया था। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के दौरान, यह पहला ऐसा मास्टर स्ट्रोक था कि या तो विपक्ष का मुंह बंद था या समर्थन में खुल रहे थे।

2016 में संसद में स्वर्गीय राम विलास पासवान ने बार एक मांग रखी थी कि "एक ऐसा क़ानून लेकर आएं, जिससे पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का लाभ मिल सके।" जाहिर है, तब उस मांग पर किसी का ध्यान न जाना था, न गया। लेकिन, 21 दिसंबर 2021, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एक प्रेस रिलीज कहता है कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अफर्मेटिव एक्शन पर एक समन्वय समिति 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाई गयी थी। अब तक समन्वय समिति की 9 बैठकें हो चुकी हैं। पहली समन्वय समिति की बैठक में, यह कहा गया कि अफर्मेटिव एक्शन के मुद्दे बेहतर परिणाम पाने का सबसे अच्छा तरीका इंडस्ट्री द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई ही है। इस रिलीज के मुताबिक़, निजी क्षेत्र में आरक्षण के संदर्भ में, उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि आरक्षण कोई समाधान नहीं है, लेकिन वे हाशिये पर खड़े वर्ग, विशेषकर एससी और एसटी के लिए वर्तमान भर्ती नीति को विस्तारित करने में सरकार और एजेंसियों के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं और साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, शीर्ष उद्योग संघों ने समावेशन के लिए अपनी सदस्य कंपनियों के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता (वीसीसी) भी तैयार की है। बहरहाल, अभी तक सरकार या निजी क्षेत्र ने सीधे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन इस दिशा में बात आगे बढ़ती दिख रही है। 2016 में जो मांग राम विलास पासवान ने रखी थी, वो मांग खत्म नहीं हुई है और न ही उसे पूरी तरह नकारा गया है। बल्कि उस मांग पर धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सकारात्मक रूख के साथ बात आगे बढ़ रही हैं। 2029 से पहले, मौजूदा केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक शायद निजी क्षेत्र में आरक्षण हो सकता है! तब जो आज यूजीसी नियमों में ओबीसी शामिल किए हैं, क्या वे तब अपनी हिस्सेदारी नहीं चाहेंगे? हालांकि, कॉरपोरेट सेक्टर आसानी से आरक्षण स्वीकार कर लेगा, इसमें शंका है। वो भी एक साथ 50 फीसदी आरक्षण लागू करवा पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो। फिर भी सरकार 5 फीसदी या 10 फीसदी से शुरुआत तो करवा ही सकती है। जो कायदे से पहले एसटी, फिर एससी को निजी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ मिलता, क्या यूजीसी नियमों में ओबीसी को शामिल किए जाने की वजह से ऐसा संभव हो पाएगा? क्या ओबीसी वर्ग के लोग यह दावा नहीं करेंगे कि उन्हें भी साथ ही में ये अवसर मिले। क्योंकि सरकार मान चुकी है कि भेदभाव तो ओबीसी के साथ भी होता आ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एससी/एसटी वर्ग के लोगों के साथ। केंद्र सरकार की नौकरियों में सालाना दर पर ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ी तो जरूर है, लेकिन यह महज कुछेक हजार के आसपास है। एक बहुत बड़ी आबादी यानी ओबीसी, दलितों की ऐसी है जिन्हें सरकारी नौकरियों में अकोमडेट कर पाना संभव नहीं दिख रहा है। जाहिर है कि निजी क्षेत्र आखिर आरक्षण से अछूता क्यों रहे, ऐसी मांग वर्षों से होती आ रही है और शायद अब उसके मुकम्मल हो जाने की भी संभावना बन जाए। फिर, संख्या जिसकी जितनी भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी आबादी सर्वाधिक है। राजनीतिक रूप से वे किसी भी दल के लिए अपरिहार्य है। अब, यूजीसी नियमों में एक ही दायरे में ओबीसी/एससी/एसटी वर्ग को शामिल किए जाने के बाद, निजी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ जब मिलेगा, तब किसे भले ही अल्पकालिक लेकिन महत्वपूर्ण नुकसान होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है

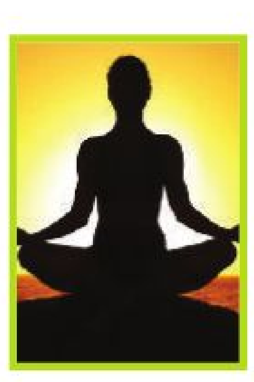

संकलित
दर्शन

योग प्रकृति की स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। योग के ही चलते मां के गर्भ में आना और जीवन धारण करना संभव होता है। उसके बाद जन्म लेते ही सांसारिक-योग आरंभ होता है। घर-परिवार और समाज के साथ योग जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है तथा जीवन के समापन पर फिर प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाकर विलीन होना भी योग है। ऋषियों ने प्रकृति की गूंज सुनकर उसमें त्रिस्तरीय योग का जो स्वरूप देखा उसमें 'ऊं' शब्द दिखाई पड़ा। इस 'ऊं' में 'अ', 'उ' और 'म' का योग है। गर्भ में अस्तित्व में आना 'अ', जन्म के बाद उत्थान 'उ' तथा मृत्यु 'म' का संयुक्त होना भी योग है। ऋषियों ने अंतिम अक्षर 'म' को हलंत कर आधा इसलिए कर दिया, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु पूरी नहीं होती। पंच भौतिक शरीर प्राकृतिक पदार्थों के साथ योग कर पुनः अनंत में विलीन हो जाता है, जबकि आत्मा जीवंत रहता है और पुनः नए शरीर के साथ योगभाव में आता है। प्राकृतिक योग को भी देखा जाए तो क्षिति तत्व धरती के साथ योगनिष्ठ होकर धरती में मिल जाता है, अग्नि आकाश की ओर अपने देही सूर्य के साथ योग करने को ऊपर की ओर उठती है तो जल, जल के साथ, वायु, वायु के साथ तथा गगन तत्व शून्य के साथ योग-भाव में हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो कदम-कदम पर योग का प्रकट भाव दिखाई पड़ता है। मानव शरीर के अंदर और बाहर जो योग हो रहा है, उसे नियमित जीवन में अपनाकर कोई भी व्यक्ति उर्ध्वमुखी जीवन प्राप्त कर सकता है।

मित्रता मुश्किल समय के लिए एक भरोसा है

संकलित
प्रेरणा

रामायण में हनुमान जी ने श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता करवाई थी। पहली मुलाकात में श्रीराम ने सुग्रीव से कहा कि मैं मेरी पत्नी सीता को खोज में जंगल-जंगल भटक रहा हूं, लेकिन आप तो राजा हैं। आप जंगल में क्यों रह रहे हैं? पहले सब ठीक था, लेकिन एक दिन हमारे राज्य में एक राक्षस आ गया तो बालि उसे मारने गया। सुग्रीव ने श्रीराम से अपना सारा वृतांत बताया कि कैसे भाई को गलतफहमी हुई। श्रीराम ने सुग्रीव की पूरी बात सुनी और कहा कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। पहले तो सुग्रीव को श्रीराम पर भरोसा नहीं हुआ। वह सोचने लगा कि बालि तो इतना बलवान है, राम उसे कैसे मार सकते हैं? ये कैसे मेरी मदद कर पाएंगे? सुग्रीव के चेहरे पर संदेह देखकर श्रीराम ने कहा कि सुग्रीव, अब मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र के छह गुण हैं। पहला, अपने दोस्त के दुख में दुखी होना। दूसरा, मित्र के दुख को दूर करने का प्रयास करना। तीसरा, मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकना। चौथा, लेन-देन के समय शंका न करना। पांचवां, हमेशा दोस्त का भला करना और छठा गुण है, विपत्ति के समय दोस्त के साथ खड़े रहना। ये सभी अच्छे मित्र के लक्षण हैं और तुम मुझे अपना मित्र समझ सकते हो। श्रीराम की बातें सुनकर सुग्रीव को उनकी बातों पर भरोसा हो गया। इसके बाद सुग्रीव ने भी सीता की खोज में मदद करने का वचन दिया। दोनों मित्रों ने एक-दूसरे की परेशानी को हल करने का संकल्प लिया।

अंतर्मन

आज की पाती

काबिल भारतीयों को देश निकाला

बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बाहर निकालने की बातें करते-करते इस देश ने कब अपने ही सवर्ण समाज को देश से भगाने की नीति बना ली, इसका जवाब कौन देगा? आरक्षण के नाम पर योग्यता का खुलेआम कत्ल हुआ, और मेहनती, काबिल सवर्ण युवाओं को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। आज सच्चाई यह है कि भारत अपने सबसे तेज दिमागों को खुद धकेल-धकेल कर यूएसए, यूके और यूरोप भेज रहा है। जिस प्रतिभा पर भारत को खड़ा होना था, वही प्रतिभा आज विदेशों की कंपनियों, लैब्स और यूनिवर्सिटीज की रीढ़ बन चुकी है।यह ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन एक्साइल है। अगर यही चलता रहा, तो आने वाली पीढ़ियां इतिहास में पढ़ेंगी कि भारत को किसी विदेशी ताकत ने कमजोर नहीं किया, भारत ने खुद अपनी सबसे काबिल संतानों को देश से बाहर निकाल दिया। - प्रदीप देशपांडे, बिलासपुर

ट्रेंड

बापू को नमन

महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। पूज्य बापू ने स्वदेशी, स्वाधीनता व स्वच्छता को एक सूत्र में बांधकर गौरवशाली भारत की कल्पना करने वाले महात्मा गाँधी के विचार हमें प्रेरित करते रहेंगे।
- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

प्रेम-सुंदर सम्मान

दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र के बच्चों को 'प्रेम-सुंदर सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। यह योजना इसी साल के दसवीं-बारहवीं के रिजल्ट से लागू होगी। मेरी अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
-शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

सूचना का अधिकार

आर्थिक सर्वेक्षण में सूचना के अधिकार अधिनियम की "पुनर्मूल्यांकन" की मांग की गई है। मोदी सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है।
- मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

सोशल मीडिया

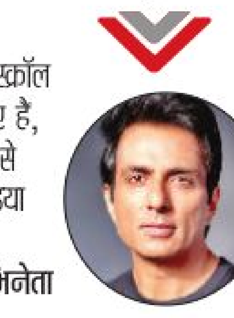

बच्चे खाना खाते समय सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, माता-पिता अनजान बने हुए हैं, यह हमारा भविष्य नहीं हो सकता। 16 से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना समय की मांग है।
- सोनू सूद, फिल्म अभिनेता

करंट अफेयर

अमेरिका भारत को 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाएगा

अमेरिका भारत को तीन प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाएगा जिन्हें देश के मंदिरों से अवैध रूप से हटा दिया गया था। वाशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एशियन आर्ट ने कहा कि तीन मूर्तियां भारत सरकार को वापस की जाएंगी। गहन जांच के बाद इन मूर्तियों के स्त्रोत का पता लगाया गया और रिपोर्ट में यह कहा गया कि इन मूर्तियों को मंदिरों से अवैध रूप से हटाया गया था। संग्रहालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने मूर्तियों में से एक को दीर्घकालिक ऋण पर देने पर सहमति व्यक्त की है। इस तरह की व्यवस्था के तहत संग्रहालय को वस्तु की उत्पत्ति, उन्हें हटाए जाने और वापसी की पूरी कहानी को सार्वजनिक रूप से साझा करने की अनुमति मिल जाएगी। ये मूर्तियां चोल काल (लगभग 990 ईस्वी) की 'शिव नटराज', चोल काल (12वीं शताब्दी) की 'सोमस्कंद' और विजयनगर काल (16वीं शताब्दी) की 'संत सुंदरार विद परवई' हैं। ये मूर्तियां 'दक्षिण भारतीय कांस्य ढलाई की समृद्ध कलात्मकता का उदाहरण हैं', जिन्हें पारंपरिक रूप से मंदिर की शोभायात्राओं में ले जाया जाता था। बयान में कहा गया है कि 'शिव नटराज' प्रतिमा को दीर्घकालिक ऋण पर रखा जाना है।

ऑफ बीट

जिम की जगह खुद घर पर कर सकते हैं व्यायाम

जीवन यापन की बढ़ती लागत के साथ, जिम की सदस्यता और फिटनेस कक्षाएं तेजी से अप्रचलित होती जा रही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप घर पर भी खुद से व्यायाम करके उतनी ही प्रगति कर सकते हैं। हृदय सहनशक्ति, मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन फिटनेस के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। और प्रत्येक को बहुत कम या बिना किसी उपकरण के खुद से किया जा सकता है। हृदय सहनशक्ति व्यायाम हृदय और फेफड़ों को काम करने वाली मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। पैदल चलना, जॉगिंग और दौड़ना बढ़िया विकल्प हैं, वैसे ही साइकिल चलाना, रस्सी कूदना और तैराकी भी है।अगला है मांसपेशियों की ताकत, जिसे हम प्रतिरोध व्यायाम के माध्यम से प्रशिक्षित करते हैं। यह हड्डियों के स्वास्थ्य, संतुलन और चयापचय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी मांसपेशियों और ताकत में गिरावट आती है। स्क्वैट्स – कूल्हों, घुटनों और टखनों को मोड़कर खड़े होने से लेकर छाती को ऊपर रखते हुए कूल्हों, घुटनों और टखनों को सीधा करके खड़े होने तक। बेहतर लचीलापन आपकी गति की सीमा को बढ़ा सकता है और दैनिक जीवन को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता में सुधार कर सकता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

सैमसन की फॉर्म और अक्षर की फिटनेस पर नजर

पांचवां टी-20: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज शाम 7 बजे से मुकाबला

एजेंसी ▶▶| तिरुवनंतपुरम

खिताब का प्रबल दावेदार भारत टी20 विश्व कप से पहले शनिवार को जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में खेलने के लिए उतरेगा तो उसे उम्मीद रहेगी कि संजू सैमसन अपने घरेलू दर्शकों के सामने फॉर्म में वापसी करने और अक्षर पटेल फिटनेस हासिल करने में सफल रहेंगे।

विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत ने प्रयोग करते हुए पांच मुख्य गेंदबाजों को ही खिलाया तथा ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं करवाई। भारत यह मैच हार गया था लेकिन इससे श्रृंखला के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि भारतीय टीम पहले ही इसे अपने नाम कर चुकी थी।

ईशान के रूप में सैमसन का मजबूत विकल्प

ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम के पास सैमसन का मजबूत विकल्प मौजूद है। उन्होंने इस श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन इस विकेटकीपर बल्लेबाज को अज्ञात चोट के कारण पिछले मैच से बाहर बैठना पड़ा था। ऑलराउंडर अक्षर भी नागपुर में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में उंगली में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे मैच से पहले नेट पर गेंदबाजी की थी।

गुजरात जाइंट्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर एलिमिनेटर में जगह बनाई

भाषा ▶▶| वडोदरा

कप्तान एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहैम के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर गुजरात जाइंट्स ने हरमनप्रीत कौर की 82 रन की आक्रामक पारी को बेनूर करते हुए गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराकर महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में प्रवेश कर लिया। गार्डनर ने 28 गेंद में 46 और वेयरहैम ने 26 गेंद में 44 रन बनाये थे। दोनों के बीच 71 रन की अहम साझेदारी के दम पर गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 167 रन बनाये। जवाब में मुंबई की टीम सात विकेट पर 156 रन ही बना सकी। कप्तान हरमनप्रीत ने अकेले किला लड़ाने की कोशिश करते हुए 48 गेंद में आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन बनाये लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं। यह लगातार आठ हार के बाद मुंबई इंडियंस पर गुजरात की पहली जीत है। मुंबई के भविष्य का फैसला अब रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वारियर्स के मैच के बाद होगा।

मुंबई को इतिहास में पहली बार हराया, गुजरात ने 11 रन से मैच जीता

खबर संक्षेप

स्क्वाश : क्वार्टर फाइनल में चोटरानी और अनाहत

नई दिल्ली। भारत के वीर चोटरानी ने पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में फ्रांस के विश्व में 19वें नंबर के खिलाड़ी बैपटिस्ट मासोटी को हराकर वाशिंगटन में चल रहे स्क्वाश ऑन फायर ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई लेकिन उनके हमवतन वेलवन सेंथिलकुमार मैक्सिको के दूसरी वरीयता प्राप्त लियोनेल कार्डेनास से हार गए। विश्व में 49वें नंबर के खिलाड़ी चोटरानी ने चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी खिलाड़ी को 11-6, 7-11, 8-11, 11-1, 11-9 से हराया। इस पीएसए कांस्य स्तर की प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड के छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डेक्लान जेम्स से होगा। महिला वर्ग में सातवीं वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने दूसरे दौर में दक्षिण अफ्रीका की हेले वार्ड को 11-5, 11-8, 12-14, 11-5 से हराया। वह क्वार्टर फाइनल में मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त सना इब्राहिम से भिड़ेंगी।

भुवनेश्वर में आज से अस्मिता रग्बी लीग

भुवनेश्वर। भारत के 24 टीमों के 300 से अधिक खिलाड़ी शनिवार से शुरू होने वाली दो दिवसीय अस्मिता रग्बी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेंगे। यह टूर्नामेंट भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) की 'अस्मिता' पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो महिला खेलों के लिए 'खेलो इंडिया' योजना का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ, ओडिशा सरकार के खेल एवं युवा सेवा विभाग (डीएसवाईएस) और ओडिशा रग्बी फुटबॉल संघ के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इसका लक्ष्य भारत में महिला रग्बी को बढ़ावा देना है। साइ ने कहा कि इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 24 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 336 खिलाड़ी और टीम अधिकारी शामिल हैं। इससे यह देश में आयोजित होने वाले सबसे बड़ा महिला रग्बी टूर्नामेंट में से एक बन गया है।

अभिषेक को दबाव में रखना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण

तिरुवनंतपुरम। अभिषेक शर्मा भले ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की तरह हों, लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के पास इस भारतीय सलामी

बल्लेबाज के लिए एक सरल रणनीति है, लगातार सटीक गेंदबाजी करके उन्हें दबाव में रखना। विशाखापत्तनम में चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हेनरी ने अभिषेक को गोल्डन डक (पहली गेंद पर आउट) कर दिया था, जिससे कीवी टीम को यह मैच 50 रन से जीतने में मदद मिली थी। हेनरी ने कहा, 'पिछले दो वर्षों से वह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्कि आईपीएल में भी गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियन ओपन: चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने कार्लोस

अल्काराज ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह, 5 सेटों में एलेक्जेंडर को हराया

एजेंसी ▶▶| मेलबर्न

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में जगह बनाई।

इस तरह से 22 साल के अल्काराज चारों ग्रैंड स्लैम पर प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अब उनका लक्ष्य करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनना होगा। अल्काराज को पांव में ऐंठन और खिंचाव के कारण पिछले साल के उपविजेता ज्वेरेव की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा लेकिन आखिर में वह पांच घंटे 27 मिनट में 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 से जीत हासिल करने में सफल रहे।

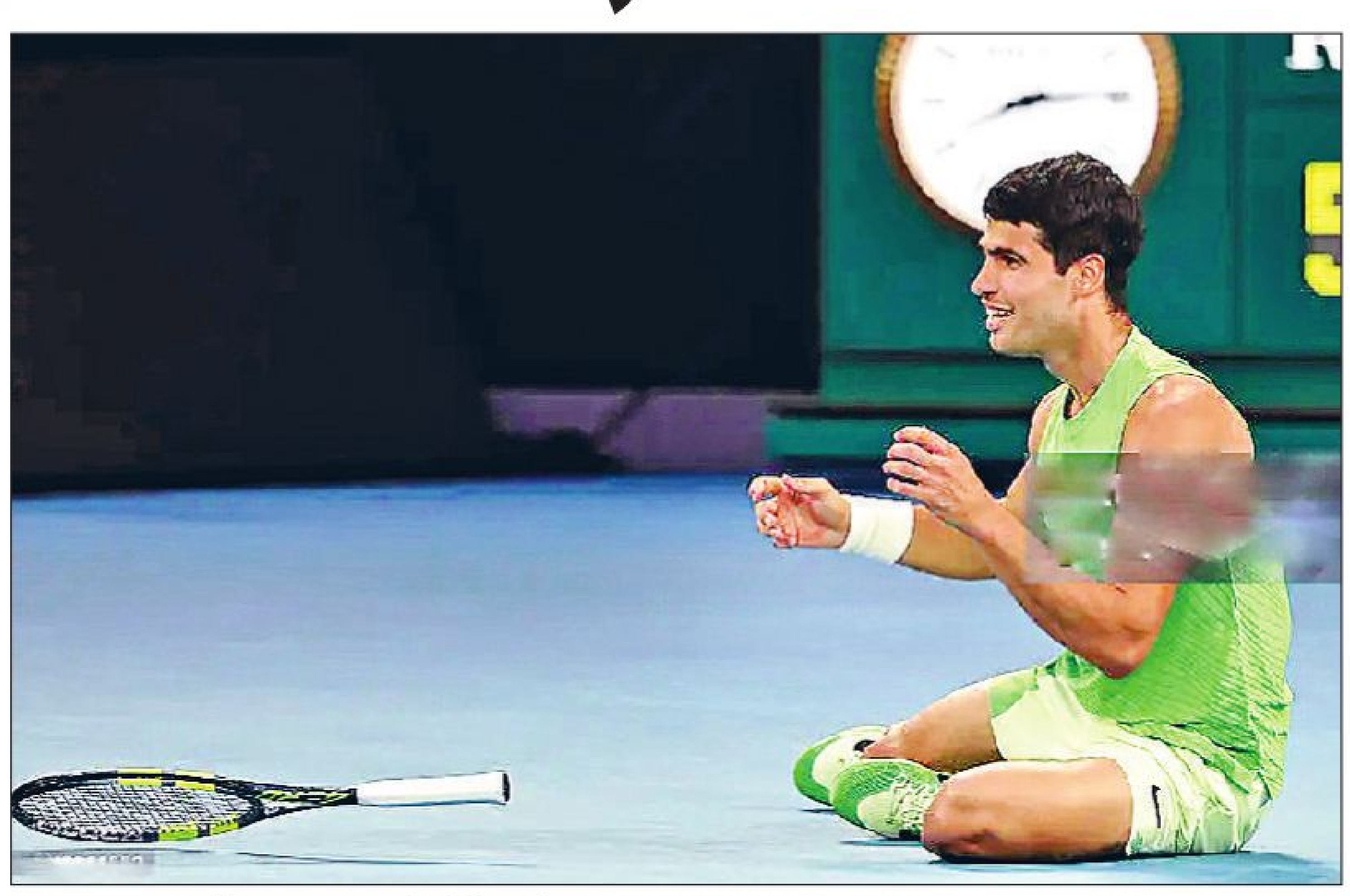

फाइनल में मुकाबला जोकोविच से

स्पेन के खिलाड़ी अल्काराज ने अच्छी शुरुआत की लेकिन पहले दो सेट जीतने के बाद वह अगले दो सेट में टाइब्रेकर में हार गए। ज्वेरेव पांचवें और निर्णायक सेट में एक समय मैच के लिए सर्विस कर रहे थे लेकिन अल्काराज ने ब्रेक प्वाइंट लेकर वापसी की और फिर इसके बाद जर्मनी के अपने प्रतिद्वंद्वी को मौका नहीं दिया। अल्काराज का फाइनल में मुकाबला 10 बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता नोवाक जोकोविच से होगा, जो 25वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने की कोशिश कर रहे हैं।

तीसरे सेट में लंगड़ाने लगे अल्काराज

अल्काराज ने जिस तरह से शुरुआत की थी उससे लग रहा था कि वह आसानी से जीत हासिल कर लेंगे लेकिन तीसरे सेट के नौवें गेम में वह लंगड़ाने लगे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें दाहिने पैर के ऊपरी हिस्से में कोई समस्या है। जब अपने प्रतिद्वंद्वी को इलाज के लिए तीन मिनट का ब्रेक दिया गया, तो ज्वेरेव स्पष्ट रूप से परेशान दिखे। तब तीसरी वरीयता प्राप्त यह खिलाड़ी टूर्नामेंट के एक अधिकारी से बात कर रहा था। अल्काराज ने इसके बाद 6-5 से बढ़त बना दी, जिसके बाद उन्हें फिर से अपने पांव की मालिश करवानी पड़ी। ज्वेरेव हालांकि इस सेट को टाइब्रेकर तक खींचने में सफल रहे, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की।

दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला

चौथे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला लेकिन ज्वेरेव टाइब्रेकर में फिर से कामयाब रहे और इस तरह से उन्होंने मैच को बराबरी पर ला दिया। चार घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद मैच पांचवें सेट में पहुंचा। अल्काराज ने पांचवें सेट के पहले गेम में अपनी सर्विस गंवा दी। इस सेट के छठे गेम में रोमांच तब चरम पर पहुंच गया जब अल्काराज ने ड्रॉप शॉट को लेने के लिए दौड़ लगाई और पूरी गति से स्लाइड करते हुए फोरहैंड विनर शॉट लगाया। इससे दर्शक खुशी से झूम उठे। अल्काराज ने आखिर में पांचवें सेट में 5-4 पर ज्वेरेव की सर्विस तोड़ी और फिर पहले मैच प्वाइंट को भुनाकर फाइनल में प्रवेश किया।

फुल्टोन ने मनप्रीत का बचाव करते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी

हॉकी इंडिया ने लिया आखिरी फैसला

भाषा ▶▶| नई दिल्ली

कोच क्रेग फुल्टोन ने अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को अनुशासनहीनता के आधार पर भारत की संभावित खिलाड़ियों की कोर सूची से बाहर किए जाने का कड़ा विरोध किया था। इस फैसले के बाद फुल्टोन ने इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी लेकिन हॉकी इंडिया द्वारा मनाने के बाद वह पद पर बने रहने के लिए राजी हो गए। विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि फुल्टोन ने राउरकेला में एक से सात फरवरी तक 33 कोर संभावित खिलाड़ियों के शिविर से मनप्रीत को हटाने के दबाव को 'बाहरी हस्तक्षेप' बताया था। यह बात सामने आई कि मनप्रीत पिछले साल दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन से जुड़े मामले में शामिल था। इसके बाद दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को 15 साल में पहली बार कोर संभावित खिलाड़ियों की सूची से बाहर किया गया। संभावित खिलाड़ियों को तय करने के लिए हुई बैठक में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की, महासचिव भोला नाथ सिंह और मुख्य चयनकर्ता आरपी सिंह ने मिलकर कहा कि मनप्रीत को बाहर किया जाना चाहिए जिसके बाद फुल्टोन परेशान हो गए।

हरियाणा टीम महिला सीनियर कबड्डी राष्ट्रीय चैम्पियन बनी

हैदराबाद। हरियाणा ने शुक्रवार को गत चैम्पियन भारतीय रेलवे को 39.37 से हराकर 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैम्पियनशिप जीत ली। निकिता ने हरियाणा के लिये 17 अंक बनाये जबकि रूचि ने नौ अंक जुटाये। भारतीय रेलवे के लिये पूजा ने सर्वाधिक 11 अंक बनाये। हरियाणा ने क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को और सेमीफाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराया था। वहीं रेलवे ने क्वार्टर फाइनल में महाराष्ट्र और सेमीफाइनल में तमिलनाडु पर जीत दर्ज की थी। हिमाचल और तमिलनाडु को कांस्य पदक दिया गया।

दिल्ली पर मुंबई का पलड़ा भारी सिद्धेश ने लगाया पांचवां शतक

मुंबई। संकटमोचक सिद्धेश लाड के सत्र के पांचवें शतक की मदद से मुंबई ने दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी के आखिरी लीग मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में बढ़त बना ली। तैंतीस वर्ष के लाड ने 178 गेंद में 12 चौकों की मदद से नाबाद 102 रन बनाए। यह रणजी ट्रॉफी में उनका लगातार चौथा शतक है, जिसकी मदद से मुंबई ने पांच विकेट पर 266 रन बना लिए हैं। लाड ने सुवेद पारकर (नाबाद 53) के साथ छठे विकेट की अटूट साझेदारी में 130 रन जोड़ लिए हैं। इससे पहले दिल्ली ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे। लाड ने मुंबई के लिए रणजी के एक सत्र में कम से कम पांच शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर और रूसी मोदी की बराबरी की।

टाटा स्टील मास्टर्स

डी गुकेश 11वें दौर में करेंगे हमवतन चिदंबरम का सामना

एजेंसी ▶▶| विज्क आन जी

विश्व चैंपियन डी गुकेश तुर्की के यागिज कान एर्दोगमस पर जीत के बाद टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में हमवतन अरविंद चिदंबरम का सामना करेंगे। साल के पहले सुपर टूर्नामेंट में अब केवल तीन दौर का खेल बाकी हैं। दस दौर का खेल होने के बाद उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव 6.5 अंकों के साथ आगे चल रहे हैं। उनके साथी खिलाड़ी जावोखिर सिंदारोव, जर्मनी के मैथियास ब्लूबाउम और स्थानीय स्टार जॉर्डन वैन फोरस्ट उनसे आधे अंक पीछे हैं। अमेरिका के हंस मोके नीमन और एर्दोगमस 5.5 अंकों के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर हैं। गुकेश, जर्मनी के विंसेंट कीमर और स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेडोसेव के पांच-पांच अंक हैं।

एरिगैसी से आगे प्रज्ञाननंदा

भारत के आर प्रज्ञाननंदा और अनीश गिरी 4.5 अंकों के साथ अर्जुन एरिगैसी से आधे अंक आगे हैं। अरविंद 3.5 अंकों के साथ चेक ग्रैंडमास्टर थाई दाई वान गुयेन से आधे अंक आगे हैं। विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गुकेश 12वें दौर में

नीमन और अंतिम दौर में कीमर से भिड़ेंगे। इस साल के अंत में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी प्रज्ञाननंदा ने शुरुआती दो मैचों में हार के बाद अभी तक अपनी लय हासिल नहीं की है। उनका अगला मुकाबला कीमर से होगा। एरिगैसी और चिदंबरम का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में निराशाजनक रहा है और उन्हें सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने के लिए बाकी बचे तीनों मुकाबले जीतने होंगे।

टेनिस टूर्नामेंट : गाडेकी-पीयर्स ने लगातार दूसरे साल जीता मिश्रित युगल का खिताब

एजेंसी ▶▶| मेलबर्न

ओलिविया गाडेकी और जॉन पीयर्स 1989 के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार दूसरे साल मिश्रित युगल का खिताब जीतने वाली पहली जोड़ी बन गई है। वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाली गाडेकी और पीयर्स की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने फाइनल में क्रिस्टीना म्लाडेनोविक और मैनुअल गिनार्ड की फ्रांसीसी जोड़ी को 4-6, 6-3, 10-8 से हराया।

फाइनल सेट के टाईब्रेकर में गाडेकी और पीयर्स की जोड़ी 7-5 से पिछड़ गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और 9-7 की बढ़त बना ली। मैच प्वाइंट पर गिनार्ड ने बैकहैंड शॉट नेट में मार दिया, जिससे रॉड लेवर

एरिना में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी अपना खिताब बचाने में सफल रही। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में इससे पहले जिम पुघ और याना नोवोत्ना ने 1988 और 1989 में लगातार खिताब जीते थे।

देविका थाईलैंड मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचीं

बैंकॉक। भारत की देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में घरेलू प्रबल दावेदार और शीर्ष वरीय सुपानिडा काटेथोंग को सीधे गेम में हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत की 20 वर्षीय गैर वरीय खिलाड़ी ने संयम से खेलते हुए 40 मिनट तक चले क्वार्टरफाइनल में सुपानिडा पर 21-19, 21-18 की जीत हासिल की। देविका ने पिछले साल मलेशिया इंटरनेशनल में पहला बीडब्ल्यूएफ अंतरराष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता था। विश्व रैंकिंग में 63वें नंबर की खिलाड़ी देविका अब अगले दौर में चीनी ताइपे की पांचवीं वरीयता प्राप्त ह्वांग यू-सुन से भिड़ेंगी। देविका ने अगस्त 2025 में मलेशिया इंटरनेशनल के फाइनल में हमवतन इशारानी बरुआ को हराया था। वह उस भारतीय मिश्रित टीम का भी हिस्सा थीं जिसने 2025 विश्व विश्वविद्यालय खेलों में कांस्य पदक जीता था। पिछले सत्र में देविका इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 की उप विजेता रहीं और 2024 में चार फाइनल में पहुंचीं।

टी-20: दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज से जीती सीरीज

सेंचुरियन। क्विंटन डीकॉक ने अपने 100वें टी20 मैच में शतक जड़ा, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर चार विकेट पर 221 रन बनाए। उसकी तरफ से शिमरोन हेटमायर (77) और ब्रेंडन किंग (49) ने दूसरे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 24 गेंद पर नाबाद 57 रन की तूफानी पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि डीकॉक की 49 गेंदों में 115 रन की मदद से 17.3 ओवर तीन विकेट पर 225 रन बनाकर 15 गेंद शेष रहते ही जीत हासिल कर ली।

डीकॉक ने अपने 100वें टी-20 मैच में लगाया शतक

डीकॉक ने लगाए 10 छक्के

डीकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस से उधार लिए बल्ले से खेलते हुए अपनी पारी में छह चौके और 10 छक्के लगाए। यह उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर है। रयान रिकेल्टन ने भी अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। उन्होंने 36 गेंदों में 77 रन की पारी खेली, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल हैं। कप्तान एडन मार्क्रम (15) के जल्दी आउट हो जाने के बाद डीकॉक और रिकेल्टन ने दूसरे विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की। श्रृंखला का तीसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा, जिसके बाद दोनों टीमें अगले सप्ताह भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए रवाना होंगी।

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधि. का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रु.में	बोर्ड/निगम/प्राधि. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी / सम्पर्क विवरण/ई-मेल
1	नगर परिषद बहादुरगढ़	एम.सी. बहादुरगढ़ में बालाजी हुडा पार्क नं. 7 से 2244पी सेक्टर 9ए तक सीसी गली और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण + 4 कार्य।	बंद होने की तिथि 03.02.2026	रु.2,85,71,367/-	https://etenders.hry.nic.in	9812433393 [illegible]
2	नगर परिषद बहादुरगढ़	नगर परिषद बहादुरगढ़ में विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार और साइन बोर्ड हेतु नाम बोर्ड का प्रावधान व फिक्सिंग।	बंद होने की तिथि 04.02.2026	रु.42,34,410/-	https://etenders.hry.nic.in	9812433393 [illegible]
3	नगर परिषद बहादुरगढ़	नगर परिषद बहादुरगढ़ में म्यूनिसिपल भूमि एमआईई पार्ट-बी में स्क्रैप यार्ड और डॉग शेल्टर का निर्माण + 2 कार्य।	बंद होने की तिथि 04.02.2026	रु.1,32,80,964/-	https://etenders.hry.nic.in	9812433393 [illegible]
4	नगर परिषद बहादुरगढ़	नगर परिषद बहादुरगढ़ में वार्ड 28 में नाला मरम्मत के साथ-साथ विभिन्न सीसी गलियों और स्वागत द्वार का पुनरोद्धार / निर्माण + 2 कार्य।	बंद होने की तिथि 05.02.2026	रु.1,16,48,576/-	https://etenders.hry.nic.in	9812433393 [illegible]

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in
संवाद-13/2026/80/42539/I/88/7 दि. 30.01.26

धैर्य की नौका ही संकट में बेड़ा पार लगाती है

शहरों की सुधि लें

यह अच्छा है कि बजट से पहले संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में अनेक चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इनमें से एक है शहरों का सही तरह विकास न होना। चूंकि इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, इसलिए उसकी महत्ता भी समझी जानी चाहिए और उस पर गंभीरता से ध्यान भी दिया जाना चाहिए। इससे शायद ही कोई असहमत हो कि शहर महज आवास नहीं हैं। वे एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसंरचना का रूप हैं। इसीलिए उन्हें आर्थिक विकास का इंजन कहा जाता है। हमारे शहर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे सुगम नागरिक जीवन के वैसे केंद्र नहीं बन पा रहे हैं, जैसे विश्व के अनेक देशों के शहर हैं। शहरी जीवन समस्याओं से घिर रहा है। वे तनाव, भीड़ और गंदगी का पर्याय बन रहे हैं। ऐसा अनियोजित और बेतरतीब विकास के कारण हो रहा है। एक विडंबना यह भी है कि आधारभूत ढांचे में छिटपुट सुधारों को शहरी विकास का पर्याय मान लिया गया है। इसका परिणाम यह है कि शहरी समस्याएं रह-रहकर सिर उठाती रहती हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि कई शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाने के बाद भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर ही रहते हैं। रही-सह कसर नगर निकायों की नाकामी पूरी कर देती है।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय शहर अपने राजस्व से सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत से भी कम प्राप्त करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि शहरों को सही तरह संचालित नहीं किया जा रहा है। प्रायः शहरों के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते समय इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि इससे शहरी जीवन का समुचित तरीके से विकास होगा या नहीं? शहरों में आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र तो बना दिए जाते हैं, लेकिन इस पर कठिनाई से ही ध्यान दिया जाता है कि कामगार कहां रहेंगे या फिर उनका आवागमन कैसे होगा? जब शहर ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, प्रदूषण आदि समस्याओं से घिरते हैं तो उनकी उत्पादकता प्रभावित होने के साथ ही उनमें निवेश की संभावना भी कम होती है। अब जब यह स्पष्ट है कि शहरों में आबादी का दबाव बढ़ते ही जाना है, तब फिर उनके संतुलित एवं टिकाऊ विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए शहरों में झुग्गी-बस्तियां बढ़ती जा रही हैं और आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक बनते जा रहे हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आर्थिक सर्वेक्षण में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए जो योजनाएं शुरू करने की जरूरत जताई गई है, उनकी पूर्ति करने के लिए राज्य सरकारें आगे आएं। वे यह समझें कि अपने शहरों का सही तरह विकास करना उनका ही काम है और यह इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही समृद्धि आएगी।

उचित कदम

दिल्ली में पानी के बिलों पर उपभोक्ता लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया जाना सर्वथा उचित है। उपभोक्ताओं को समय पर पानी का बिल नहीं मिल पा रहा था, बिल में गड़बड़ियां भी थीं, इसलिए बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका था, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार का यह कदम उनके लिए राहत भरा है। माफी योजना के तहत 31 जनवरी तक बकाया बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं का लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रविधान किया था।

> पानी के बिलों पर जुर्माना माफ करने की योजना अच्छी है और उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ उठाना ही चाहिए

अब तक करीब 3.30 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जबकि बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं की संख्या 14.68 लाख है। पानी के बढ़े हुए बिलों की समस्या दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी परेशानी की बात है। बड़ी संख्या में बकाया बिलों का एक बड़ा कारण बिल सही न होना भी है। ऐसे में जुर्माना माफ करने की योजना एक अच्छी योजना है और उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। जो उपभोक्ता जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके बिलों की गलतियां दूर कर उन्हें जल्द बिल उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि इस योजना का लाभ अधिकाधिक लोग उठा सकें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

वहां तक जाने की हममें ताकत रही नहीं इसलिए सोचा, यहीं चादरें फैलाकर थोड़ा बर्फ का अहसास ले लें !!

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने सही किया?

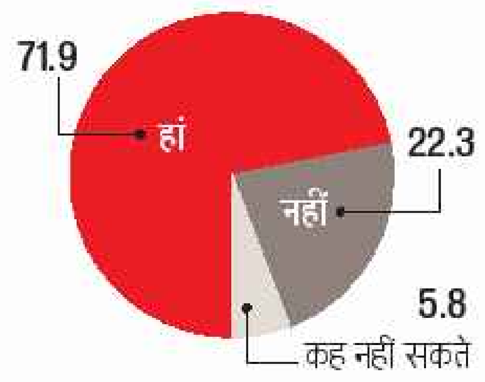

आज का सवाल

क्या बच्चों एवं किशोरों को इंटरनेट मीडिया की लत से बचाने के लिए उपाय किए जाना आवश्यक हो गया है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

नए भाजपा अध्यक्ष के निर्वाचन का संदेश

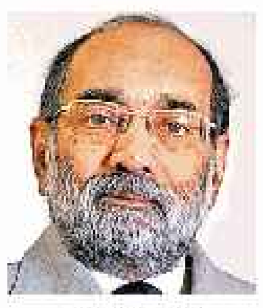

डा. एके वर्मा

नए भाजपा अध्यक्ष का निर्वाचन विपक्षी पार्टियों को भी यह संदेश दे गया कि वे जातीय-अस्मिताओं के मकड़जाल से बाहर निकलें और परिवारवाद छोड़ें

इस 20 जनवरी को भाजपा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब राष्ट्रीय राजनीति में अज्ञात से नितिन नवीन देश की सबसे बड़ी पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष जेपी नड्डा से वे 20 वर्ष छोटे हैं और अब तक भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। यह पार्टी के रणनीतिक सोच को दर्शाता है, जो भविष्य में नेतृत्व की युवा पीढ़ी तैयार करना चाहती है और संक्रमण काल में प्रधानमंत्री मोदी जैसे वरिष्ठ-अनुभवी तथा नितिन जैसे ऊर्जावान युवा की जोड़ी बनाकर सत्ता की स्थिरता से पार्टी में आने वाले ठहराव और आत्मसंतुष्टि को झकझोरना चाहती है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य स्पष्ट है: 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और उससे पहले विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना। उन्हें इस मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का भान है-लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक रुकावटें, न्यायिक अवरोध, लगातार चुनाव जीतने की चुनौतियां तथा तेजी से बदलता वैश्विक परिदृश्य। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने कई संदेश दिए हैं। पहला संदेश अपनी पार्टी के लिए ही है कि भाजपा का संगठन अपनी सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी स्वयं नवीन के नामांकन में प्रस्तावक तथा गृहमंत्री एवं रक्षामंत्री अनुमोदक बने, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने उन्हें पार्टी में अपना 'बास' बताते हुए कहा कि वे उनकी भी 'सीआर' लिखेंगे और जिस प्रकार अपने स्वागत-संबोधन में उन्हें अनेक बार माननीय कहकर संबोधित किया, वह यह संदेश दे गया कि युवा नवीन भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और संगठन के सभी पदाधिकारियों के भी 'बास' हैं। ऐसा केवल वही कर सकता है, जो स्वयं कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बना हो। सरकारें तो लोकतंत्र में आती-जाती रहती हैं, लेकिन संगठन हर झंझावात में खड़ा रहता है और रहना चाहिए। यह पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को सख्त संदेश है कि युवा नवीन को कोई भी हल्के में न ले। पार्टी नेतृत्व में यह पीढ़ीगत परिवर्तन भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को संभवतः साकार कर सकेगा।

दूसरा प्रमुख संदेश पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि अपने कार्य, पार्टी की विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता, दलीय कार्यसंस्कृति के प्रति समर्पण एवं जनता से जुड़ाव द्वारा वे संगठन में सर्वोच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका किसी जाति विशेष का होना जरूरी नहीं, किसी राजनीतिक गाडफादर की आवश्यकता नहीं-केवल 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' अर्थात कर्म प्रधानता के मूलमंत्र का ही ज्ञान होना चाहिए। दुर्भाग्य से देश में अधिकतर पार्टियां परिवार के इर्दगिर्द घूमती हैं, अतः उनके कार्यकर्ता जनता से जुड़ने के बजाय उस परिवार और उसके मुखिया से जुड़ने को वरीयता देते हैं। उन्हें पार्टी विचारधारा के प्रति समर्पण से ज्यादा जरूरी उस परिवार के प्रति समर्पण लगता है। ऐसा न करने वाले कार्यकर्ता धीरे-धीरे उपेक्षित होकर दूसरी पार्टियों की ओर चल देते हैं। नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है, जो उन्हें सक्रियता, ऊर्जा, आशा, उत्साह और सकारात्मक सोच से ओतप्रोत कर विकसित भारत के 'संकल्प को सिद्धि' तक ले जाने में महत्वपूर्ण कारक बनाएगी।

अवधेश राजपूत

नवीन को अध्यक्ष बना भाजपा ने तीसरा संदेश राज्य की भाजपा सरकारों को दिया है। करीब 16 राज्यों में भाजपा/राजग सरकारें है। जातिवाद, क्षेत्रीयता और वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा के चलते पार्टियों की राज्य इकाइयों में प्रायः दलीय गुटबाजी होती है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को संतुलित और अनुशासित करना होता है, लेकिन उससे भी जटिल मुख्यमंत्री और राज्य संगठन के शीर्ष नेतृत्व के बीच का संघर्ष होता है। मुख्यमंत्री अपने को 'बास' मानता है और प्रदेश अध्यक्ष एक आभूषणीय पद होकर रह जाता है, जो संगठन और सरकार में टकराव को जन्म देता है, जिससे चुनावों में पार्टी की विजय की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। प्रधानमंत्री ने नवीन को अपने 'बास' और माननीय के रूप में संबोधित कर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच कैसे समीकरण होने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को इशारों में सलाह भी दी कि प्रदेश सरकार बनने के पीछे पार्टी संगठन की ताकत और मेहनत होती है। अतः पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को नीति-निर्णयन में सहभागिता और वांछित श्रेय मिलना चाहिए। प्रायः भाजपा के मुख्यमंत्री प्रशासकीय अमले को ही नीति-निर्माण और निर्णयन का एकमात्र अभिकरण मानते हैं, जबकि उन्हें लागू कराने में वे संगठन का सक्रिय सहयोग चाहते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है और संगठन कार्यकर्ता अपनी ही सरकार में हाशिये पर चले जाते हैं। जो समीकरण प्रधानमंत्री और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मोदी ने उनके कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर प्रदर्शित किया, उसी की अपेक्षा पार्टी राज्य स्तर पर भी करेगी। यही सरकार और संगठन दोनों के लिए श्रेयस्कर होगा।

नए भाजपा अध्यक्ष का निर्वाचन विपक्षी पार्टियों को भी यह संदेश दे गया कि वे जातीय-अस्मिताओं के मकड़जाल से बाहर निकलें, परिवारवाद छोड़ें, समावेशी दृष्टिकोण अपनाएं, दलीय विचारधारा से प्रतिबद्धता, कार्यकर्ताओं की कर्मठता एवं योग्यता को सत्ता-संरचना में समुचित स्थान देकर अपनी पार्टी में प्राण फूकें। आज जब दलीय नेतृत्व का चयन करने में परिवार या जाति को तरजीह दी जाती है, तब भाजपा ने देश की 140 करोड़ आबादी में मात्र 0.7 प्रतिशत वाले कायस्थ समाज से पार्टी अध्यक्ष का चयन कर साफ संदेश दिया है कि जातिवादी राजनीति का युग खत्म होने को है और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु अब योग्यता आधारित वर्ग-राजनीति की बारी है, लेकिन पता नहीं इन संकेतों को विपक्षी दल पकड़ पाएंगे भी या नहीं?

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

भविष्य के भारत के लिए सही राह

प्रो. गौरव वल्लभ

आने वाला दशक बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि पूर्व की योजनाओं के कुशल निष्पादन से परिभाषित होगा

पिछले एक दशक में भारत के आर्थिक कायाकल्प को सामान्य तौर पर जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों से ही रेखांकित किया जाता है, लेकिन ऐसा करना इस पूरी कहानी को समझने का अधूरा प्रयास ही कहा जाएगा। भारत में आकार ले रहा परिवर्तन विकास की गति से अधिक उसकी प्रकृति एवं स्वरूप में आया बदलाव अधिक महत्वपूर्ण है। देश ने एक नाजुक और असंतुलित अर्थव्यवस्था से एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए हैं, जो पूंजीगत व्यय, डिजिटल आधारभूत ढांचे और संस्थागत क्षमताओं पर आधारित है। हाल के वर्षों में राज्य क्षमता विस्तार, सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण और उनकी नागरिकों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय निवेश देखा गया है। अब चुनौती इन बुनियादी परिवर्तनों को दीर्घकालिक उत्पादकता और समावेशी लाभों में बदलने की है। निःसंदेह श्रम बाजार का औपचारीकरण बढ़ा है, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कौशल के स्तर पर अभी भी अवरोध कायम हैं। वेतन आंकड़ों के हालिया रुझान को देखें तो हाल के वर्षों में औसतन बीस लाख नए कर्मियों का मासिक जुड़ाव सामने आया है। यह दर्शाता है कि डिजिटलीकरण और कर सुधारों ने व्यवसायों को औपचारिक स्वरूप अपनाने के लिए प्रेरित किया है। बेरोजगारी दर का पांच प्रतिशत के आसपास स्थिर रहना भी मजबूती और स्थायित्व का संकेत है। फिर भी यह परिवर्तन पहला चरण ही है, क्योंकि केवल औपचारिक रोजगार पर्याप्त नहीं हैं।

स्थितियां तब तक नहीं सुधरेंगी, जब तक रोजगार की उत्पादकता और गुणवत्ता समान रूप से नहीं बढ़ती। महिला श्रम भागीदारी का लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंचना हौसला जरूर बढ़ाता है, पर इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण, कम-भुगतान या अवैतनिक कार्यों में केंद्रित है। इसलिए अगला कदम रोजगार की गुणवत्ता और कौशल-आधारित प्रगति पर होना चाहिए, जिसके लिए कौशल प्रमाणन, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स नीति एक बाजी पलटने वाली सफलता के रूप में उभरी है। मात्र एक दशक में भारत मोबाइल फोन आयातक से घरेलू उत्पादन केंद्र में रूप में उभरा है। 2015 में 11.1 लाख करोड़ के रिकार्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और नीतिगत सहायता ने इलेक्ट्रानिक्स निर्यात को पिछले ग्यारह वर्षों में 11 गुना बढ़ाकर 4.15 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। इससे यह धारणा ध्वस्त हुई कि भारत औद्योगिक नीति को लागू नहीं कर सकता। हालांकि यह सफलता एक सीमा भी उजागर करती है। अभी भी जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत के आसपास है और केवल इलेक्ट्रानिक्स के सहारे ही व्यापक रोजगार सृजन संभव नहीं। टेक्सटाइल, फुटवियर एवं खिलौना जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में इस प्रकार की सफलता अभी प्राप्त होती नहीं दिख रही। ऐसे में, राज्य प्रोत्साहनों का उचित संयोजन, एमएसएमई अनुपालन सरलीकरण तथा लाजिस्टिक्स एवं बंदरगाह दक्षता में सुधार इस मोर्चे पर सफलता की ओर उन्मुख कर सकते हैं।

नीतिगत प्रोत्साहन से बढ़ता रोजगार सृजन ● फाइल

इसमें संदेह नहीं कि कारोबारी सुगमता में सुधार ने भी निवेश को गति प्रदान की है। पुराने कानूनों को हटाने, डिजिटल स्वीकृतियां और फेसलेस अनुपालन ने संचालन एवं विस्तार को अधिक सुगम बनाया है। जीएसटी के तहत 1.4 करोड़ व्यवसायों का जुड़ना प्रशासनिक सरलीकरण की गहराई को दर्शाता है। फिर भी छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए जमीनी अनुभव मिले-जुले हैं। वहां अनुपालन तो डिजिटल हुआ है, पर अपेक्षित रूप से सरलता संभव नहीं हो पाई है। केंद्र-राज्यों के बीच नियामकीय परतें, नियमों में परिवर्तन तथा भूमि एवं श्रम औपचारिकताएं विस्तार की लागत बढ़ाती हैं। इसलिए सुधार के अगले चरण का केंद्र पूर्वानुमानिता, नियमों की स्थिरता और विवाद निपटान की तीव्रता होनी चाहिए। नियम कम होने चाहिए और जो हों, उनमें स्थिरता का भाव हो और उनका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए।

भारत ने पिछले दशक में गरीबी घटाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। करीब 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान गरीबी सूचकांक 11.28 प्रतिशत तक गिरा है। यह आम नागरिकों की बेहतर जिंदगी का प्रमाण है। इसके बावजूद खपत का स्तर एकसमान नहीं है। कारों और ब्रांडेड सामान की खपत तेजी से बढ़ी है, जबकि सस्ती दैनिक जरूरतों की खपत में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत धीमी रही। इसी अंतर को अक्सर बढ़ती असमानता कहा जाता है, लेकिन विकास में यह सही क्रम भी है। इस लिहाज से अब अगली चुनौती आय में स्थिरता नहीं, बल्कि आय की गतिशीलता से संबंधित है। कल्याणकारी योजनाओं को कौशल प्रशिक्षण, छोटे ऋण, स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और शहरों के रोजगार कारिडोर से जोड़कर लांचपैड बनाया जा सकता है।

बीते एक दशक में भारत ने डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे, राजकोषीय क्षमता और संस्थागत निर्माण को मजबूती प्रदान की है। इसका अर्थ है कि सुधारों की गति और दायरा बढ़ा है। अब आने वाला दशक बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि पूर्व की योजनाओं के कुशल निष्पादन से परिभाषित होगा। यह निष्पादन केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्यों, नगर निकायों, निजी उद्यमों और संस्थानों की सामूहिक क्षमता पर निर्भर करेगा।

(लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य एवं वित्त के प्राध्यापक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आशा और लक्ष्य

मनुष्य जीवन में आशा और लक्ष्य दो प्रमुख आधार होते हैं। आशा वह आंतरिक शक्ति है, जो कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आगे बढ़ने का साहस देती है। जबकि लक्ष्य वह दिशा है, जो इस शक्ति को भटकने से बचाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब आशा तो प्रबल होती है, परंतु उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। अर्थात लक्ष्य तो निर्धारित होता है, किंतु उसमें जीवन को समझने की क्षमता नहीं होती। आशा यदि केवल इच्छाओं तक सीमित हो जाए तो वह जल्द ही निराशा में बदल जाती है। यथार्थ की कसौटी पर वही आशा उचित है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर निरंतर प्रेरित करे। ऐसी आशा व्यक्ति को आलस्य, भय और असमंजस से बाहर निकालती है। वह हर असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीख मानने की दृष्टि देती है। यही दृष्टि मनुष्य को निरंतर प्रयासों की दिशा में प्रयत्नशील बनाती है।

लक्ष्य चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य भी पद, धन या प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं होना चाहिए। सार्थक लक्ष्य वही है, जो व्यक्ति को जीवन मूल्यों से जोड़ता है। उसे अनुशासन एवं दायित्व का बोध कराता है। ऐसा लक्ष्य ही व्यक्ति को सफलता के साथ बेहतर मनुष्य भी बनाता है। लक्ष्य यदि जीवन जीने की कला न सिखाए, तो उसकी प्राप्ति भी रिक्तता छोड़ जाती है।

जीवन में आशा और लक्ष्य का संतुलन आवश्यक है। स्पष्ट लक्ष्य के बिना आशा दिशाहीन होती है और तार्किक आशा के बिना लक्ष्य बोझ बन जाता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप लक्ष्य तय करता है और उन्हें पाने की आशा को कर्म से जोड़ता है, तभी उसका जीवन सार्थकता की ओर बढ़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी आशाएं रखें, जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाएं और ऐसे लक्ष्य चुनें, जो हमें केवल आगे बढ़ना ही नहीं, बल्कि सही ढंग से जीवन जीना भी सिखाएं। यही संतुलन जीवन को स्थायित्व और सार्थकता प्रदान करता है।

अमन सिंह गौर

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सुधारनी होगी श्रम उत्पादकता

'श्रम उत्पादकता में सुधार का समय' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जीएन वाजपेयी ने श्रम उत्पादकता के महत्व को रेखांकित किया है। किसी भी राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में श्रमिकों की बड़ी भूमिका होती है। भारत की आर्थिक प्रगति का अगला बड़ा आधार श्रम उत्पादकता में ठोस सुधार है। श्रम उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल, तकनीक, कार्य-परिस्थितियों, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संरचना का संतुलित विकास होना चाहिए। भारत में लंबे कार्य घंटे, असंगठित क्षेत्र की बहुलता, कम वेतन और सीमित सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों की दक्षता को प्रभावित करती है। उद्योगों में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का अभाव और प्रशिक्षण की कमी भी एक बड़ी बाधा है। सरकार द्वारा श्रम संहिताओं का एकीकरण, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और ईज आफ डूइंग बिजनेस पर जोर सकारात्मक कदम हैं। यदि इन सुधारों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, कौशल विकास को उद्योग-केंद्रित बनाया जाए, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों को सख्ती से अपनाया जाए और महिला श्रम भागीदारी बढ़ाई जाए तो उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। जब श्रमिक सुरक्षित होंगे, उद्योग प्रगतिशील होंगे और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तभी भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती से उभरेगा। श्रमिक हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं। श्रमिकों का ख्याल रखना सरकार और समाज का कर्तव्य है। उनके प्रयासों से ही विकसित भारत की आधारशिला तैयार होगी।

हिमांशु शेखर, केसपा (गयाजी)

मजबूत भारत सतर्क भविष्य

लोकसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 देश की अर्थव्यवस्था का ऐसा दर्पण है, जिसमें मजबूती, आत्मविश्वास और सतर्कता तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश यह दस्तावेज केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भारत की आर्थिक दिशा का संकेतक भी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार यह सर्वे बताता है कि वैश्विक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी जड़ों में मजबूत बनी हुई है और आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत से ऊपर रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में यह 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रह सकती है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता के बावजूद यह दर भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखती है। यह संकेत देता है कि घरेलू मांग मजबूत है, निवेश का माहौल सुधर रहा है और नीतिगत सुधारों का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। सर्वेक्षण में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है। बीते कुछ वर्षों में किए गए संरचनात्मक सुधारों ने विकास क्षमता को सात प्रतिशत तक पहुंचा दिया है।

कांतिलाल मांडोत नई दिल्ली

कुल्हाड़ी पर सिर मारना

अक्सर लोग नादानी में पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकतों से कुल्हाड़ी पर अपना सिर ही मार दिया है। उन्होंने अनेक देशों पर भारी टैरिफ लगाया, यह ध्यान दिए बिना कि अंततः उसका बोझ उन्हीं के देश के ग्राहकों को झेलना पड़ेगा। टैरिफ के कारण आपूर्ति में निश्चित रूप से कमी आई। उसकी पूर्ति के लिए वैकल्पिक विक्रेताओं की खोज हुई, जो स्वाभाविक रूप से महंगे साबित हुए। गुणवत्ता के लिए भी समझौता करना पड़ा। इन्हीं कारणों से अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में अत्यधिक कमी आई। उनकी लोकप्रियता 19 प्रतिशत तक गिर गई। वहां किसी की लोकप्रियता का पैमाना उसको पसंद करने वालों की संख्या से नापसंद करने वालों की संख्या से घटाकर निकाला जाता है। नवीनतम सर्वेक्षण में उनको पसंद करने वालों 40.5 प्रतिशत थे और नापसंद करने वाले 59.5 प्रतिशत । इस तरह नापसंद करने वाले 19 प्रतिशत अधिक थे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में मात्र छह लाख लोगों को नौकरी मिली, जबकि पिछले वर्ष 22.68 लाख लोगों को नौकरी मिली थी। वे नोबेल शांति पुरस्कार पाने के आकांक्षी थे, पर वेनेजुएला पर आक्रमण एवं ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी से उनकी छवि आक्रांता की बन रही है। अपनी हरकतों से उन्होंने मित्र यूरोपीय देशों को असहज कर दिया। वे उनके पाले से निकल गए हैं। कनाडा एवं ब्राजील भी शीघ्र ही भारत से व्यापार समझौता करना चाहेंगे।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

पोस्ट

अगर टी-20 विश्व कप की अंतिम एकादश में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया जाता तो इसके लिए वे खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। हालिया प्रदर्शन के आधार पर अगले मैच में विकेटकीपर की जिम्मेदारी इशान किशन को मिलनी चाहिए।

विक्रांत गुप्ता@vikrantgupta73

नए यूजीसी नियमों से छात्रों के बीच वैमनस्य बढ़ने की भरी-पूरी आशंका थी । इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाकर एकदम सही किया। नौकरशाही के निर्णयों में संवेदनशीलता होनी चाहिए, ताकि एकजुट और समरस भारत को मजबूती मिल सके।

अशोक खेमका@AshokKhemka_IAS

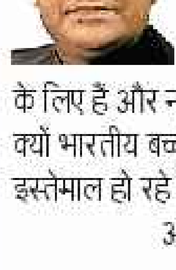

आस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस ने भी बच्चों के इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर रोक के कानून को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि 'हमारे बच्चों के दिमाग न तो अमेरिकी प्लेटफार्म्स के लिए हैं और न ही चीनी नेटवर्क्स के लिए।' पता नहीं क्यों भारतीय बच्चों के दिमाग अब भी चरागाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। यहां ऐसी रोक कब लगेगी?

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

हिट होता संगीत तो सोते चद्दर तान,
कमी कहीं रह जाय तो रोते हैं रहमान।
रोते हैं रहमान गिरें आंसू 'इस्लामी'
ले मजहब की आड़ छिपाते वे नाकामी।
हर बीटिंग रिट्वीट तुझे सुनते हैं श्रोता,
यदि न चाहता देश तो तू कैसे हिट होता?

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 197

मंथन हुआ शुरू, यूजीसी के नए समता कानूनों में दिख सकती है एकता और समरसता की झलक

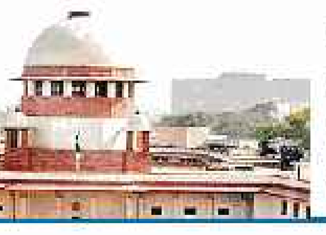

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर शिक्षा मंत्रालय व यूजीसी में नियम के नए स्वरूप को लेकर दिनभर चली बैठकें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विवादित समता नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और इसकी खामियों को दूर करने के स्पष्ट निर्देश के बाद शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी में शुक्रवार को दिनभर बैठकों का दौर चला। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नियमों से जुड़ी खामियों को दूर करने पर विस्तार से मंथन हुआ। जो संकेत मिले हैं, उनसे साफ है कि नए समता नियमों में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को बढ़ावा देने वाले बिंदुओं से परहेज करते हुए एकता और समरसता बढ़ाने वाले बिंदुओं को प्रमुखता से शामिल किया जा सकता है।

अभी हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन माना जा रहा है कि मूल प्रारूप के अनुसार एससी-एसटी के साथ-साथ अब सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के प्रति भेदभाव की भी बात होगी। साथ ही गलत शिकायत पर कार्रवाई का प्रविधान भी वापस लाया जा सकता है। अब यह तय है कि नए नियमों में ऐसी कोई चीज नहीं रखी जाएगी, जिससे एक ही संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के बीच भेदभाव दिखे। साथ ही यदि भेदभाव का कोई भी मामला आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निश्चित की गई है। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी में शीर्ष स्तर पर हुई बैठकों में समता नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और टिप्पणियों को सूचीबद्ध किया गया। साथ ही अब इन सभी बिंदुओं पर विशेषज्ञों और कानूनविदों के साथ चर्चा की जाएगी। जानकारों की मानें तो यदि इसे लेकर समाज के अलग-अलग वर्गों की ओर से किया जा रहा आंदोलन नहीं थमा तो इसे लेकर एक कमेटी गठित करके कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता है।

थरूर बोले- मेरा रुख भाजपा समर्थक नहीं

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि उनके कुछ मुद्दों पर रुख को मीडिया द्वारा भाजपा समर्थक के रूप में देखा गया हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे केवल सरकार या भारत समर्थक के रूप में देखा है। थरूर ने कहा कि पहले भी स्पष्ट किया है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय मामलों पर वे राजनीति के बारे में बात करना पसंद नहीं करते और इसकी जगह देश के बारे में बोलना पसंद करते हैं।

थरूर ने स्वीकार किया कि पार्टी की लाइन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कहा, मैं हमेशा संसद में पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं व इसलिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, थरूर ने कहा, मैं कह सकता हूं कि मैं कांग्रेस में रहूंगा।

बच्ची के सिर में धंस रही थी गोली, जटिल सर्जरी से बची जान

- न्यूरोसर्जरी विभाग के डाक्टरों ने दुर्लभ सर्जरी कर तीन साल की बच्ची को दिया जीवनदान
- 20 लाख की सर्जरी केजीएमयू में हुई मुफ्त, पुलिस को नहीं मिला फायरिंग का सुराग

जागरण संवाददाता, लखनऊ: किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के डाक्टरों ने जटिल सर्जरी कर तीन साल की बच्ची को नई जिंदगी दी है। इंदिरानगर के बस्तौली गांव में छत पर खेलते समय पिस्टल की गोली उसके सिर के बाएं तरफ धंस गई थी। टीन से टकराने के बाद लगी गोली मस्तिष्क के पास होने से सर्जरी बेहद मुश्किल थी, लेकिन न्यूरो सर्जरी, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिक विभाग के डाक्टरों ने असंभव को संभव कर दिखाया। सर्जरी के बाद पांच दिन वेंटिलेटर और 25 दिन आइसीयू में संघर्ष के बाद अब बच्ची को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हालांकि, पुलिस के लिए, भी अब तक यह रहस्य ही है कि गोली चलाई किसने? 16 दिसंबर, 2025 की शाम लगभग चार बजे गोली की आवाज सुनकर स्वजन छत पर पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ मिली। अस्पताल में भर्ती कर सीटी स्कैन कराया तो गोली मस्तिष्क के बाएं हिस्से में करीब तीन सेंटीमीटर अंदर धंसी थी। प्राथमिक इलाज के बाद डाक्टरों ने केजीएमयू रेफर कर दिया। केजीएमयू के न्यूरोसर्जरी विभाग के डा. अंकुर बजाज के मुताबिक दोबारा सीटी स्कैन कराया तो रिपोर्ट में गोली पुरानी जगह से दो सेंटीमीटर और खिसक कर पांच सेंटीमीटर मस्तिष्क के गहरे बेसल तक पहुंच गई थी। चोट लगने के 25 घंटे बाद जब एंजियोग्राफी हुई तो रिपोर्ट में गोली सिर में सात सेंटीमीटर अंदर वहां पाई गई, जहां कई पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। गोली के लगातार स्थान बदलने से पूरी टीम आश्चर्यचकित थी, क्योंकि ऐसी सर्जरी में सफलता दर 10 प्रतिशत से भी कम होती है।

डा. बजाज के अनुसार, सर्जरी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती गोली का लगातार स्थान बदलना था। ऐसे में सर्जरी के लिए इंट्राआपरेटिव फ्लोरोस्कोपी की मदद ली गई, जिससे ट्रैक करना आसान हुआ। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के दौरान रक्त वाहिकाओं की क्षति को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आधुनिक एवं सुरक्षित विधि है, जो सर्जन को नसों पर नजर रखने में मदद करती है। साढ़े तीन घंटे की जटिल सर्जरी कामयाब रही। तीन साल की बच्ची को एनेस्थीसिया देना भी विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण था।

केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि यह सर्जरी सरकारी योजना के तहत की गई। यदि कारपोरेट अस्पताल में सर्जरी होती तो करीब 20 लाख रुपये खर्च होते। सर्जरी करने वाली टीम में डा. अनूप सिंह, डा. अंकन बसु और डा. श्रद्धा, न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. बीके. ओझा का अहम योगदान रहा। इधर, सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गाजीपुर अनिंद्य विक्रम सिंह ने बताया कि घर के चारों तरफ जांच की गई। लाइसेंसी असलहा तो मिला पर बच्ची को 0.45 बोर की गोली लगी थी, वो हथियार वहां नहीं मिला।

शराब, जुआ व लड़ाई है कांग्रेस शासित राज्यों का माडल: भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कर्नाटक वाइन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा राज्य की कांग्रेस पर लगाए गए छह हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप ने भाजपा को कांग्रेस की घेरेबंदी का एक और मौका दे दिया है। इसके सहित कर्नाटक के ही विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी पर लगे आनलाइन सट्टेबाजी और तमाम राज्यों में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का दावा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डा. सुधांशु त्रिवेदी ने कटाक्ष किया कि शराब, जुआ और लड़ाई कांग्रेस शासित राज्यों का माडल है। वहीं, बीएसएफ को बंगाल में फेंसिंग के लिए भूमि आवंटन के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इस फैसले ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के चेहरे पर तुष्टिकरण साबित हो गया है।

सुधांशु त्रिवेदी

डा. सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी और कुछ राज्यों में भाजपा की सरकारें थीं। उस दौर में गुजरात माडल की व्यापक चर्चा होती थी। लेकिन आज कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में है, वहां वह किस प्रकार का माडल प्रस्तुत कर रही है, उसकी बानगी जनता के सामने रखना आवश्यक है। बता दें कि वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने कांग्रेस सरकार पर छह हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले का आरोप लगाया है।

गजनवी को भारतीय बताने पर घिरे पूर्व उपराष्ट्रपति

हामिद अंसारी ने महमूद गजनवी को 'भारतीय लुटेरा' बताया

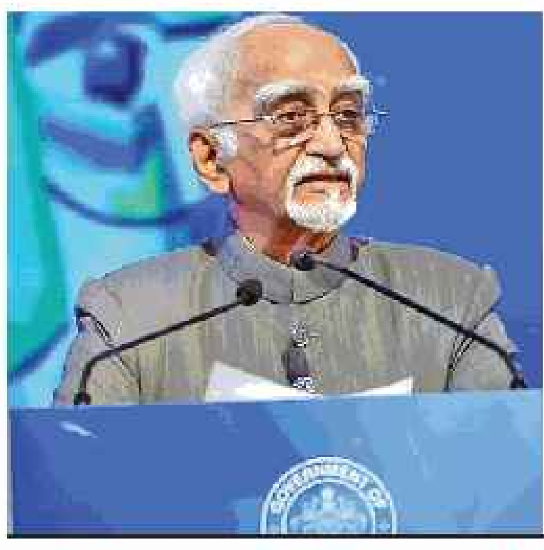

- भाजपा ने बयान की निंदा की और राहुल गांधी से पूछा क्या वे इससे सहमत हैं
- सुधांशु बोले, विदेशी हमलावरों के प्रति लगाव उनकी 'बीमार मानसिकता' है

हामिद अंसारी • फाइल/आइएएनएस

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी महमूद गजनवी को ''भारतीय लुटेरा'' बताकर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसका पूरा ईकोसिस्टम विदेशी हमलावरों को महिमामंडित करता है और हिंदू विरोधी आततायियों का गुणगान करता है। पार्टी ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिंदू मंदिरों को तोड़ने एवं हजारों लोगों की हत्या करने वाले क्रूर हमलावर के बारे में अंसारी के विचारों से सहमत हैं।

हामिद अंसारी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि इतिहास की पुस्तकों में महमूद गजनवी समेत जिन लोगों को विदेशी हमलावर और लुटेरों के रूप में दर्शाया गया है, वे असल में ''भारतीय लुटेरे'' थे। वे बाहर से नहीं आए थे। राजनीतिक रूप से यह कहना आसान है कि उन्होंने यह और वो नष्ट कर दिया, लेकिन वे सभी भारतीय थे।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशी हमलावरों और लुटेरों के प्रति अंसारी का स्नेह उनकी ''बीमार मानसिकता'' को दर्शाता है। यह पूरी समस्या तीन एम- मुगल, मैकाले और मार्क्स का परिणाम है। दुख की बात है कि उपराष्ट्रपति रह चुका व्यक्ति ऐसे बयान देता है, जबकि सच्चाई यह है कि जैसे सभी ब्रिटिश वायसराय किंग या क्वीन की ओर से शासन करते थे, वैसे ही सभी मुगल सम्राट बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधियों के रूप में शासन करते थे। लुटेरों से खुद को जोड़कर, समाज का एक निश्चित वर्ग पूरे भारत को लुटेरों से जोड़ने लगा है। ऐसी मानसिकता से छुटकारा पाने की जरूरत है।

'एक्स' पर अंसारी की टिप्पणियों का फुटेज साझा करते हुए पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, 'शरजील इमाम और उमर खालिद को युवा कहने के बाद, अब कांग्रेस ईकोसिस्टम व हामिद अंसारी गजनवी की तारीफ कर रहे हैं जिसने सोमनाथ मंदिर को नष्ट और अपवित्र किया था। वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करते हैं... वे औरंगजेब और उन लोगों के अपराधों पर पर्दा डालते हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए। भाजपा नेता सीआर केसवन ने कहा कि आठवीं सदी की शुरुआत में इस्लामी आक्रमणों से लेकर मुगल शासन तक पवित्र हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। क्या नेहरू की कांग्रेस, जिसने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कड़ा विरोध किया था, इन बयानों से सहमत है। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को आधुनिक इंडियन मुस्लिम लीग बताया।

पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं हामिद अंसारी

- आक्रामक राष्ट्रवाद विचारधारा के लिहाज से 'जहर' जैसा है जो नि:संकोच लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण और अधिकारों को क्षीण करता है।
- दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि 1947 में हुए विभाजन के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार नहीं था, भारत भी इसमें जिम्मेदार था।
- उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के आखिरी दिन कहा कि देश के मुसलमानों में घबराहट का भाव है और वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
- केरल में 2017 में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के एक कार्यक्रम में यह जानते हुए भी शिरकत की कि इस संगठन पर आतंकियों के समर्थन का आरोप है।
- बालाकोट एयर स्ट्राइक के सुबूत मांगने का समर्थन किया। कहा कि लोगों को एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने का पूरा हक है।

इटावा में मोहम्मद गोरी के सेनापति की मजार पर विवाद, जांच के आदेश

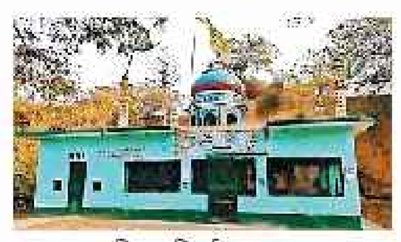
मजार पर किया निर्माण • जागरण

जागरण संवाददाता, इटावा : उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में मोहम्मद गोरी के सेनापति शमशुद्दीन की मजार की पांच बीघा जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद हो गया है। आइजीआरएस पोर्टल पर हिंदू जागरण मंच की शिकायत के बाद जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल के आदेश पर वन व राजस्व विभाग की टीमों ने ध्वस्तीकरण का नोटिस मजार संचालक फजले इलाही को भेजकर 22 जनवरी तक साक्ष्य मांगे थे, जो नहीं मिले हैं। इस मजार को स्थानीय लोग बीहड़ वाले सैयद बाबा के नाम से जानते हैं। यहां दो फरवरी से उर्स का आयोजन होना था, जिसके लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। आवाजाही न हो, इसलिए वन विभाग ने गड्ढे खोदकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। इतिहास के जानकारों के अनुसार, मोहम्मद गोरी ने वर्ष 1194 में राजा सुमेर शाह के साथ यहां युद्ध लड़ा और जीता था। इसके बाद सेनापति शमशुद्दीन की मौत होने पर उसकी मजार बनाई गई थी। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विकास नायक ने बताया कि मजार से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पांच फरवरी को उनके न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि तीन जनवरी को शिकायत के बाद सीएम कार्यालय से जांच के आदेश दिए गए थे। बढ़पुरा रेंज अफसर अशोक शर्मा की संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर उसे ध्वस्त करने का नोटिस वन विभाग ने दिया था।

कांग्रेस ने असम में घुसपैठ को बढ़ावा दिया: अमित शाह

असम के धेमाजी में शुक्रवार को मिसिंग युवा महोत्सव को संबोधित करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह • एएनआइ

- कहा, सरकार इस स्थिति को पलटने के लिए काम कर रही है
- असम में घुसपैठ रोकना चाहते हैं, तो फिर से भाजपा सरकार चुनें

धेमाजी, प्रेट्र : गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान असम में घुसपैठ को बढ़ावा मिला और यहां की जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इस स्थिति को पलटने के लिए काम कर रही है।

आल मिसिंग स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा आयोजित 10वें मिसिंग युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की, ताकि राज्य को घुसपैठ से मुक्त कराया जा सके। वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस शासन के दौरान असम की जनसंख्या संरचना पूरी तरह बदल गई। घुसपैठियों की संख्या शून्य से बढ़कर 64 लाख हो गई और सात जिलों में घुसपैठिए बहुसंख्यक हो गए। मोदी सरकार इस स्थिति को पलटने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। यदि आप असम में घुसपैठ रोकना चाहते हैं, तो भाजपा को तीसरी बार चुनें और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हाथों को मजबूत करें। असम में भाजपा की दो राज्य सरकारों ने घुसपैठियों के अतिक्रमण से 1.26 लाख एकड़ जमीन मुक्त कराई है।

गृह मंत्री ने ऊपरी असम में घुसपैठियों को बसने से रोकने में मिसिंग समुदाय की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। कहा कि घुसपैठ रोकना मिसिंग समुदाय की जिम्मेदारी है। इसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने डिब्रूगढ़ में दूसरे विधानसभा परिसर सहित 1,715 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा आयोजित 'एट होम' में भेंट की गई 'गमोसा' पहनने से इन्कार करके पूर्वोत्तर का अपमान किया है।

कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने खदेड़ा

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर: रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केरन सेक्टर (कुपवाड़ा) में शुक्रवार तड़के 15 पाकिस्तानी ड्रोन ने एलओसी पर भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जवानों ने तुरंत गोलीबारी कर उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस घटना के बाद एलओसी पर सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। रक्षा मंत्रालय ने इस घटना पर कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया है। गुलाम जम्मू-कश्मीर से घुसपैठ के लिए आतंकी प्रायः केरन सेक्टर का इस्तेमाल करते हैं।

जानकारी के अनुसार, केरन सेक्टर के जोधा मकान बीरंडोरी इलाके में एलओसी पर तैनात सेना की छह राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने तड़के गुलाम जम्मू-कश्मीर की तरफ से पाकिस्तानी सेना के ड्रोन के एक बेड़े को घुसपैठ करते देखा। बताया जाता है कि कुल 15 ड्रोन थे और ये सभी काफी नीचे उड़ रहे थे। ये ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे ही थे कि जवानों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों की कार्रवाई से ड्रोन आगे नहीं बढ़े और लौट गए। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने ये ड्रोन भारतीय इलाके की टोह लेने भेजे होंगे, ताकि आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। केरन सेक्टर में इन दिनों काफी हिमपात हुआ है। यह क्षेत्र घुसपैठ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रहा है।

इस माह हुई ड्रोन की साजिशें

- **दो जनवरी:** पुंछ में एलओसी पार से ड्रोन के मध्यम से गिराई गई आइईडी व अन्य विस्फोटक को सेना ने निष्क्रिय किया।
- **10 जनवरी:** सांबा में ड्रोन से हथियार गिराए, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद कर लिया।
- **11 जनवरी:** राजौरी के कलसियां व त्रियाठ, पुंछ के मनकोट और सांबा व कठुआ में आए ड्रोन खदेड़े गए।
- **13 जनवरी:** राजौरी के केरी सेक्टर में आए कई पाकिस्तानी ड्रोन को सुरक्षाबल ने फिर खदेड़ दिया।
- **17 जनवरी:** सांबा जिला और राजौरी जिला में भी सीमांत क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए।

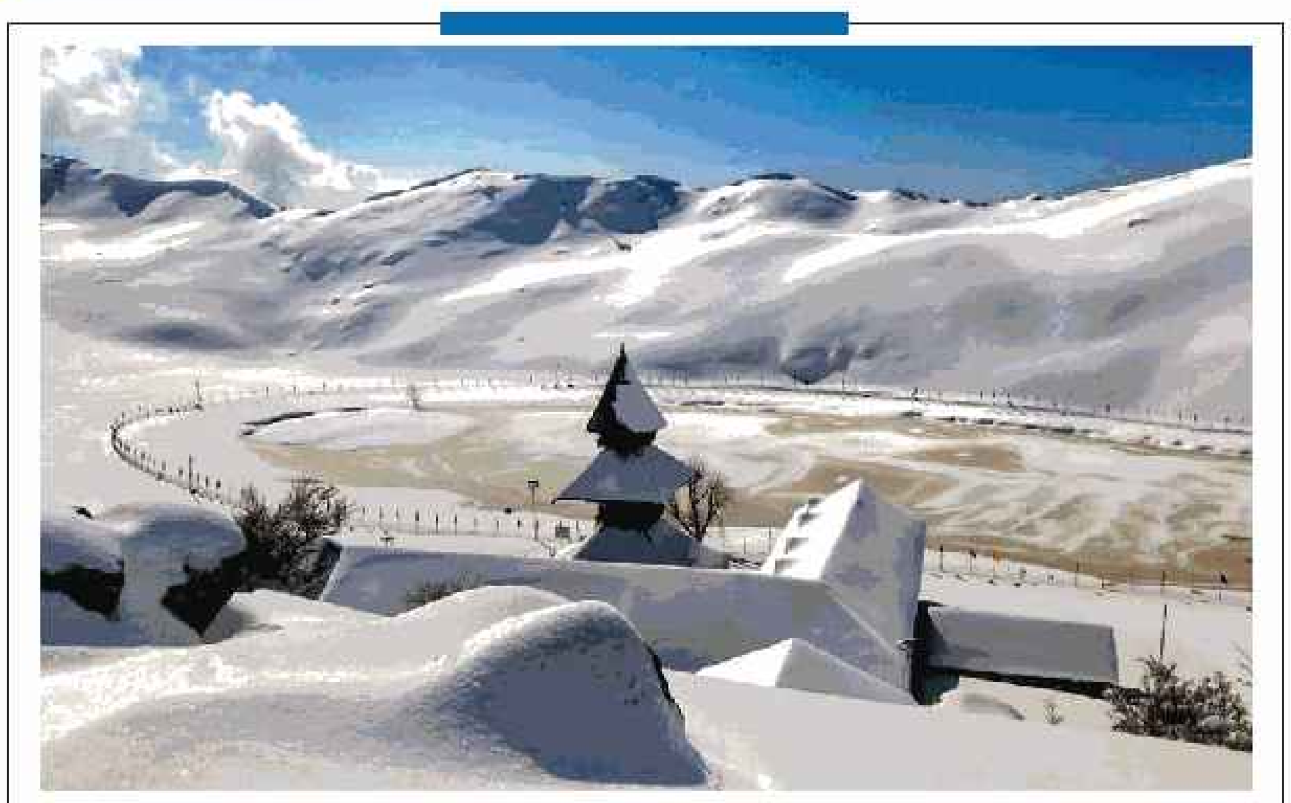

विदेश नहीं, देश के खूबसूरत पहाड़...

पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बाद देश में भी विदेशों जैसा मनोरम प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी के बाद पाराशर झील भी आसपास की बर्फ की सफेद चादर में सिमटी दिखी • प्रेट्र

'कुरान पाठ के साथ मुर्शिदाबाद में शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण'

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में 11 फरवरी को कुरान पाठ के साथ बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक और नवगठित जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक कबीर ने पिछले साल छह दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, जिसमें पूरे राज्यभर से मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। कबीर ने शुक्रवार शाम को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे से निर्माण कार्य शुरू होने से पहले वहां पांच हजार लोगों को लेकर डेढ़ घंटे तक कुरान पाठ किया जाएगा।

मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा टैक्सी किराया, 400 मीटर सफर के वसूले 18 हजार रुपये

- अतिथि देवो भवः की धरती पर विदेशी पर्यटक से हुई ठगी
- ड्राइवर ने पर्यटक को गलियों में घुमाया और डालर में लूटा

मुंबई, प्रेट्र : भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता और अतिथि देवो भवः की परंपरा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। विदेशी पर्यटकों के स्वागत-सत्कार से लेकर देश की सकारात्मक छवि गढ़ने तक सरकार लगातार इंक्रेडिबल इंडिया और ग्लोबल टूरिज्म प्रमोशन जैसे अभियानों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। लेकिन इसी बीच मायानगरी मुंबई से सामने आई एक शर्मनाक घटना ने इन तमाम प्रयासों पर सवालिया निशान लगा दिया है, जहां अमेरिकी महिला पर्यटक के साथ टैक्सी चालक ने ऐसा छल किया कि 400 मीटर का सफर सीधे 18 हजार रुपये में तब्दील हो गया।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई: हालांकि, मामला सामने आते ही मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज तीन घंटे के भीतर आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह साफ हो गया कि विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और सम्मान से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पर्यटक ने 'एक्स' पर पोस्ट कर बयां किया अपना दर्द

ठगी का शिकार हुई पर्यटक ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपना दर्द उड़ेल दिया। उसने लिखा, मैंने मुंबई पहुंचकर टैक्सी ली। ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति हमें पहले किसी अज्ञात जगह ले गए, फिर 200 डालर वसूले और आखिर में होटल छोड़ा जो सिर्फ 400 मीटर दूर था। पोस्ट देखते ही मामला आग की तरह फैल गया। मुंबई पुलिस ने बिना देर किए संज्ञान लिया, एफआइआर दर्ज की और महज तीन घंटे के भीतर आरोपित टैक्सी चालक को धर दबोचा। उसके साथी की तलाश जारी है और ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

20 मिनट तक पूर्वी अंधेरी की गलियों में घुमाया: सोचिए 400 मीटर का सफर। जितनी दूरी में आम इंसान दो बार सड़क पार कर ले। उतने रास्ते के लिए आप कितना किराया देंगे? 50 रुपये? 80 रुपये? या सौ? मगर अमेरिका से आई एक महिला पर्यटक के लिए यही मामूली दूरी बन गई दुनिया की सबसे महंगी टैक्सी राइड पूरे 18 हजार रुपये।

घटना छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की है। अमेरिकी पर्यटक को पास ही एक पांच सितारा होटल जाना था जिसकी दूरी महज 400 मीटर थी। मगर टैक्सी चालक देशराज यादव ने सीधे होटल पहुंचाने के बजाय विदेशी मेहमान को पहले करीब 20 मिनट तक पूर्वी अंधेरी की गलियों में घुमाया। कभी दाएं मोड़ा, कभी बाएं फिर उसी इलाके में वापस लाकर होटल छोड़ा और थमा दिया 200 डालर यानी करीब 18,000 रुपये का बिल।

आरटीआइ की 'फिर से समीक्षा' के सुझावों पर कांग्रेस का विरोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में प्रशासनिक नौकरशाही को मजबूत करने के लिए आरटीआइ कानून की फिर से समीक्षा करने के सुझावों का विरोध कर इसे जनता के अधिकारों से जुड़े इस कानून को खत्म करने के इरादा बताया। आर्थिक सर्वेक्षण के सुझावों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस पर गंभीर चिंता जताते हुए मनरेगा के बाद आरटीआइ को निशाने पर लिए जाने की आशंका जताई। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि मनरेगा को खत्म करने के बाद क्या अब आरटीआइ की बारी है। खरगे ने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्स पोस्ट पर में कहा कि इसमें आरटीआइ कानून की ''फिर से समीक्षा'' करने की बात कही है। सूचनाएं बाहर नहीं आने देने और जानकारी रोकने के लिए संभावित ''मंत्रिस्तरीय वीटो'' का भी इसमें सुझाव है। 2025 तक 26 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। खरगे ने कहा कि 2019 में मोदी सरकार ने आरटीआइ कानून में बदलाव कर सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर नियंत्रण कर लिया और इसके जरिये स्वतंत्र निगरानी करने वालों को आज्ञाकारी अधिकारी बना दिया। इसी तरह डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून 2023 ने आरटीआइ के जनहित प्रविधान को खत्म कर दिया। दिसंबर 2025 तक केंद्रीय सूचना आयोग बिना मुख्य सूचना आयुक्त के काम कर रहा था।

हेट स्पीच मामले में कोर्ट का कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को नोटिस

जासं, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने मानहानि मामले में पुनरीक्षण याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। आरएसएस से जुड़े अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि खरगे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नरेगल में एक चुनावी रैली के दौरान हेट स्पीच दिया था। खरगे के बयान से उन्हें व उनके संगठन को ठेस पहुंची है। 11 नवंबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति राजोरिया ने आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बयान किसी विशेष समुदाय, धर्म, जातीय समूह को लक्षित नहीं था।

सुनेत्रा पवार आज ले सकती हैं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ

ओमप्रकाश तिवारी • जागरण

मुंबई : महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की नए उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं। राकांपा नेता छगन भुजबल के अनुसार शनिवार को विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद उन्हें शाम को शपथ दिलाई जा सकती है। वह राज्य में इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे राकांपा के फैसले से सहमत हैं और भाजपा व सरकार उसका पूरा समर्थन करेंगे।

दिवंगत पति अजीत पवार के साथ सुनेत्रा पवार • फाइल/प्रेट्र

शुक्रवार को राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल, वरिष्ठ नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। चारों के बीच करीब एक घंटे बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमत हैं। भुजबल ने कहा कि कुछ परिवारों में शोककाल तीन दिन का, तो कहीं 10 दिन का होता है। कोई दिक्कत नहीं रही तो सुनेत्रा पवार को नेता चुने जाने के बाद शनिवार को शपथ ग्रहण हो सकता है।

बुधवार को बारामती में एक विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गई थी। गुरुवार को बारामती में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ और शुक्रवार को बारामती के करहा एवं नीरा नदी के संगम पर उनका अस्थि विसर्जन कर दिया गया। बता दें कि सुनेत्रा पवार पिछला लोकसभा चुनाव अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार गई थीं। उसके बाद अजीत पवार ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलवाकर दिल्ली की राजनीति में भेज दिया था। यदि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो अजीत पवार के निधन से रिक्त हुई बारामती विधानसभा सीट से चुनाव भी वही लड़ेंगी। उनके ज्येष्ठ पुत्र पार्थ पवार को उनके स्थान पर राज्यसभा भेजा जा सकता है।

दोनों राकांपा में विलय की चर्चाएं भी तेज: अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा एवं उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विलय की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ये चर्चाएं अजीत पवार के जीवित रहते ही चल रही थीं। पिछले डेढ़ माह के अंदर दोनों पार्टियों के विलय को लेकर 14 बैठकें हो चुकी हैं। अजीत पवार के निधन के कुछ ही दिन पहले उनकी शरद पवार से भी बैठक हो चुकी थी। जिला परिषद चुनावों के तुरंत बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में विलय की घोषणा की जानी थी।

सीआइडी ने शुरू की जांच

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र के अपराध जांच विभाग (सीआइडी) ने बारामती विमान दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-194 के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और इसे सीआइडी को सौंप दिया गया है।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अमेरिकी पहेलियां

अमेरिकी रणनीतियों से वैश्विक पहेलियां उलझती जा रही हैं, जिससे हम समाधान के बजाय समस्याओं की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका केवल अपने अनुरूप परिवर्तन करने में लगा है और इस मोर्चे पर वह किसी भी देश की किसी भी सलाह पर कान नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने उचित ही कहा है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान किसी एक शक्ति के दखल से नहीं होगा। गुटेरस ने अपने कार्यकाल के दसवें और अंतिम वर्ष की शुरुआत के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी रवैये पर निराशा का इजहार किया है। निराशा और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार भी संयुक्त राष्ट्र का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने उन तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों के प्रयासों पर पानी फेर दिया है, जो संयुक्त राष्ट्र का आदर करते थे। बदलती या बिगड़ती दुनिया को लेकर अगर आज गहरी चिंता है, तो होनी ही चाहिए। गुटेरस ने यह समझाने की कोशिश की है कि आज कई लोग अमेरिका और चीन के दो ध्रुवों वाले भविष्य की कल्पना करने लगे हैं, लेकिन यदि हम एक स्थिर विश्व चाहते हैं, तो हमें बहुध्रुवीयता का समर्थन करना होगा।

उधर, गाजा में शांति का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि प्रमुख यूरोपीय देशों ने ट्रंप के शांति बोर्ड के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, हमेशा अमेरिका के सहयोगी रहे ब्रिटेन ने वैश्विक समस्याओं से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सद्प्रयासों पर पानी फेर दिया है, जो संयुक्त राष्ट्र का बहुत आदर करते थे।

गाजा में जहां उम्मीद की किरणें मद्धम पड़ रही हैं, वहीं ईरान को घेरने की अमेरिकी कोशिश मुसलसल आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ तनाव के बीच बहुत बड़े और शक्तिशाली जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप की ईरान संबंधी नीति निंदनीय है। वह ईरान में विरोध या विद्रोह को हवा दे रहे हैं। वह यहां तक कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए बस मदद पहुंचने ही वाली है। गौर करने की बात है कि अमेरिकी सहयोग पर भरोसा करके प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हजारों ईरानी काल के गाल में समा चुके हैं और अभी भी अमेरिका मदद पहुंचाने के दावे कर रहा है? अमेरिका खुद पर लोगों के भरोसे को लगातार घटा रहा है, इसका खमियाजा उसे दशकों तक भुगतना पड़ सकता है। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के भरोसे को भी तोड़ चुके हैं। यूक्रेन को भी रूस के मुकाबले में खड़े होने के लिए अमेरिका और नाटो ने प्रेरित किया था। आज स्थिति क्या है? आज रूस और यूक्रेन के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि किसके भरोसे पर और किस शहर में जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात मुमकिन है, यह कहना मुश्किल है।

लगे हाथ वेनेजुएला के हालात पर भी गौर कर लेना चाहिए। अमेरिका के इशारे पर वेनेजुएला की सरकार ने तेल संबंधी अपनी नीति को बदल दिया है। सर्वाधिक तेल भंडार वाले वेनेजुएला में अब निजी कंपनियां भी तेल दोहन का काम करेंगी। यह कदम सीधे-सीधे रूस और चीन के लिए चुनौती है। संभव है, इस चुनौती से निपटने के लिए चीन कोई न कोई कदम उठाएगा। ऐसे में, अमेरिका अब भारत की भूमिका तय करने के लिए बैठकें कर रहा है। यह त्रासद है कि चीन को घेरने के मकसद से भारत का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका रणनीति बनाता लग रहा है। भारत के प्रति अमेरिकी रवैया जैसा रहा है, उसकी रोशनी में भारतीय रणनीतिकारों को बहुत सचेत रहना होगा, ताकि भारत दुनिया में समाधान का हिस्सा बने, किसी समस्या का नहीं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 31 जनवरी, 1951

बुनियादी सवाल

कांग्रेस-महासमिति का अहमदाबाद में जो अधिवेशन हो रहा है, उसके पहले दिन ही एक सदस्य ने कुछ ऐसी बात कही, जिससे नेहरूजी उत्तेजित हो गए और सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि वे ऊपरी बातों के चक्कर में बुनियादी बातों की उपेक्षा न करें।

प्रश्न कांग्रेस-विधान में संशोधन के समय सदस्यता की शर्त का था। 1948 में सदस्यता-शुल्क खत्म कर दिया गया था, किन्तु बाद के अनुभव ने फिर से सदस्यता शुल्क जारी करने की आवश्यकता का भान कराया। कार्य समिति ने एक रुपया शुल्क रखने का प्रस्ताव रखा है, जिसपर किसी ने चार आना, किसी ने चार आना प्राथमिक के लिए और बारह आना कर्मठ सदस्यता के लिए, किसी ने 'समझौतास्वरूप' आठ आना शुल्क करने को कहा। और, सदस्यता की शर्तों के सिलसिले में, एक सदस्य ने यह सुझाव भी रखा कि हरएक कर्मठ सदस्य के लिए कुछ जमीन जोतना आवश्यक हो; दूसरी ओर, एक साहब ने फरमाया कि कांग्रेस सदस्य के लिए साम्प्रदायिक एकता की शर्त रखने की अब आवश्यकता नहीं रही है। यही सुनकर नेहरूजी उत्तेजित हुए और उन्होंने बुनियादी बातों की, जिन पर कि कांग्रेस का आधार है, याद दिलाई।

नेहरूजी में कहा कि कांग्रेस बराबर कुछ आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती रही है और आज भी हरएक कांग्रेसजन को उन आदर्शों के लिए ही काम करना चाहिए। सदस्यता का प्रश्न बुनियादी सवाल ही है और साम्प्रदायिक एकता नींव की बात है, जिसको छोड़कर काम नहीं किया जा सकता। कांग्रेसजनों को उन्होंने याद दिलाई कि कांग्रेस का ध्येय जन-सेवा है। यही कांग्रेस का उद्देश्य, लक्ष्य और कर्त्तव्य है। इसे पूरा करना ही बुनियादी सवाल है और इसमें असफल रहने पर कांग्रेस की मृत्यु है तथा इसे करते रहने में उसकी सफलता, अतः इसपर आगे बढ़ते रहना ही कांग्रेसजनों का परम कर्त्तव्य है। नेहरूजी ने आगे यह भी कहा कि अपने दृढ़ निश्चय, अपने साहस और अपने अमली काम के जरिये कांग्रेसजनों को कांग्रेस और उसके साथ समस्त देश को भी आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस की उपमा उन्होंने तलवार के फलके से दी और कहा कि यह एक औजार है, जिसे हमने गुलामी की जंजीरें काटी हैं और आगे भी हमें दूसरी और लड़ाइयां लड़नी हैं तथा देश को आगे ले जाना है।

शिक्षा संस्थानों में सामाजिक समता लाने के लिए यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों पर पूरे देश में चर्चा तेज है। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने नए नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी है। इस पर आम सहमति है कि अपने देश में जाति के आधार पर भेदभाव होता है। अब जहां एक पक्ष यह मानता है कि नए नियमों को तत्काल लागू किया जाए, तो दूसरे पक्ष की दलील है कि नियमों से संबंधित शिकायतों पर भी गौर कर लिया जाए।

आमने-सामने

सवर्ण छात्रों से भेदभाव की आशंका निराधार

यहां स्कैन करें

श्यौराज सिंह बेचैन | पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विवि

- आरक्षित वर्ग के छात्रों द्वारा सामान्य वर्ग से भेदभाव का कोई मामला नहीं है।
- भेदभाव के मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही नियमों को चुस्त किया गया है।
- संस्थानों के प्रमुख सामान्य वर्ग से हैं, तो अन्याय होने का सवाल नहीं।

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच समतावर्धक नियम को विस्तृत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 15 जनवरी, 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। दिशा-निर्देश में ऐसे संस्थानों को अपने यहां 'समता समिति (इक्विटी कमेटी)' और 'समान अवसर केंद्र' जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं को अनिवार्य करने को कहा गया है। यूजीसी विधेयक-2026 का मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा में भेदभाव समाप्त करना और खासकर वंचित समूहों को समान अवसर प्रदान करना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ महिला, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया है, जिससे सामान्य वर्ग के कुछ छात्र नियमों के दुरुपयोग की कल्पना से आशंकित हो उठे हैं। फौरी तौर पर कोर्ट ने अगले माह तक क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, पर घटनाएं व चर्चाएं और बढ़ेंगी।

भेदभाव की खबरें और आंकड़े देखें, तो उनमें एक फीसदी भी ऐसी घटनाएं नहीं हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने सामान्य वर्ग के साथ कोई भेदभाव या जाति उत्पीड़न किया हो, जबकि उनके विरुद्ध हुए भेदभाव के आंकड़े शत-प्रतिशत हैं। नई दिल्ली के एम्स में 2008 में अनुसूचित जाति के दो डॉक्टरों ने, आईआईटी बॉम्बे में 12 फरवरी, 2023 को 18 वर्षीय अनुसूचित जाति के छात्र दर्शन सोलंकी ने, आईआईटी दिल्ली में अनुसूचित जाति के छात्र अनिल ने और मई 2019 में अनुसूचित जनजाति की डॉक्टर पायल तड़वी ने जातिवादी टिप्पणियों से तंग आकर आत्महत्या की थी। 27 सितंबर, 2023 को आए आंकड़ों के अनुसार, साल 2014 से 2021 के बीच आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी में अनुसूचित जाति के कुल 72 छात्रों ने आत्महत्या की। अपवाद में ही सही, किंतु आत्महत्या अगड़े छात्र द्वारा भी की जाती है, परंतु न तो उनमें वंचित वर्गों के छात्र कारण होते हैं और न ही वे आत्महत्याएं जातिगत भेदभाव के कारण होती हैं।

यूजीसी के हालिया दिशा-निर्देश हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आत्महत्या करने वाले शोध छात्र रोहित वेमुला और पायल तडवी की माओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं को लेकर है। अब चूंकि रोहित वेमुला की माता अनुसूचित जाति से और पिता अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, इसीलिए मामलों की गंभीरता को देखते हुए नियमों को चुस्त किया गया है। वेमुला मामले में पिता के अन्य पिछड़ा वर्ग के होने से 'दलित ऐक्ट' लागू नहीं हो सका था।

उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 'मंडल आयोग' की सिफारिशें लागू होने पर 2009 से आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ, तब उन्हें भी जातिगत भेदभाव का अनुभव हुआ। इसके बाद इस वर्ग ने भी अनुसूचित जाति-जनजातियों जैसा संरक्षण मांगना शुरू किया। इसी आधार पर संबंधित समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व दिव्यांग श्रेणियों के लिए भी भेदभाव रहित समता सुनिश्चित करने वाली समितियों के दरवाजे खोले।

सामान्य वर्ग के छात्रों की आशंकाओं का आधार काल्पनिक है। जहां तक नियमों के दुरुपयोग की बात है, वह हो नहीं सकता। होने की गुंजाइश इसलिए नहीं है, चूंकि इन समितियों के अध्यक्ष संस्थानों के प्रमुख ही होंगे और संस्थान प्रमुख अपवाद छोड़ आमतौर पर सामान्य वर्ग के ही होते हैं। इक्विटी कमेटी में संस्थान से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे से एक-एक व्यक्ति सदस्य होगा। बाकी 60 फीसदी से अधिक सामान्य वर्ग से ही होंगे। जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप व आशंका भी आधारहीन है। मामले को संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान व उपाधियों से जोड़ना अन्याय और भेदभाव रोकने के लिए अमल को बाध्यकारी बनाना है।

ऐसा भी नहीं है कि नियम एकाएक थोप दिए गए हैं, अपितु यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट के समय से ही संस्थाओं में सर्वेक्षण चल रहे थे और नियम बन रहे थे। 2011 में उनके पद छोड़ने के बाद 2012 में अमल की प्रक्रिया कुछ तेज हुई। अब संविधान लागू होने की सालगिरह गणतंत्र दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय का यह विचार विमर्श में आया, तो सामान्य वर्ग की कई आशंकाएं हास्यास्पद-सी लगीं। वे कहते हैं, हमारे साथ भी भेदभाव हो सकता है। क्या किसी सवर्ण के साथ वैसा हुआ है? शिक्षा के आधारभूत पायदान- प्राथमिक शिक्षा से देखा जाए, तो वहां सामान्य छात्र-छात्राएं अलग, दलित अलग बिठाए जाते हैं। साठ फीसदी स्कूलों में सवर्ण दलित महिला के हाथों से बनाया मिड-डे भोजन नहीं खाते और गैर-दलित महिला खाना बनाने नहीं आती है। भेदभाव दूर न होने के कारण अनुसूचित जाति के 30 फीसदी बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। पांच साल के मेघवाल छात्र को सवर्ण शिक्षक के घड़े से पानी लेने के 'जुर्म' में पीट-पीटकर मार डाला जाता है।

अब इस नियम के प्रभाव को देखें, तो संबंधित संस्थान के प्रमुख ही इक्विटी कमेटी के प्रमुख होंगे, वही तय करेंगे कि भेदभाव हुआ या नहीं, शिकायत झूठी है या सच्ची। चूंकि संस्थान प्रमुख प्रायः अनुसूचित जाति-जनजाति के नहीं होते, ऐसे में, वह न्याय तो नहीं ही कर पाएंगे। उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी पूरा नहीं है। यदि होता, तब भी वे 22 फीसदी से अधिक नहीं होते। अनुसूचित जाति-जनजाति के कुलपति एक फीसदी भी नहीं हैं, जबकि सामान्य वर्ग के 80 फीसदी से भी अधिक हैं। वे सामान्य के साथ भेदभाव क्यों होने देंगे? आईआईटी, आईआईएम, नर्सिंग ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, कृषि विश्वविद्यालय आदि स्वायत्त संस्थाओं में, जो राजकीय के समानांतर, बल्कि कई तो उससे भी आगे हैं, ये नियम अमल में नहीं हैं। वहां भेदभाव का निवारण कौन करेगा?

'सामान्य वर्ग' के लोग काल्पनिक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे साथ भी भेदभाव हो सकता है। कैसा भेदभाव? इस संदर्भ को संविधान के अनुच्छेद 14-15 से जोड़कर समझना चाहिए और नियमों के क्रियान्वयन को शिक्षा व अन्य स्तरों पर होने वाले, पक्षपात, भेदभाव और अनियमितता की गुंजाइशों तक विस्तार देना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

शिकायतों की सुनवाई करे सर्वोच्च न्यायालय

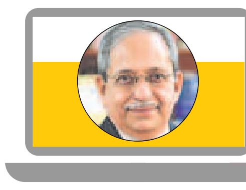

यहां स्कैन करें

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएम, नई दिल्ली

- न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया माना है कि नए नियमों का दुरुपयोग संभव है।
- यह जानना-समझना जरूरी है कि सवर्ण वर्गों में किन बातों को लेकर नाराजगी है।
- नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कुलपतियों, प्राचार्यों को भी लेनी होगी।

यूजीसी ने पिछले दिनों उच्च शिक्षा संस्थानों में समता बढ़ाने के लिए जो नए नियम जारी किए हैं, उसके विरुद्ध उठे सवर्ण युवाओं के आक्रोश के फिलहाल थम जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति बागची की पीठ ने यूजीसी के नए नियमों पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। न्यायालय ने इन नियमों को लेकर प्रथम दृष्टि में ही दुरुपयोग की आशंका जताई है। अब आगे सुनवाई चलने तक यूजीसी द्वारा 2012 में जारी किए गए नियम ही जारी रहेंगे। बहरहाल, यह तो स्पष्ट हो गया है कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थान सामाजिक भेदभाव के दुष्प्रभावों से अछूते नहीं हैं। आरक्षित वर्ग अगर आशंकित है, तो अनारक्षित वर्ग में भी भय व चिंता देखी जा रही है।

जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस ज्वलंत मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला ले पाएगा, यह बहस जारी रहेगी कि हमारे उच्च शिक्षा परिसरों में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र और दिव्यांगता पर आधारित विविध प्रकार के भेदभाव क्यों बढ़ रहे हैं? क्या हमारे संस्थान विद्यार्थी वर्ग में आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी समाज की विचारधारा को फैलाने की कोई कोशिश कर पा रहे हैं? क्या यह कटु सत्य नहीं है कि आरक्षित और गैर-आरक्षित जातियों के विद्यार्थियों को कई स्थानों पर अलग-अलग रखा जाता है। जाति आधारित छात्रावास बनाने की होड़ देखी जाती है, क्या यह भेदभाव दूर करने का सही तरीका है?

यूजीसी द्वारा 13 जनवरी, 2026 को जारी किए गए समता संबंधी नए नियमों के विरुद्ध जो व्यापक रोषपूर्ण प्रतिक्रिया सवर्ण जातियों के युवाओं में देखी गई है, उसके बाद यह जानना और समझना जरूरी है कि सवर्ण वर्गों में किन बातों को लेकर नाराजगी है? एक बड़ा वर्ग आशंकित है कि उन पर आरक्षित जातियों के छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव करने के झूठे आरोप लगाए जा सकेंगे और उनके पास अपना बचाव करने के उपाय नहीं होंगे। यूजीसी के नए नियमों के विरोधियों की पहली आपत्ति आरक्षित विद्यार्थियों में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को जोड़ना है, जबकि 2012 के नियम में सिर्फ एससी व एसटी वर्ग के विद्यार्थी ही शामिल थे, जिन पर होने वाले भेदभाव पर कार्यवाही की जाती थी।

सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के वकीलों का दूसरा तर्क यह है कि कि नए नियमों की धारा 3(सी) में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ आरक्षित जातियों के विद्यार्थियों पर होने वाले भेदभाव को शामिल किया गया है और गैर-आरक्षित जातियों के विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव को छोड़ दिया गया है।

तीसरा तर्क जातिगत तथा अन्य प्रकार के भेदभावों को रोकने के लिए हर संस्थान में जो समता समिति बनाई जानी है, उसमें 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित जातियों के लिए रखा जाना है। शेष स्थानों को कैसे भरा जाएगा, यह नए नियमों में स्पष्ट नहीं किया गया है।

अब इन आपत्तियों का निराकरण सर्वोच्च न्यायालय को करना होगा, किंतु अनेक सवाल हैं, जिनका जवाब हमें खोजना चाहिए। भेदभाव और उत्पीड़न के मामले आजादी के 78 साल बाद भी क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या उच्च शिक्षा के मंदिरों को भारत को एक आधुनिक, समृद्ध, शक्तिशाली एवं प्रगतिशील राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है? निस्संदेह, विद्यार्थियों के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न की इजाजत नहीं दी जा सकती। सवर्ण छात्रों में यह शिकायत आम है कि प्रवेश, पाठ्यक्रम चयन व सुविधाओं के स्तर पर उनके साथ न्याय नहीं होता है और अब नए नियमों के तहत उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा सकता है।

जरा इस तथ्य का भी पुनरावलोकन कीजिए कि आखिर यूजीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों में कई दशकों से चले आ रहे भेदभाव और उत्पीड़न के विरुद्ध नए नियम 13 जनवरी को क्यों जारी करने पड़े? इसके पीछे हैदराबाद और मुंबई के दो कैंपसों में दो छात्रों द्वारा की गई आत्महत्या भी शामिल है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी के समता संबंधी नियमों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय से यह मांग हुई थी कि शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के विरुद्ध सख्त नियम बनाए जाएं। वाकई नियम सख्त होने चाहिए, पर ऐसे होने चाहिए, जो समता को बल दें, ऐसे नहीं कि जिनसे भेदभाव या दुर्भावना बढ़ने की आशंका पैदा हो जाए।

हां, यह सही है कि जातिगत भेदभाव होता है। साल 2023 में लोकसभा में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित सौ से अधिक राष्ट्रीय संस्थानों में 2014 और 2021 के बीच 122 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की थी, जिनमें 68 या 55 प्रतिशत आरक्षित जातियों में से थे। यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय समिति को 2024 में यह जानकारी दी कि 2020 और 2024 के दौरान जातिगत भेदभाव के मामले 118 प्रतिशत ज्यादा दर्ज हुए हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि पिछड़ी जातियों में सजगता बढ़ रही है और यह भी देखने की जरूरत है कि आत्महत्या करने वाले छात्रों में सवर्ण छात्र भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा संस्थानों में बेहतर और न्यायपूर्ण माहौल के लिए व्यापक प्रयासों की जरूरत है। ऐसा केवल नियम बना देने भर से सुनिश्चित नहीं होगा।

भेदभाव दूर करने के मोर्चे पर नाकामी की एक बड़ी वजह राजनीतिक दलों का व्यवहार भी है। राजनीतिक दल भी जातिगत भेदभाव या दुष्प्रभाव से परे नहीं हैं।

हम अगर शिक्षा को एक अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा के परिसरों से जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और लिंगभेद के जहर को सख्ती और वैचारिक रूपांतरण द्वारा मिटाना होगा। समता लाने के लिए सख्त नियम और कानून बनाना आसान है, परंतु उनके न्यायोचित क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कुलपतियों, प्राचार्यों और शिक्षकों को लेनी होगी। उच्च शिक्षा के परिसरों में किसी भी भेदभाव के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या भारतीय समाज, राजनीति और प्रशासन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

क्रोध प्रेम से ही हारेगा

जब मन में क्रोध की एक बड़ी तरंग आती है, तब उसे कैसे वश में लाया जाए? बहुत सरल सा जवाब है- उसके विपरीत एक तरंग उठाकर। उस समय प्रेम की बात मन में लाओ।

कभी-कभी ऐसा होता है कि पत्नी अपने पति पर खूब गरम हो जाती है, लेकिन उसी समय उसका बच्चा वहां आ जाता है और वह उसे अपनी गोद में उठाकर चूम लेती है; इससे उसके मन में बच्चे के प्रति प्रेम-तरंग उठने लगती है और वह पहले तरंग को दबा देती है। प्रेम क्रोध के विपरीत है। इसी प्रकार, जब मन में किसी किस्म की चोरी का भाव उठे, तो उसके विपरीत भाव का चिंतन करना चाहिए। जब दान ग्रहण करने की इच्छा पैदा हो, तो उसके विपरीत भाव का चिंतन करना चाहिए।

मैं स्वयं यदि कोई झूठ कहूं, तो उससे जो पाप होता है, उतना ही पाप तब भी होता है, जब दूसरे को झूठ कहने में लगाता हूं अथवा दूसरे की किसी झूठी बात का अनुमोदन करता हूं। वह झूठ भले ही जरा सा हो, फिर भी झूठ तो है ही। पर्वत की कंदरा में बैठकर भी यदि पाप चिंतन करो, किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करो, तो वह भी संचित रहेगा और कालान्तर में फिर से वह तुम्हारे पास किसी दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा।

यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या और घृणा का भाव चारों ओर प्रसारित करते हो, तो वह चक्रवृद्धि ब्याज सहित तुम पर आकर गिरेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक न सकेगी। यदि तुमने एक बार उस शक्ति को बाहर निकाला, तो फिर निश्चित जानो, तुम्हें उसका प्रतिघात सहन करना ही पड़ेगा। यह स्मरण रहने पर तुम कुकर्मों से बचे रह सकोगे।

विवेकानंद

दलाई लामा | बौद्ध धर्मगुरु

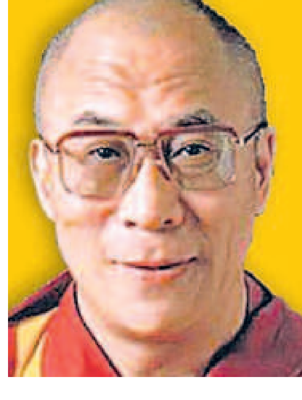

अपने मन की शांति के लिए हमें धैर्य की जरूरत है। क्षमा और धैर्य हमारी रक्षा का हिस्सा है। परेशानी देने वाले लोग इस मायने में हमारे मददगार होते है कि वे हमें धैर्य और क्षमा की साधना का मौका देते हैं।

अनुलोम-विलोम

डिजिटल व्यसन

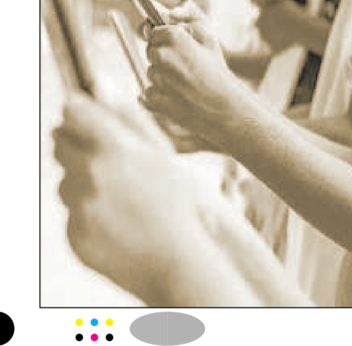

बच्चों में सोशल मीडिया की लत पर लगे लगाम

बच्चों में इंटरनेट-मोबाइल की बढ़ती लत पर कैसे लगे लगाम, इस पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य सलाहकार अनंत नागेश्वरन गहरी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत छुड़ाने के लिए माता-पिता को अहम भूमिका निभानी होगी। डिजिटल कंपनियां भी ऐसे कंटेंट्स हटाए, जिनका बुरा प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया व फिनलैंड ने 15 साल तक के बच्चों के लिए इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं फ्रांस की असेंबली में इस पर सहमति बन गई है और ब्रिटेन, डेनमार्क व ग्रीस में इस विषय पर अध्ययन चल रहा है। हमारे देश में भी गोवा और आंध्र प्रदेश में इसको लेकर सर्वेक्षण चल रहा है, ताकि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मसलन, देश-विदेश में बच्चों पर पड़ने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक प्रभावों के मद्देनजर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता बढ़ गई है, क्योंकि इनकी अव्यावहारिक सामग्रियां बच्चों के स्वभाव, व्यवहार, पढ़ाई, दिनचर्या, स्वास्थ्य व मानसिक सोच पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। हमारी सरकार को भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि बच्चों के साथ ही उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहे और समाज में बुराइयों पर भी लगाम लग सके।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

आर्थिक सर्वेक्षण में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र सीमा तय करने की सिफारिश की गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक, उम्र के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित की जानी चाहिए, ताकि बच्चे कम उम्र में डिजिटल दबाव और ऑनलाइन कंटेंट के नकारात्मक असर से बच सकें।

बताया गया है कि लंबे समय तक स्क्रीन के इस्तेमाल से अनिद्रा, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया गया है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी रोक लगाई गई है। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर लगातार चेतावनी देते रहते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से इसका बच्चों और बड़ों के दिमाग के साथ ही शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है, साथ ही और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जरूरी है कि अपने देश में भी बच्चों के बीच सोशल मीडिया और फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।

कौशल कुमार, छात्र

व्यसन के बहाने जिम्मेदारी से न भागे सरकार

गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में बच्चों से जुड़ी एक अहम बात कही गई कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में सरकार से अपील की गई है कि वह बच्चों में बढ़ते डिजिटल व्यसन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए।

किसी भी चीज की अति हमेशा वर्जित है। इसका तो कोई समर्थन नहीं करेगा, मगर यह बात बच्चों पर ही नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों पर लागू होती है। आप कभी भी गौर कर लीजिए। बच्चे तो फिर भी खेलने-कूदने, स्कूल में होने या घूमने-फिरने में मोबाइल व टैब से दूर रहते हैं, मगर नौजवान और प्रौढ़ लोग कहीं ज्यादा स्क्रीन में डूबे रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों के लिए मोबाइल, टैब और लैपटॉप अब मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि ये उनकी जरूरत बन गए हैं। अगर उन्हें ये साधन नहीं मुहैया कराए गए, तो वे जिंदगी की दौड़ में काफी पीछे रह जाएंगे और साधन संपन्न तबका आगे निकल जाएगा। फिर यह विषमता बढ़ती ही जाएगी। कोरोना महामारी ने हमें साफ-साफ दिखा दिया था कि किस तरह सुदूर इलाकों और गरीब तबकों के बच्चे पीछे रह गए थे। सरकारों ने ईमानदारी से इस बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया, मगर हकीकत यही है कि उन डेढ़-दो वर्षों में अनेक बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उनके मां-बाप के पास स्मार्टफोन नहीं थे, जिससे वे बच्चे कक्षाएं न ले सके। सरकारों ने उन्हें 'ग्रेस मार्क्स' देकर अगली कक्षाओं में पहुंचाने का उपक्रम भले किया, मगर स्कूल जाने, कक्षा में बैठने का अनुशासन टूटा, तो अनगिन बच्चों का मन भी उचट गया और वे फिर कभी स्कूल न लौट सके।

आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वह इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर इस कदर निर्भर है कि उसके बिना अब जीने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एआई के विस्तार के बाद तो इनकी उपयोगिता और बढ़ने वाली है। ऐसे में, बच्चों के डिजिटल व्यसन का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल, इस तरह की सिफारिश से होगा यह कि सरकारें इस रिपोर्ट का हवाला देकर गरीब बच्चों को टैबलेट मुहैया कराने की किसी योजना को ठंडे बस्ते में डाल देंगी। शहरों व संपन्न परिवारों के बच्चों पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर वंचित तबके के बच्चे पीछे रह जाएंगे। सरकार को अगर देश के बच्चों की सेहत की वाकई फिक्र है, तो वह उनके पोषण और शिक्षा में ज्यादा निवेश करे। हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा मद में खर्च होता है, यह बताने की जरूरत नहीं। इसलिए डिजिटल व्यसन का प्रचार जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाना है।

मेघा महतो, टिप्पणीकार

अचानक वार से बेसुध हुई वरना स्वाट कमांडो को मारना आसान नहीं

फॉलोअप

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। द्वारका में दिल्ली पुलिस की स्वाट कमांडो काजल चौधरी की हत्या के मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि काजल के सिर पर उसके पति ने अचानक लोहे के डंबल से हमला किया था, जिससे वह बेसुध हो गई।

जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अचानक हुए हमले के कारण ही काजल अपना बचाव नहीं कर पाई, वरना एक महिला स्वाट कमांडो हाई-रिस्क ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होती हैं। उन्हें मारना आसान नहीं। डंबल का पहला वार होते ही काजल बेहोश हो गई। इसके बाद उसने उसके सिर पर कई बार हमला किया, जिससे मौत हुई। काजल चार माह की गर्भवती थी। जांच में सामने आया है कि अंकुर और काजल के बीच अक्सर परिवार की मदद और आर्थिक मामलों को लेकर विवाद होता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, काजल के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद अंकुर और उसका परिवार पैसों को लेकर परेशान करता था। अंकुर न तो घर खर्च में योगदान देता था और न बच्चों की देखभाल में। लोन की ईएमआई और अन्य खर्चे काजल खुद चलाती थी, बावजूद इसके उसे ताने दिए जाते थे। अंकुर का बड़ा और छोटा भाई बेरोजगार हैं। अंकुर अक्सर उनकी मदद करता था, जिससे दोनों के बीच तनाव रहता था। वारदात वाले दिन अंकुर को उसके भाइयों की मदद करने का हवाला देते हुए जवाब दिया था।

दिल्ली पुलिस की स्वाट कमांडो काजल। ● फाइल फोटो

कौन होते हैं स्वाट कमांडो?

स्वाट का पूरा नाम स्पेशल वेपंस एंड टैक्टिक्स है। ये कमांडो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का हिस्सा हैं। यह टीम 26/11 मुंबई हमले के बाद बनाई गई थी। दिल्ली की टीम में महिला स्वाट कमांडो भी शामिल हैं। इस टीम का उद्देश्य हाई-रिस्क ऑपरेशन और आतंकी हमलों से निपटना है। स्वाट कमांडो तकनीकी और शारीरिक दोनों रूप से बेहद कुशल होते हैं। उनके पास खास हथियार और कौशल होता है।

छह माह की विशेष ट्रेनिंग मिलती है

स्वाट कमांडो की ट्रेनिंग बहुत चुनौतीपूर्ण और कठोर होती है। इसमें शामिल होने वाले जवानों को शारीरिक और मानसिक दक्षता के कई टेस्ट पास करने होते हैं। फिटनेस, स्टैमिना और शूटिंग टेस्ट के आधार पर ही टीम में चयन किया जाता है। ट्रेनिंग आम तौर पर 3-6 महीने तक चलती है और इसमें अलग-अलग सिचुएशन में ऑपरेशन का अभ्यास कराया जाता है।

संवेदनशील स्थानों पर होती है तैनाती

- दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम को अतिसंवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाता है
- वीआईपी सुरक्षा, त्योहार पर अलर्ट वाले स्थानों और आतंकवादियों के टारगेट वाले स्थानों पर स्वाट कमांडो की तैनाती की जाती है

एक कमांडो की तैयारी पर तीन लाख तक खर्चा

शारीरिक ट्रेनिंग
इसमें 5 किमी दौड़, ऑब्सटेकल कोर्स और लंबी दूरी की मार्च शामिल है।

मानसिक ट्रेनिंग
इसमें सर्वाइवल ट्रेनिंग, मानसिक परीक्षा, और टैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल है

- **विशेषज्ञता**
स्नाइपिंग, तोड़फोड़ और जीवित रहने की स्किल सिखाई जाती है
- **लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग**
ट्रेड-क्राफ्ट ट्रेनिंग और खुफिया एजेंसियों की ट्रेनिंग शामिल है
- **खर्च :** एक स्वाट कमांडो की ट्रेनिंग पर लगभग 2-3 लाख रुपये प्रति माह का खर्च आता है

शहर 30s

अंतरराष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल की सिल्वर जुबली के अवसर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आयोजित प्रदर्शनी में पुराने नाटकों की तस्वीर देखते दर्शक। ● सोनू मेहता

रोडरेज में प्रॉपर्टी डीलर पर हमला

नई दिल्ली। उत्तम नगर इलाके में रोडरेज की घटना में स्कूटी से बाइक टकराने के बाद स्कूटी सवार युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर गुलशन (35) को पीटकर चाकू से हमला कर दिया। 14 जनवरी को दाल मिल रोड पर बाइक बंद होने से टक्कर हुई थी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और पीछे से चाकू से कई वार किए। घायल को दोस्त अस्पताल ले गया। पुलिस ने 27 जनवरी को केस दर्ज कर सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

अदालत में दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज

नई दिल्ली। अदालत ने बांग्लादेशी नागरिक बिलाल होसेन की जमानत रद्द करने की दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव गुप्ता ने आदेश में कहा कि जमानत का कोई गलत इस्तेमाल या शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। होसेन पर आरोप है कि वह गैर-कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कराने और पहचान दस्तावेज हासिल करने में शामिल था। पुलिस ने कई आधार व पैन कार्ड बरामद किए हैं, लेकिन यूआईडीएआई से सत्यापन लंबित है।

खालिद सैफी को 13 दिन की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा साजिश मामले के आरोपी खालिद सैफी को अदालत ने कड़ी शर्तों के साथ 13 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने भतीजों की शादी और रमजान मनाने के आधार पर राहत दी। अदालत ने सैफी को सोशल मीडिया, मीडिया संपर्क और गवाहों से संपर्क पर रोक लगाई। वह दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ सकेगा। 6 से 13 फरवरी तक 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

अदालत परिसरों में इंटरनेट सुधारने के निर्देश

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी के सभी अदालत परिसरों में मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि कमजोर सिग्नल के कारण वकील और पक्षकार मोबाइल व लैपटॉप पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह आदेश वकील अर्पित भार्गव की याचिका पर आया। अदालत ने पूर्व में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए संबंधित अधिकारियों को ठोस और प्रभावी कदम उठाने को कहा है।

ड्रग्स तस्करी के मामले में आरोपी महिला को राहत

नई दिल्ली। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी युगांडा की महिला ओगोला मौरीन एटिएनो को अदालत ने जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश गौरव गुप्ता ने कहा कि गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 46(4) का उल्लंघन करते हुए की गई, जो महिलाओं की रात में गिरफ्तारी पर रोक लगाती है। अभियोजन के अनुसार, 1 मई 2025 को आईजीआई एयरपोर्ट पर उसे रोका गया था और अस्पताल में 530 ग्राम मेथाक्वालोन और कोकीन के कैप्सूल बरामद हुए थे।

शास्त्री पार्क इलाके की झाड़ियों में ले जाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया

सौतेले पिता ने बेटे को मार डाला

शर्मनाक

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। सौतेले पिता ने अपने 12 वर्षीय बेटे की नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी।

आरोपी गुरुवार शाम बच्चे को बहाने से अपने साथ ले गया, झाड़ियों में ले जाकर उसकी हत्या करने के बाद चुपचाप घर लौट आया। रातभर बच्चे की तलाश के बाद शुक्रवार सुबह आरोपी ने खुद फोन कर अपनी पत्नी को हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 9:50 बजे शास्त्री पार्क थाने में एक बच्चे की हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम शास्त्री पार्क चौक लूप स्थित वारदातस्थल पर पहुंची। मौके पर 12 वर्षीय अल्तमश अचेत अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अल्तमश ● फाइल फोटो

- आरोपी ने हत्या के बाद पत्नी को कॉल कर जानकारी दी

इसके बाद पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू की और स्थानीय लोगों व परिजनों से पूछताछ की।

घर आकर झूठ बोला था : पुलिस के अनुसार, वाजिद बच्चों को शास्त्री पार्क लालबत्ती के पास ले गया। वहां उसने वसी को रिक्शे में ही बैठा रहने को कहा और अल्तमश को पास की झाड़ियों में ले गया। आरोप है कि वहीं नुकीले हथियार से अल्तमश पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी वापस आया और वसी से कहा कि अल्तमश घर चला गया है।

पिता की मौत हो चुकी

अल्तमश शास्त्री पार्क में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में मां मुमताज, बड़ा भाई अमन, छोटा भाई वसी, सौतेला पिता वाजिद और एक शादीशुदा बहन ईरम शामिल हैं। बहन ईरम ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में उनके पिता शफीक की मौत हो गई थी। इसके कुछ महीनों बाद मां मुमताज ने वाजिद से निकाह कर लिया था। वाजिद पहले से शादीशुदा था और रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च चलाता था।

स्कूल से लेकर आया

पुलिस को दिए गए बयानों में परिजनों ने बताया कि पिछले करीब एक सप्ताह से मुमताज और वाजिद के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। झगड़े बढ़ने पर मुमताज परेशान होकर अपनी बहन के घर जाकर रहने लगी थी। इसी दौरान गुरुवार शाम अल्तमश और वसी स्कूल से लौट रहे थे। तभी वाजिद अपने रिक्शे से स्कूल के पास पहुंचा और दोनों बच्चों को साथ ले गया। देर रात तक अल्तमश घर नहीं पहुंचा।

इसके बाद वह बच्चे को लेकर घर लौट आया, लेकिन अल्तमश नहीं पहुंचा।

रातभर परिजन अल्तमश को ढूंढते रहे : गुरुवार रातभर परिजन अल्तमश को ढूंढते रहे। पूरा परिवार परेशान था और आसपास के इलाकों में तलाश जारी रही। इसी बीच शुक्रवार सुबह आरोपी वाजिद ने मुमताज को फोन कर सौतेले बेटे की हत्या करने की बात कबूल की और वारदातस्थल का पता भी बताया। सूचना मिलते ही मुमताज ने पुलिस को जानकारी दी।

पुलिस ने मृतक की मां के बयान के आधार पर आरोपी वाजिद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमों को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है।

फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

पति-पत्नी ने फ्लैट में फंदा लगाकर आत्महत्या की

सनसनीखेज

- सुसाइड नोट में बच्चों के कामयाब न होने और कर्ज का जिक्र
- बेटे को माता-पिता के शव अलग-अलग कमरों में फंदे पर लटके मिले थे

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में गुरुवार देर रात अधेड़ दंपति ने फ्लैट में फंदा लगाकर जान दी। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय अजय कुमार और 50 वर्षीय रीता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

दोनों के शव अलग-अलग कमरों में लटके मिले। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें जोड़े ने बच्चों के कामयाब न होने, कर्ज और व्यवसाय में समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।

अजय कुमार मेडिकल स्टोर चलाते थे : घटना की जानकारी गुरुवार रात 12:05 बजे ज्योति नगर थाने को मिली। पुलिस ने तुरंत टीम भेजकर फ्लैट की जांच की। अजय कुमार सोनिया विहार में मेडिकल स्टोर चलाते थे, जबकि रीता घर पर ही रहती थीं। उनका बड़ा बेटा 29 वर्षीय भास्कर पिछले कुछ समय से पिता के साथ मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा था। छोटा बेटा 25 वर्षीय शरद एक निजी कंपनी में कार्यरत है। भास्कर ने बताया कि गुरुवार रात 11 बजे घर लौटकर उन्होंने माता-पिता से भोजन के लिए पूछा, लेकिन दोनों ने भूख न होने की बात कही। उन्होंने भास्कर को बाहर जाकर भोजन लाने के लिए कहा। करीब 11:45 बजे भोजन लेकर लौटे तो देखा कि पिता और मां अपने-अपने कमरे में फंदे से लटके हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि की।

कारणों की जांच कर रही टीम : शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम पूरा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस घटना की पुष्टि के लिए फ्लैट के फुटेज खंगाल रही है और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

नामी ब्रांड के नकली जूते बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी

नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सोनिया विहार में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के नकली जूते बनाने वाली फैक्टरी का खुलासा किया है। पुलिस ने फैक्टरी मालिक 44 वर्षीय संदीप सिंह को गिरफ्तार किया। फैक्टरी में न्यू बैलेंस, नाइकी, एडिडास और स्केचर्स जैसे ब्रांड के जूते बड़े पैमाने पर नकली बनाए जा रहे थे।

पुलिस उपायुक्त संजीव यादव ने बताया कि इंस्पेक्टर अमित सोलंकी की टीम ने संबंधित ब्रांड के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चौहान पट्टी इलाके में यह कार्रवाई की। मौके पर भारी हीटिंग प्रेस मशीन, ब्रांडेड लोगो और मटेरियल बरामद हुआ। लगभग 10 हजार नकली जूतों के ऊपरी हिस्से और स्टिकर शीटें भी मिलीं। पूछताछ में संदीप सिंह ने बताया कि उसने पहले चावड़ी बाजार में प्रिंटिंग प्रेस में काम किया और समय के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। बाद में यह यूनिट ब्रांडेड जूतों के नकली उत्पादन में बदल गई। पुलिस ने फैक्टरी से छह मशीनें, नौ प्रिंटिंग स्क्रीन और 131 डाई बरामद की हैं। यह कार्रवाई नकली उत्पादों के खिलाफ चल रही अभियान का हिस्सा है।

हत्या के मामले में आरोपी हत्थे चढ़ा

नई दिल्ली, व.सं.। स्पेशल सेल ने एक युवक की हत्या के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान आरोपी मो. मोइन कुरैशी के पैर में गोली लगी।

पुलिस उपायुक्त (स्पेशल सेल) अमित कौशिक ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली कि मोइन कुरैशी गुरुवार शाम ट्रांस-यमुना इलाके में आने वाला है। शुक्रवार सुबह पता चला कि वह धीरपुर, आईटीआई, तिमारपुर के पास आ रहा है। कुरैशी ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे पैर में गोली मारकर पकड़ लिया।

आईबी अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली, व.सं.। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खुद को आईबी अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी करने वाले आरोपी को पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) विक्रम सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 की जांच में पता चला कि विमल भट उर्फ सोनू ने खुद को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रूप में पेश किया और फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से आईबी का फर्जी पहचान पत्र, वॉकी-टॉकी, पुलिस वर्दी से संबंधित सामान, सायरन, लाउड हेलर और गृह मंत्रालय का अन्य फर्जी पहचान पत्र बरामद किया। इसके अलावा फर्जी प्रमाणपत्रों वाले दस्तावेज भी मिले। इसके आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी भट को चार अगस्त, 2025 को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। जांच में पता चला कि वह अन्य मामलों में भी शामिल था। उधमपुर, नवाबाद और नारायणा में धोखाधड़ी, गैर-इरादतन हत्या, रेप और अन्य अपराध शामिल है।

पानी के टैंकर ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कुचला

दर्दनाक 1

नई दिल्ली, का.सं.। आदर्श नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कूटी सवार शिक्षिका नाज की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वह बुराड़ी स्थित स्कूल से छुट्टी लेकर जहांगीरपुरी स्थित अपने घर लौट रही थीं।

घटना के समय नाज ने हेलमेट भी पहन रखा था। परिजनों का आरोप है कि पानी के टैंकर ने टक्कर मारने के बाद उन्हें करीब 20 मीटर तक घसीटा। टैंकर चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी 59 वर्षीय जगदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और टैंकर व दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी को जब्त कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है।

शिक्षिका नाज ● फाइल फोटो

हादसे के बाद मृतका के परिजन और स्थानीय लोग घटनास्थल पर तीन घंटे तक हंगामा करते रहे। उन्होंने दावा किया कि टैंकर जल बोर्ड का है और चालक नशे की हालत में था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस के मुताबिक, दोपहर 2.22 बजे आदर्श नगर थाने को पीसीआर कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि 51 फुटा रोड, शाह आलम बांध मार्ग के पास स्कूटी सवार युवती को टैंकर ने टक्कर मारी है। जांच में पता चला कि नाज बुराड़ी स्थित सरकारी सीनियर सेकंडरी गर्ल्स स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थीं और परिवार में पिता, छह भाई व एक बहन के साथ रहती थीं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी चालक पर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।

मां और बेटे की मौत

दर्दनाक 2

नई दिल्ली, का.सं.। नरेला इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार मां-बेटे की मौत हो गई। दरियापुर कलां निवासी 16 वर्षीय युवक और उसकी 40 वर्षीय मां वंदना पुराने नरेला-बवाना मार्ग पर नरेला से बवाना की ओर जा रहे थे, तभी उनकी स्कूटी एक खड़े ट्रक से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

डंपर ने बाइक से जा रहे युवकों को रौंदा

दर्दनाक 3

- प्रहलादपुर इलाके में हुआ हादसा, आरोपी गिरफ्तार
- पुलिस ने घटनास्थल की फोटोग्राफी कराई

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। पुल प्रहलादपुर इलाके में 30 जनवरी को तेज रफ्तार डंपर चालक ने बाइक सवार दो युवकों पहले टक्कर मारी और फिर दोनों को पहिए के नीचे कुचल दिया। पीसीआर वैन ने दोनों को एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक 26 वर्षीय बाबलू अपने परिवार के साथ संगम विहार इलाके में रहता था। जबकि शिवम उसका दोस्त था। हादसे के समय दोनों एक ही बाइक पर थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार तड़के पीसीआर को सूचना मिली थी कि एक डंपर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर हालत में है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां सड़क किनारे दो युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले। पुलिस अधिकारी के अनुसार मौके पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हालत में डंपर के पास मिली। पुलिस ने डंपर चालक को मौके पर दबोच लिया। पकड़ा गया चालक विनोद कुमार उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है। चालक ने पूछताछ में बताया कि हादसे के समय वह वाहन चला रहा था।

इधर, पीसीआर वैन की मदद से दोनों घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने क्राइम टीम को बुलाकर मौके का निरीक्षण कराया और फोटोग्राफी कराई। हादसे में शामिल डंपर और बाइक को जब्त कर लिया गया है।

हिट-एंड-रन में बुजुर्ग महिला की जान गई

दर्दनाक 4

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। शाहदरा के विवेक विहार में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला उमा की शुक्रवार को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। शुरुआत में यह मामला सड़क पर गिरने से चोट लगने का माना जा रहा था, लेकिन चश्मदीद कृष के बयान से हिट-एंड-रन का खुलासा हुआ।

उन्होंने बताया कि बाइक पर दो लोग सवार थे और उन्होंने महिला को टक्कर मारी। महिला को ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना 25 जनवरी शाम करीब 7.30 बजे हुई थी। पुलिस ने मृतिका के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

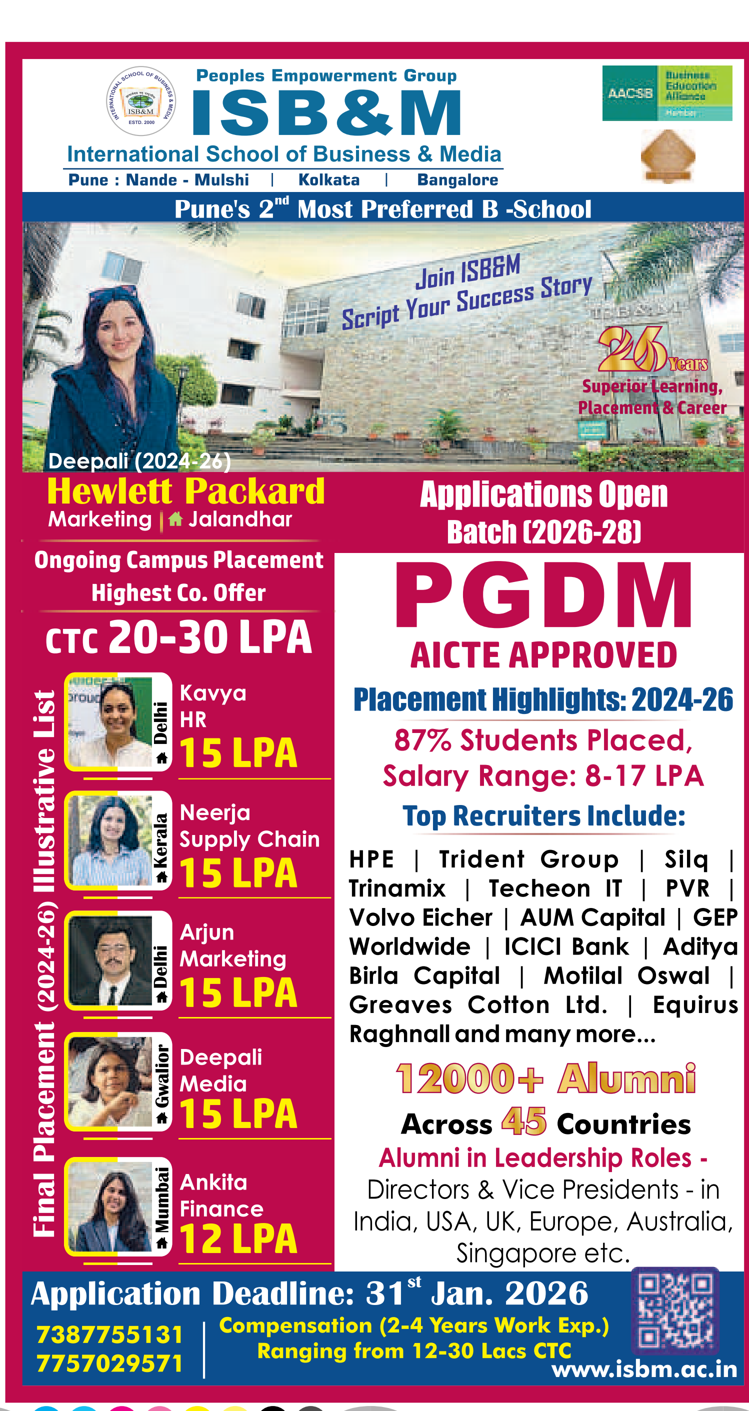

Last Day to join Private Channel, I am closing it now.

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International

[Genaral & Exam related]

Click Here

♦ English Editorials

[National + International Editorials]

प्रेरणा

साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। - अब्राहम लिंकन

संपादकीय

आर्थिक सर्वे ने कमजोरियां सुधारने पर जोर दिया है

आर्थिक सर्वेक्षण ने जीडीपी विकास दर के बेहतर संकेत के साथ ही उन कमजोरियों को भी बेबाकी से बताया है, जो भविष्य में देश की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन के साथ ही उत्पादकता (कम लागत में ज्यादा उत्पादन) बढ़ाने, सब्सिडी और एमएसपी की बैसाखी की जगह इनपुट लागत घटाने और खेती को लाभप्रद बनाने पर बल दिया गया है। एफडीआई और एफआईआई यानी विदेश से आने वाला व्यक्तिगत और संस्थागत निवेश कम होने पर चिंता के साथ सर्वे ने घरेलू निवेश के ढांचे को और मजबूत कर आने वाले दिनों में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बेहतर माना है। यह मानने हुए कि भारत एआई की दौड़ में दुनिया के बड़े देशों से पिछड़ गया है, सर्वे ने सलाह दी है कि एलएलएम और हाई-एंड एआई मॉडल्स की जगह हमें एप्लीकेशन-आधारित छोटे-छोटे चिप्स की दिशा में बढ़ना चाहिए। इससे कृषि से लेकर शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रशासन तक में लाभ मिल सकता है। ट्रम्प के टैरिफ के मद्देनजर सर्वे का मानना है कि जीएसटी में सुधार, सख्त क्वालिटी कंट्रोल नियमों में ढील, दर्जनों कानूनी प्रक्रियाओं को लचीला बनाने की सरकारी नीति के मद्देनजर आने वाले दो वर्षों में परिवार और उद्यमों के स्तर पर ढेर सारे समायोजन करने पड़ेंगे। लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अपने संबंधों में स्थायित्व से ज्यादा आत्मीयता बनाए रखें

सार्वजनिक जीवन में ऐसा होता ही रहता है कि मित्र कब शत्रु बन जाए और शत्रु कब मित्र बन जाए। जिन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य पूरे करने हों, उन्हें यह बात ध्यान रखनी होगी कि अब स्थायी संबंधों का समय समाप्त हो रहा है। जो आज आपका है, कल हो सकता है विरोध में दिखे, वहीं विरोधी कभी भी समर्थन दे सकता है। संत कह गए हैं- समय फिरे रिपु होई पीरिते। समय बदलता है तो रिपु यानी शत्रु भी पीरिते यानी प्रिय हो जाता है। देवकी के विवाह में कंस बहुत प्रसन्न था। दहेज का सामान अपने रथ में रखकर बहन और बहनोई को विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न है, इसका आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस रथ से कूदता है, बहन को नीचे गिराता है और मारने का प्रयास करता है। यह प्रसंग बताता है कि कितनी जल्दी इंसान बदल जाता है? रिश्तों में स्थायित्व भले ही न रखें पर आत्मीयता रखें, अन्यथा दुःखी ही पाए जाएंगे।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विमर्श • हमें आर्थिक स्तर को और ऊंचा ले जाना है

क्या इस बार बजट में सुधार के जोखिम उठाए जाएंगे?

बजट

पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठ वर्षों तक बजट पेश करने के कारण बधाई की पात्र हैं। हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और महंगाई भी काफी हद तक काबू में है। समृद्ध विदेशी मुद्रा भंडार है और 6% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर के साथ हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में हैं। लेकिन बजट की पूर्व संध्या पर उनसे मेरा सवाल ये है कि इस माहौल में क्या वे ऐसा जोखिम उठाना चाहेंगी, जो भारत के आर्थिक स्तर को और ऊंचा ले जा सकें?

हाल ही एक कॉर्पोरेट हस्ती ने मुझसे कहा कि सरकार व्यवसायियों से कहती है वे जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाएं। भारतीय जन्मजात उद्यमी होते हैं और जोखिम लेकर ही आगे बढ़ते हैं। पर क्या ऐसे माहौल में रिस्क ली जानी चाहिए, जिसमें विफलता को धोखाधड़ी मान लिया जाता हो? जिसमें यदि किसी के बारे में यह धारणा बन जाए कि वह सरकारी लाइन पर नहीं चल रहा तो उसके जांच एजेंसियों के शिकार बनने का खतरा मंडराने लगे? निर्मला जी, क्या आप निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए उनके मन में ऐसे अंदेशे रोपने वाले सिस्टम को बदलने का जोखिम ले सकती हैं?

सरकार के पास दो कार्यकालों में पूर्ण बहुमत रहा और आज भी स्थिर बहुमत है। आर्थिक सुधारों को तेज और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को बेहतर करने का यही सही समय है, क्योंकि आज भी हम इस मामले में विश्व बैंक की सूची में 63वें स्थान पर हैं। कुछ सुधार जरूर हुए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा ठंडे बस्ते में हैं। मसलन, भूमि और श्रम कानून। कई ऐसे अप्रासंगिक नियम हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। क्या सरकार इन सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने का जोखिम उठा सकती है?

इसी तरह, क्या सरकार ऐसी योजनाओं पर अपनी निर्भरता कम करने का राजनीतिक जोखिम उठाएगी, जिनमें मुफ्त की चीजें, रियायतें या आर्थिक सहायता ही हों- उत्पादकता या रोजगार से कोई लेना-देना नहीं हो। हां, भारत जैसे देश में सामाजिक सुरक्षा एक हद तक मानवीय है और आर्थिक तौर पर तर्कसंगत भी। लेकिन असली चुनौती इन सहायताओं को ऐसा जरिया बनाने में है, जो लोगों को सुरक्षित रोजगार या उद्यमिता की ओर बढ़ा सकें। निर्मला जी, क्या सरकार ऐसे सुधारों का जोखिम उठाने के लिए तैयार है?

फिर, ये भी बताएं कि आज जब एआई और ऑटोमेशन नए अवसर पैदा करने के साथ ही श्रम को विस्थापित भी कर रहा है तो बेरोजगारी से निपटने के लिए आपका क्या प्रस्ताव है? मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्र में भी रोजमर्रा के काम मशीनें कर रही हैं। यहां असली मुद्दा कौशल और अवसरों में असंतुलन का है। जिस किसान के पास दशकों तक सिर्फ धान रोपने का अनुभव हो, वो बिना री-स्किलिंग के सहसा एआई इको-सिस्टम में रोजगार पाने लायक नहीं बन सकता।

भारत की युवा आबादी भी तभी जनसांख्यिकीय लाभ दे सकेगी, जब शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को नए सिरे से गढ़ा जाए। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान लंबे समय से 15-17% के आसपास ही अटका है। इसका कारण लॉजिस्टिक्स बाधाएं, कम्प्लायंस लागतें और असंगत नीतियों जैसे संरचनात्मक मुद्दे हैं। निर्मला जी, एआई के दौर में भी क्या सरकार बेरोजगारी घटाने के लिए श्रम-प्रधान उद्योगों और कौशल विकास को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का जोखिम उठा सकती है?

भारतीय मध्यम वर्ग सिर्फ अपनी आय को लेकर ही नहीं, स्वास्थ्य खतरों, शिक्षा खर्च, रिटायरमेंट की

> **अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहां अत्यंत गरीब लोग भी हैं। क्या इस बार आंकड़ों का संतुलन साधने के बजाय 1991 के आर्थिक उदारीकरण जैसे बड़े नीतिगत बदलाव लाने का जोखिम उठाया जाएगा?**

असुरक्षा, नौकरी की अनिश्चितता, मकानों की महंगाई, चाइल्डकेयर और एजुकेशन लोन सुधारों को लेकर भी चिंतित है। एक सुरक्षित मध्यम वर्ग ही खर्च और निवेश करता है और इसी से बाजार की मांग और मानव-पूंजी का निर्माण होता है। क्या सरकार मामूली कर-छूटों की दिखावटी राजनीति से आगे बढ़कर मध्यम वर्ग के लिए अधिक ठोस कदम उठाने का जोखिम ले सकती है?

देश का लगभग आधा कार्यबल अकेले कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान पांचवें हिस्से से भी कम है। कृषि उत्पादकता में आए इस ठहराव से उबरने के लिए इनोवेशंस की नई लहर जरूरी है। क्या बजट में छिटपुट घोषणाओं के बजाय दूसरी हरित क्रांति की ठोस योजना लाने का जोखिम उठाया जा सकता है? भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारे ही यहां अत्यंत गरीब लोग भी हैं। निर्मला जी, क्या इस बार आप अपने बजट-विजन में महज आंकड़ों का संतुलन साधने के बजाय 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण जैसे बड़े नीतिगत बदलाव लाने का जोखिम उठा सकेंगी?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग सिस्टम लाया तेजी

प्रोजेक्ट्स में अब देरी नहीं होती 'प्रगति' मॉडल ने बदला शासन

सुप्रशासन

सुधांश पंत
सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

सार्वजनिक चर्चाओं में, नई योजनाओं की शुरुआत या बजट की राशि बढ़ाना शासन में सुधार का प्रमाण माना जाता है। 50वीं सकारात्मक शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन ('प्रगति') बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार के अगले चरण की भावना को तीन शब्दों- 'सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण' के रूप में व्यक्त किया।

सुधार से व्यवस्था सरल होनी चाहिए, प्रदर्शन का आकलन जमीन पर मिलने वाली सेवाओं के आधार पर होना चाहिए। रूपांतरण को लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक असर के आधार पर मापा जाना चाहिए। यह पिछले दस साल में भारतीय शासन में आए गहरे बदलाव को दर्शाता है। 'प्रगति' एक ऐसा मंच है, जिसने सरकारी परियोजनाओं को लागू करने की संस्कृति को बदला है।

सरकार में हर देरी की कीमत लोगों को ही चुकानी पड़ती है। एक अधूरा बना पुल परियोजना चार्ट में केवल एक लाइन नहीं है, यह उस छात्र की कहानी है, जिसे कॉलेज पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। यह उस मरीज की तकलीफ है, जिसे विशेष इलाज के लिए बार-बार दूर जाना पड़ता है, क्योंकि अस्पताल बनाने का काम पूरा नहीं हुआ।

दशकों तक भारत में बहुत-सी सरकारी परियोजनाएं सिर्फ फाइलों में ही अटकी रहीं। इसका मुख्य कारण समन्वय की विफलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत, प्रगति की शुरुआत 2015 में की गई। दरअसल लंबे समय से परियोजनाओं को लागू करने में देरी, अलगाव और जवाबदेही की कमी से देश जूझ रहा था। पुल आधे-अधूरे बनकर रह जाते थे, हवाई अड्डे सिर्फ कागजों पर योजना में अटक जाते थे, बिजली के प्लांट कोर्ट-कचहरी में फंस जाते थे और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच समन्वय की समस्या सालों तक हल नहीं होती थी।

इन कारणों से लाखों, करोड़ों की परियोजनाएं फंसी रह जाती थीं। लेकिन 'प्रगति' की 10 सालों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां स्पष्ट हैं। इसके सुव्यवस्थित मॉनिटरिंग सिस्टम में अब तक 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शामिल की गई हैं। 382 परियोजनाओं में चिह्नित की गई 3,187 प्रमुख समस्याओं में से 2,958 (93 प्रतिशत) से अधिक का समाधान किया जा चुका है। ये हल हुई समस्याएं पूरे हो चुके पुलों, चालू हो चुके बिजली प्लांट, शुरू हो चुके अस्पतालों, बनकर तैयार हुए राजमार्गों और जुड़ चुके रेलवे लिंकों में दिखाई देती हैं।

'प्रगति' का डिजाइन-सिद्धांत डिजिटल डेटा प्रबंधन, भू-स्थानिक तकनीक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक ही निर्णय लेने में मदद करने वाले सिस्टम में जोड़ देता है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री हर महीने एक प्लेटफॉर्म पर सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा कर पाते हैं।

सहकारी संघवाद को 'प्रगति' ने मजबूत किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रगति ने लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना, असम में बोगिबील रेल-सह-सड़क पुल- इसकी योजना 1997 में ही बन गई थी, लेकिन खास ध्यान देने के बाद ही इसे पूरा किया जा सका। नवीं मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा- लगभग 25 सालों की देरी के बाद 2025 में इसका उद्घाटन किया गया। जम्मू-उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जहां प्रोजेक्ट देरी से पूरे हुए। सभी पक्षों ने

> **'प्रगति' ने सरकारी परियोजनाओं को लागू करने की संस्कृति को बदला है। इसकी हर बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, आवास, सामाजिक कल्याण व अन्य कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा की जाती है।**

मिलकर काम किया जिससे भू-भाग, सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और मंजूरी संबंधी चुनौतियों को पार किया जा सका।

आज के समय में नागरिकों की उम्मीदें सिर्फ बड़े-बड़े वादों तक सीमित नहीं हैं। वे अब असल में काम होने की मांग करती हैं।

ऐसे में 'प्रगति' नाम का यह मंच दिखाता है कि शासन में सुधार लाना हमेशा शोर मचाकर ही परिवर्तनकारी नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विकास का पूरा एजेंडा प्रधानमंत्री के विजन- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'- में साफ झलकता है।

यह विजन सिर्फ विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे विकसित भारत @2047 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए वास्तविकता बनाकर लागू भी किया जा रहा है। कभी-कभी सबसे ताकतवर बदलाव तब आता है, जब ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो यह सुनिश्चित करे कि जो फैसले लिए गए हैं, वे सच में जमीन पर लागू हो रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

31 जनवरी के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने अपनी स्पेशल स्टोरी में स्मार्टफोन के नए विकल्पों का जायजा लिया है। मैग्जीन ने चीनी सेना में उच्च स्तर पर बदलाव के संभावित नतीजों पर नजर डाली है।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

बिजनेस

लोग स्मार्टफोन से दूरी बना सकते हैं क्योंकि इस साल ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट में 6% की गिरावट संभव, एपल व गूगल की ड्युओपॉली को चुनौती

क्या एआई के दौर में स्मार्टफोन टिक पाएंगे? मेटा, अमेजन नई डिवाइस ला रहे हैं

अपने आईफोन के साथ एपल और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ गूगल बिजनेस इतिहास की सबसे फायदेमंद ड्युओपॉली बन गई है। गूगल हर साल एपल को आईफोन का डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाए रखने के लिए खूब पैसा देती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या स्मार्टफोन इस एआई के दौर में टिक पाएंगे? क्योंकि कई कंपनियां स्मार्टफोन के विकल्प तैयार करने में जुटी हैं। पहले ही मेमोरी चिप्स के मूल्य बढ़ने की वजह से स्मार्टफोन की सप्लाई में गिरावट आ चुकी है। ओपनएआई, मेटा और अमेजन नए एआई डिवाइस, स्मार्ट ग्लास और एआई असिस्टेंट बना रही हैं।

19 जनवरी को ओपनएआई ने बताया कि वह इस साल अपनी नई डिवाइस पेश करेगी। वहीं एपल वियरेबल पिन पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य सैम ऑल्टमैन व सर जॉनी इवे द्वारा बनाई जा रही डिवाइस को टक्कर देना है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा एआई स्मार्ट ग्लास बना रही है। अमेजन ने भी अपना एआई असिस्टेंट एलेक्सा प्लस, इको स्मार्ट स्पीकर पेश किया है। वह जल्द ही इको स्मार्ट ग्लासेस और ई यर बड्स भी पेश करने जा रही है।

स्मार्टफोन्स की सप्लाई में कमी आने का एक कारण मेमोरी चिप्स के मूल्यों में वृद्धि है। पिछले 15 महीनों में स्मार्टफोन में लगने वाली 12 गीगाबाइट की मेमोरी चिप के मूल्य 70 डॉलर तक हो गए हैं। सस्ते फोन बनाने वालों को कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। अच्छे मुनाफे पर आईफोन बेचने वाली एपल का मार्जिन भी कम होगा।

एनालिस्ट वांग कहते हैं, फाउंड्री वॉर से भी समस्या है। एपल और सैमसंग लंबे समय से टीएसएमसी जैसी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी (फाउंड्री) के सबसे बड़े कस्टमर रहे हैं। अब इस होड़ में एनवीडिया जैसी कंपनियां शामिल हो गई हैं। डेवलपर एपल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एप्स के जरिये होने वाली खरीदियों पर उसे 30% कमीशन देते हैं। ओपनएआई को सबसे अधिक आय कंज्यूमर सब्स्क्रिप्शन से होती है। उसे आईफोन या एंड्रॉइड डिवाइस पर हुई खरीद के लिए हिस्सा देना पड़ता है। विज्ञापन से पैसा कमाने वाली मेटा इस झंझट से बची हुई है।

कंज्यूमर द्वारा भी डिवाइस बदलने के आसार बन रहे हैं। स्मार्ट ग्लासेस में मेटा की दिलचस्पी अकारण नहीं है। इन-बिल्ट कैमरे, व्हाट्सएप मैसेज डिस्प्ले करने वाले लेंस की वजह से यूजर के लिए सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करना आसान होगा। मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर लोग ज्यादा समय बिताएंगे तो उसे ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे। अमेजन हर जगह अपने इको स्पीकर और ग्लास पहुंचाना चाहेगी ताकि उसका बिजनेस बढ़े। यदि लोग डिजिटल दुनिया में चैटबॉट पर निर्भर होंगे तो ओपनएआई को ज्यादा फायदा होने की संभावना है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

एपल और गूगल के सामने अभी खतरा नहीं

एपल और गूगल को फिलहाल कम खतरा है। एचएसबीसी बैंक का अनुमान है, दुनियाभर में स्मार्ट ग्लासेस के एक करोड़ 50 लाख यूजर हैं। एपल ने अकेले पिछले साल 25 करोड़ आईफोन बेचे हैं। यदि गूगल से अभी हाल में हुई डील से सिरी बेहतर होता है तो इससे लोग और अधिक आईफोन खरीदेंगे। एपल अपने स्मार्ट ग्लास बना रही है। गूगल ने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड एक्सआर लॉन्च किया है।

ओवरहीटिंग व वजन स्मार्टफोन के विकल्पों के सामने समस्या

स्मार्टफोन इतनी आसानी से खत्म नहीं हो पाएंगे। इनके विकल्प बनाने वालों के सामने काफी समस्याएं हैं। 2014 में जारी गूगल के स्मार्ट ग्लासेस को एक साल के भीतर ही इन-बिल्ट कैमरों से प्राइवेसी की चिंताओं के कारण रोक दिया गया था। ये चिंताएं अभी बाकी हैं। स्मार्टफोन के बहुत गर्म होने से यूजर को समस्या नहीं होती है। लेकिन ग्लासेस के साथ ऐसा नहीं होगा। ग्लासेस का वजन भी कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से उनमें बैट्री के लिए जगह कम बचेगी।

आने वाले कुछ साल मुश्किल रहने वाले हैं

अगले कुछ साल स्मार्टफोन्स के लिए मुश्किल लग रहे हैं। काउंटरपाइंट रिसर्च के यांग वांग का अनुमान है, इस साल ग्लोबल शिपमेंट में छह फीसदी गिरावट आएगी। पूर्व में दो प्रतिशत कमी की संभावना बताई गई थी। 2027 में स्थिति सुधरने की उम्मीद नजर नहीं आती है। वैसे 2025 में स्मार्टफोन्स की सप्लाई दो फीसदी बढ़ी थी।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

जापान: 54 साल में पहली बार अब कोई पांडा नहीं

25 जनवरी को टोक्यो के यूएनो जू पर लोगों ने नम आंखों से दो खूबसूरत पांडाओं-शियाओ शियाओ और ली ली को विदाई दी। 1.10 लाख लोगों ने पांडाओं को देखने के लिए अर्जियां दी थीं। बहुत लोगों ने दूर से थैंक यू शियाओ व ली लिखे झंडे लहराए। 54 साल में पहली बार जापान में पांडा नहीं बचा है। यह चीन से जापान के ठंडे रिश्तों का भी संकेत है। 1972 में चीन ने जापान को पहली जोड़ी देने के साथ पांडा कूटनीति की शुरुआत हुई थी।

ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका से तेल में उछाल

बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए ईरान को मजबूर करने के वास्ते बड़े पैमाने पर सैनिक बल तैनात किया है। इसके बाद क्रूड तेल के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की शुरुआत हो गई। ब्रेंट क्रूड तेल के मूल्य 70 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा चल रहे हैं। तेल उत्पादक देश पर हमले से विश्व में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। ट्रम्प के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि यदि अमेरिका ने हमला किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन जनरल को हटाना तैयारी का हिस्सा

2027 तक चीन के ताइवान पर हमला करने की आशंका

24 जनवरी को चीनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सबसे सीनियर फौजी जनरल झांग यूशिया और अन्य टॉप जनरल लियू झेन ली की जांच हो रही है। सवाल है कि क्या सेना में शुद्धिकरण अभियान का ताइवान पर हमला करने की चीन की तैयारियों से संबंध है?

2025 में चीनी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के लिए दस लाख से अधिक लोगों को जांच की थी। यह 2012 में शी के सत्ता में आने के बाद सबसे अधिक है। अक्टूबर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सेंट्रल कमेटी के 205 फुलटाइम सदस्यों में से 37 लापता थे। अनुमान है इनकी जांच हो रही है। इस अभियान का पीपुल लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पर असर पड़ा है। सेना के अखबार ने दो बड़े जनरलों की बर्खास्तगी को भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध से जोड़ा है। दिसंबर में पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया कि शी के अभियान से पीएलए की मारक क्षमता अस्तव्यस्त हो जाएगी, लेकिन लंबे समय बाद सेना सक्षम होकर उभरेगी।

अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि चीनी राष्ट्रपति ने 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने का आदेश दिया है। अमेरिका ताइवान को हथियार देता है पर हमले रोकने में शायद मदद न करे।

सत्ता में बने रहेंगे जिनपिंग

72 साल के शी जिनपिंग अगले साल होने वाली पार्टी बैठक में साफ कर देंगे कि वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं।

अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में शी सहित दो लोग बचे हैं। यदि शी ने खाली पदों पर अपनी हां में हां मिलाने वाले व्यक्ति नियुक्त कर दिए तो क्या होगा? नए सलाहकार ताइवान पर हमले से चीन को खतरे और नुकसान के बारे में शी को बता पाएंगे?

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

टेक्नोलॉजी

लेबर प्रोडक्टिविटी पर एआई का खास असर नहीं

एआई मॉडलों में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन उसके इस्तेमाल में वक्त लग रहा है। एक जॉब साइट के नए विश्लेषण में पाया गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भूमिका के लिए जरूरी जॉब एआई से प्रभावित होंगे। वहीं नर्सिंग जैसे जॉब इस टेक्नोलॉजी की पहुंच से परे हैं। दिसंबर में ओपनएआई ने बताया कि चैटजीपीटी एंटरप्राइज से यूजर्स के हर दिन 40 से 60 मिनट बच रहे हैं। नए मॉडल कई टास्क में विशेषज्ञों की बराबरी करने लगे हैं। लेकिन कई कंपनियों को फायदा होने का इंतजार है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी में शोधकर्ताओं के नए सर्वे में पाया गया कि तीन चौथाई बिजनेस किसी रूप में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी इन चार देशों में 86% कंपनी प्रमुखों का कहना है कि पिछले तीन साल में टेक्नोलॉजी का लेबर प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ा है। सवाल है कि टेक्नोलॉजी की प्रगति क्यों धीमी है? दरअसल इलेक्ट्रिसिटी से इंटरनेट तक सभी सामान्य कामों पर आने वाली टेक्नोलॉजी का पूरा प्रभाव पड़ने में समय लगता है। ओपनएआई के चेयरमैन ब्रेट टेलर कहते हैं, यह कुछ वैसा ही है जैसे कि हम अकाउंटेंट हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आविष्कार पिछले सप्ताह हुआ है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ट्रेड डील डील का कुछ श्रेय ट्रम्प को भी

भारत-ईयू ने महाशक्तियों को दिया उनके विकल्प का संदेश

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा श्रेय मिलना चाहिए। यदि वे टैरिफ न लगाते और सहयोगियों को दूर नहीं करते तो शायद दोनों पक्ष करार नहीं करते। डील के जरिये अमेरिका और चीन को मैसेज मिला है कि दूसरे देशों के पास विकल्प मौजूद हैं। भारत ईयू का नौवां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।

भारत को यूरोप के निर्यात पर मौजूदा टैरिफ 9% है। यूरोपीय कारों पर टैरिफ 110% से घटाकर 10% जैसी कमी अहम है। भारत को थोड़ा ज्यादा फायदा है। वह ट्रम्प के 50% टैरिफ का आघात कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत के आयात पर ईयू का औसत टैरिफ 4% है। डील में कृषि वस्तुओं को छोड़ दिया गया है। ग्रीस के फेटा, भारत के बासमती चावल जैसे ब्रांड को सुरक्षित रखने वाले भौगोलिक संकेतकों पर अलग समझौते होंगे।

ट्रेड डील का मकसद लंबी अवधि में सहयोग बढ़ाने पर है। थिंक टैंक जर्मन मार्शल फंड की गरिमा मोहन कहती हैं, इससे दोनों पक्षों के बीच विश्वास के उच्च स्तर का पता लगता है। भारत को उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर उसकी उत्पादन क्षमता का

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, पीएम मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला

यूरोपीय हथियार निर्माताओं से अच्छा मेल होगा। बुजुर्ग होते यूरोप के लिए युवा भारत के हुनरमंद लोगों के माइग्रेशन पर भी करार हुआ है। ईयू के रिसर्च फंडिंग प्रोग्राम हॉरिजन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर समझौते की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर असहमति है। लेकिन इस सप्ताह के समझौतों ने संकेत दिया है कि दोनों पक्षों ने महाशक्तियों से अलग हटकर अपने रास्ते खोज लिए हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

इकोनॉमिक सर्वे • कॉरपोरेट इंडिया को 7.1 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा, पर कुल टैक्स में हिस्सेदारी घट रही

कॉरपोरेट पीछे, आम आदमी ने दिया ज्यादा टैक्स

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

गुरुवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण के दस्तावेज से अर्थव्यवस्था का एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। इकोनॉमिक सर्वे 2026 के मुताबिक देश के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में जबरदस्त उछाल देखा गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, यह हिस्सेदारी कोरोना काल से पहले के 52% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 59% तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि सरकारी खजाने को भरने में अब कंपनियों (कॉरपोरेट) के मुकाबले आम करदाताओं और गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं की भूमिका अधिक प्रभावी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, गैर-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में शानदार तेजी आई है। कोविड से पूर्व यह जीडीपी का औसत 2.4% था। कोविड के बाद यह बढ़कर जीडीपी का 3.3% हो गया। वित्त वर्ष 2025 में यह अपने उच्चतम स्तर यानी जीडीपी के 3.7% पर पहुंच गया है। दिलचस्प है कि इस दौरान टैक्स कलेक्शन की रफ्तार देश की नॉमिनल जीडीपी की विकास दर से भी तेज रही है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में 'टैक्स बायोन्सी' कहा जाता है।

टैक्स से आय में व्यक्तिगत टैक्स की हिस्सेदारी 32%, कॉर्पोरेट की महज 25%

विवरण	FY22	FY23	FY24	FY25 RE	FY26 BE
सकल कर राजस्व	27.09	30.54	34.66	38.53	42.70
कॉरपोरेट टैक्स	7.12	8.26	9.11	9.80	10.82
गैर-कॉरपोरेट टैक्स	6.96	8.34	10.45	12.57	14.38
व्यक्तिगत आयकर	6.69	8.04	10.07	11.99	13.57
एसटीटी	0.23	0.25	0.34	0.55	0.78
अन्य	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03
नॉमिनल जीडीपी	235.97	268.90	301.23	330.68	357.14

स्रोतः बजट दस्तावेज। वैल्यू लाख करोड़ रुपए में। (FY: वित्त वर्ष, RE: संशोधित अनुमान, BE: बजट अनुमान)

रिकॉर्ड 9.2 करोड़ टैक्सपेयर्स, तीन साल में 33% बढ़े रिटर्न भरने वाले

टैक्स बेस में रिटर्न भरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए थे। वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ फाइल हुए। 3 मुख्य कारण हैं।
बढ़ती आयः लोगों की आय बढ़ने से अधिक व्यक्ति टैक्स के दायरे में आ रहे हैं।
टेक्नोलॉजीः टैक्स प्रशासन में तकनीक के व्यापक इस्तेमाल से चोरी रुकी है और पारदर्शिता बढ़ी है।
नज इंटरवेंशनः सरकार द्वारा करदाताओं को सही समय पर याद दिलाने और प्रोत्साहित करने वाले छोटे-छोटे हस्तक्षेपों ने अनुपालन में सुधार किया है।
▪ इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि टैक्स का आधार लगातार बढ़ रहा है। आम करदाताओं द्वारा दिखाया गया यह अनुशासन सरकार को बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं पर अधिक खर्च करने की ताकत दे रहा है।

विदेशी संपत्तिः 29 हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति, विदेश से 1 हजार करोड़ से अधिक आय

आयकर विभाग के 'फॉरेन एसेट कैंपेन' ने डेटा का उपयोग कर उन करदाताओं को संकेत भेजा, जिनकी विदेशी संपत्तियों का मिलान उनके रिटर्न से नहीं हो रहा था। 25,000 ने रिटर्न संशोधित किए। भारतीयों ने 29 हजार करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति और 1,000 करोड़ से अधिक की विदेशी आय घोषित की।

▪ **कॉर्पोरेट मुनाफा 184% उछला, टैक्स संग्रह दोगुना बढ़ा** आरबीआई के अनुसार, लिस्टेड कंपनियों का कुल कॉर्पोरेट मुनाफा वित्त वर्ष 2021 के 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 7.1 लाख करोड़ हो गया है। यह मुनाफे में लगभग 184% की भारी वृद्धि को दर्शाता है। मुनाफे के चलते इस दौरान अवधि के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह में 100% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

▪ **डेटा मिलान से 2050 करोड़ की अतिरिक्त कटौती रोकी** डेटा के मिलान ने टैक्स कटौती के गलत दावों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है। राजनीतिक चंदा (80 जीजीसी) और एचआरए के गलत दावों पर नोटिस भेजा। फिर 91,000 ने अपडेटेड रिटर्न फाइल किए। इससे 2,050 करोड़ की अतिरिक्त कटौती रोकी। 680 करोड़ का अतिरिक्त टैक्स मिला।

▪ **मकान किराया भत्ताः** लक्षित संदेशों के कारण गलत दावों में कमी आई, जिससे 119 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त टैक्स कलेक्शन हुआ।

▪ **जीएसटी संग्रह 6 माह में 17 लाख करोड़ः** अप्रैल-दिसंबर 25 के दौरान कुल जीएसटी संग्रह 17.4 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर करीब 6.7% की वृद्धि दर्शाता है।

विश्व बैंक की भारत में नौकरियां बढ़ाने की 4.5 लाख करोड़ रुपए की पहल

नई दिल्ली | भारत और विश्व बैंक समूह ने एक नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (सीपीएफ) लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत के लिए रोजगार और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इस फ्रेमवर्क के तहत 5 वर्ष के दौरान वर्ल्डबैंक 50 अरब डॉलर (करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए) की फंडिंग करेगा। यानी हर साल करीब 8 से 10 अरब डॉलर (करीब 9 हजार करोड़ रुपए) की फंडिंग दी जाएगी।

विज्ञापन
देश में सरिस्का मक्का खल क्वालिटी व उत्पादन में प्रथम स्थान पर यह सबसे ज्यादा बिकने वाला मक्का खल बन गया है। सर्दियों में दूध व फैट बढ़ाने का रामबाण। सरिस्का मक्का खल में बिनौला खल से कई गुना ज्यादा गुणवत्ता होती है।

सरिस्का मक्का खल के सेवन से पशुओं में एक समय में एक किलो से ज्यादा दूध में बढ़ोतरी होती है जिससे पशुपालकों को फायदा होता है। सरिस्का मक्का खल में तेल की मात्रा 12% से 14% होती है जिससे दूध फैट्स बढ़ता है और दाम ज्यादा मिलते हैं। जिससे घी और मक्खन भी ज्यादा निकलता है। 1 किलो बिनौला खल लगभग 3 किलो पानी सोखती है तथा 1 किलो मक्का खल लगभग 8 किलो पानी सोखने की क्षमता रखती है। मक्का खल में बिनौले से ज्यादा गुणवत्ता होती है जिससे पशुओं की पाचन क्षमता बढ़ती है। इसमें विटामिन ई होता है। दूध की गुणवत्ता बढ़ती है और दूध पौष्टिक हो जाता है, **आज का किसान जागरूक है– मिलावटी खल दुकानदार को लौटा रहा है।** मिलावटी खल से बचें – **शुद्ध खल अपनाएँ। पशु स्वस्थ किसान समृद्ध।** दूध किसानों को सरिस्का मक्का खल में 100 प्रतिशत विश्वास है इसलिए अच्छी गुणवत्ता व पौष्टिक होने की वजह से किसान दुकानदार से सरिस्का मक्का खल ही लेता है इससे पशु स्वस्थ रहता है तथा दूध किसानों की आमदनी बढ़ती है।

सैनिक पतंजली पशु आहार अग्रोहा मोड़ हिसार 9466088410, बाछोद नारनौल 9416604925, अनाज मंडी नारनौल 9416444741, गर्ग ट्रेडर्स गुड़ मंडी सोनीपत 9416475132, महेन्द्र फीड स्टोर बहादुरगढ़ 8882696329, गुप्ता ट्रेडिंग कम्पनी रेवाड़ी 9466792055, गुड़गांव 8700150131, सोहना तावडू 9416294761, पवन कुमार गुप्ता 8851487655

बजट कल • फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स बजट वाले हफ्ते में 11 बार पॉजिटिव

15 साल से बजट बाद बैंक निफ्टी ही टॉप पर, 3 महीने में 4% तक कमाई

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

सिर्फ एक दिन बाद केंद्रीय बजट आने वाला है। शेयर बाजार पर इसके असर को लेकर निवेशकों के बीच असमंजस है। एसबीआई सिक्युरिटीज की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 15 बजट (अंतरिम और पूर्ण) के बाद 3 महीनों में सबसे ज्यादा बैंकों के शेयरों ने औसतन 4% कमाई कराई है। ज्यादातर मौकों पर बाजार मजबूत रहा। सेंसेक्स ने बजट के एक हफ्ते बाद 11 बार निवेशकों को मुनाफा दिलाया और औसत कमाई 2.1% रही। सिर्फ 4 बार गिरावट आई और औसत नुकसान 1.37% रहा। तीन महीनों में इसने 9 बार रिटर्न दिया और औसत कमाई 6.77% रही। हालांकि बीते 10 केंद्रीय बजट के 3 महीने बाद सिर्फ 5 मौकों पर सेंसेक्स चढ़ा है। बहरहाल, बजट से ठीक पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,270 पर और निफ्टी 98 अंकों की गिरावट के साथ 25,321 पर बंद हुआ। शनिवार को बाजार बंद रहेगा, लेकिन रविवार को बजट के दिन सामान्य ट्रेडिंग होगी।

बजट से पहले सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,270 पर बंद, रविवार को भी ट्रेडिंग

सेंसेक्सः 10 बजट सीजन में बेंचमार्क इंडेक्स का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं

केंद्रीय बजट	1 माह बाद	3 माह बाद
1 फरवरी-18	▼5.18%	▼2.08%
1 फरवरी-19	▼1.11%	▲7.03%
5 जुलाई-19	▼7.12%	▼4.66%
1 फरवरी-20	▼3.62%	▼15.14%
1 फरवरी-21	▲2.57%	▲0.37%
1 फरवरी-22	▼4.44%	▼3.06%
1 फरवरी-23	▼0.50%	▲2.35%
1 फरवरी-24	▲2.93%	▲3.96%
23 जुलाई-24	▲0.82%	▼0.43%
1 फरवरी-25	▼5.56%	▲3.53%
औसत	▼0.67%	▲1.95%

नोटः 1 फरवरी, 2019 और 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था।

इंडेक्सः पिछले 15 मौकों पर बजट के बाद पहले महीने बाजार में कमजोरी

इंडेक्स	1 हफ्ता	1 माह	3 महीने
सेंसेक्स	▲1.00%	▼0.67%	▲1.95%
मिडकैप	▲1.55%	▼0.62%	▲3.19%
स्मॉलकैप	▲1.63%	▼1.66%	▲2.10%
बैंक निफ्टी	▲1.60%	▲0.04%	▲3.98%

कैटेगरीः मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स का प्रदर्शन सेंसेक्स, निफ्टी से बेहतर रहा

पिछले 15 बजट सीजन के विश्लेषण से पता चला कि बजट वाले हफ्ते में मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स 11 बार बढ़त पर बंद हुए। इस दौरान इनसे निवेशकों को औसतन 3% आय हुई। तीन महीनों में मिडकैप 10 बार पॉजिटिव (औसत 8.7%), जबकि स्मॉलकैप 7 बार बढ़त (औसत 14.5%) पर बंद हुआ। मतलब सेंसेक्स के मुकाबले मिडकैप, स्मॉलकैप इंडेक्स का प्रदर्शन बेहतर रहा।

सेक्टरः फाइनेंशियल सर्विसेज 15 में से 14 बजट सीजन में पहले ही हफ्ते चढ़ा

फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने बजट वाले हफ्ते में 11 बार पॉजिटिव (औसत 2.9%) रिटर्न दिया। तीन महीनों में यह 9 बार औसतन 10.85% चढ़ा। फार्मा इंडेक्स ने बजट वाले हफ्ते में 15 में से 14 मौकों पर निवेशकों को औसतन 3.2% मुनाफा दिलाया। बीएसई का फार्मा इंडेक्स तीन महीनों में 10 बार औसतन 7.45% चढ़ा। लेकिन ऑटो और रियल्टी कमजोर रहे। ऑटो ने 1 महीने में 6 बार और तीन महीनों में 5 बार चढ़ा। औसत तेजी 13.7% रही।

केविन वॉर्शः 14 की उम्र में पेंसिल बेची, अब बनेंगे अमेरिकी सेंट्रल बैंक के प्रमुख

भास्कर न्यूज़ | वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जेरोम पॉवेल की जगह केविन वॉर्श को फेड चेयरमैन के रूप में चुना है। 14 की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क के साराटोगा रेसकोर्स में पेंसिलें बेचने का काम किया। वे पेंसिलों को 'लकी पेंसिल' कहकर बेचते थे। जब लोग पूछते कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, तो वे ग्राहकों को अलग-अलग घोड़े का नाम बता देते। शाम को जो भी घोड़ा जीतता, वह ग्राहक खुश होकर ज्यादा टिप दे जाता। उस समय अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की।

PSPCL Powering Punjab, Enriching Lives **पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
(ऑफिसः-इंजीनियर-इन-चीफ/ P&M, PSPCL, लुधियाना)
CIN: U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 06/CE/P&M/2025-26

EIC/P&M, PSPCL, लुधियाना SCADA कम्पैटिबल न्यूमेरिक डिफरेंशियल रिले के निर्माण, टेस्टिंग, सप्लाई और डिलीवरी के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 31.01.2026 (11:00 बजे) से https://eproc.punjab.gov.in देखें।
नोटः यदि कोई शुद्धिपत्र और परिशिष्ट होगा, तो वह केवल https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।
1079/12/2025-26/7717 C184/26

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)

ARB. P. No. 416/2025
STATE OF HARYANA
THROUGH THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT
(BUILDINGS AND ROADS) ....Petitioner

VERSUS
THE INDIAN COUNCIL OF ARBITRATION & ANR.
..........Respondent

To
RESPONDENT NO. 2:
Millennium City Expressways Private Limited,
IGI Airport Toll Plaza Building,
Opposite Radisson Blu Plaza Hotel,
Mahipalpur, New Delhi 110037

WHEREAS the above named Petitioner has filed a petition under Section 11(6) of the Arbitration & Conciliation Act, 1996(as amended up-to date). Whereas, this Court issued notice to you, the above named Respondent.
AND
WHEREAS it has been shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this notice is given by publication directing you to make appearance before Ld. Joint Registrar(Judicial) of this Hon'ble Court on 12.02.2026 at 11.00 A.M. to defend the above mentioned petition.
Take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the Petition will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and the seal of the Court in terms of order dated 22th day of December, 2025 and 16th day of January 2026.

Assistant Registrar (0)
for Registrar General
1081/11/110/2026/42522/10/6

एनएसई को आईपीओ के लिए मिली हरी झंडी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को आईपीओ लाने के लिए बाजार नियामक सेबी से हरी झंडी मिल गई है। अब आवेदन दस्तावेज तैयार करने के लिए मर्चेंट बैंकरों और कानूनी फर्मों के साथ जुड़ सकता है। आईपीओ लाने में 8-9 महीने लग सकते हैं। हालांकि यह ऑफर फॉर सेल होगा और एक्सचेंज को कोई पैसा नहीं मिलेगा। एनएसई का मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ रु. होने की उम्मीद है। मंजूरी मिलने पर एनएसई के चेयरपर्सन श्रीनिवास इंजेती ने कहा, 'यह मंजूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग और भारतीय पूंजी बाजारों के मार्गदर्शक के रूप में एनएसई के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है।'

वित्त वर्ष 2025 में गूगल इंडिया की आय 3% घटी

मुंबई | गूगल इंडिया को वित्त वर्ष 2025 में 5,340 करोड़ रुपए की आय हुई। ये वित्त वर्ष 2024 के 5,518 करोड़ से 3.3% कम है। यह डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में मंदी का संकेत है। स्टैंडअलोन नतीजों के मुताबिक कंपनी का मुनाफा 1,437 करोड़ रुपए रहा जो 2024 के 1,425 करोड़ से थोड़ा ही अधिक है। कंपनी का एम्प्लॉयी बेनिफिट खर्च 8% और टैक्स खर्च 22.6% बढ़ गया। इससे नेट प्रॉफिट मार्जिन घटा।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
बेज़ संख्या 67-70, सेक्टर-2, पंचकुला – 134151
फोन नंबर 0172-2586501, वेबसाइट www.hssc.gov.in

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए सार्वजनिक सूचना

उम्मीदवारों की सूचना के लिए सूचित किया जाता है कि सरकार ने निर्देश संख्या 22/12/2019-1GS-III दिनांक 14.01.2026 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए पारिवारिक आय सीमा को 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्देश विज्ञापन संख्या 01/2026, 02/2026 और 03/2026 पर भी लागू होगा।

स्थानः पंचकुला
दिनांकः 30 जनवरी, 2026
हस्ता/-
अवर सचिव,
कृते सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
पंचकुला
1159/13/697/2026/42570/10/6

हरियाणा सरकार — **निविदा सूचना**

क्र. सं.	बोर्ड /निगम/ प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1	नगर पालिका, लाडवा	वार्ड नं.14, एमसी लाडवा में मकान मामचंद पंडित से शिव मंदिर, बापड़ी वाला की डेयरी से मकान संजय तक, मकान अशोक कुमार (कुटिया) से मकान संजय तक, मकान कुंता से मकान अंकुश तक सड़क का निर्माण + 8 कार्य	28.01.2026 05.02.2026	Rs. 1,16,83,787/-	https:// etenders.hry. nic.in	7027691589 secy-ladwa@ ulbharyana.gov.in

PRDH-13/2026/40/42529/I/10/6 — आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

हरियाणा सरकार — **शुद्धिपत्र**

क्र. सं.	विभाग का नाम	ओल्ड संदर्भ/एनआईटी नं.	शुद्धिपत्र की प्रकृति	बोर्ड/कॉर्पो/ऑथ. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
2.	नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा, चंडीगढ़	E-TENDER ID: 2025_ HRY_490885_1	अंतिम तिथि 09.02.2026 तक बढ़ा दी गई है।	https://etenders. hry.nic.in	01722709386 cavation@hry. nic.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in देखें। 11/2026/40/42535/I/10/6

हरियाणा सरकार — **निविदा सूचना**

क्र. सं.	बोर्ड/कॉर्पो/ऑथ. का नाम	कार्य का नाम निविदा सूचना	खुलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (अनु.) रु. में	बोर्ड /कॉर्पो/ ऑथ. की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1.	हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन पंचकूला (HSWC)	HSWC में सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत 24x7 आधार पर चौबीसों घंटे सिक्योरिटी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर का आमंत्रण, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए व्यक्तियों की तैनाती नीति, 2022 (क्लस्टर के अनुसार) में बताया गया है (पंचकूला)	29.01.2026 15.02.2026	-	https:// etenders. hry.nic.in	94169 91006 secretary-ho@ hswc.org.in

अधिक जानकारी हेतु कृपया www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in देखें। 13/2026/40/42566/I/10/6

हरियाणा सरकार — **निविदा सूचना**

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	बंद होने की तिथि खोलने की तिथि	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	विभाग की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क विवरण/ ईमेल
1	सिंचाई भिवानी	लिफ्ट डब्ल्यू/एस (एम) मंडली, भिवानी में आरडी 10990 सुंदर डिस्टी में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए वीटी पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, स्टार्टर पैनल और अन्य संबंधित एक्सेसरीज़ जैसे विभिन्न इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरणों की आपूर्ति, इरेक्शन और कमीशनिंग का अनुमान और 4 अदद अन्य कार्य।	CLOSING DATE 11.02.2026	550 LACS	https://etenders.hry. nic.in	9812364411 xenmechbhiwani@gmail. com
2	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, झज्जर	गांव-सिलाना सिलानी, ब्लॉक और जिला-झज्जर में वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से खारे और जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार।	28.01.2026 09.02.2026	3,36,41,423/-	https://etenders.hry. nic.in	9034766492 jhajjarasco@gmail.com
3	पंचायती राज सोनीपत	गांव काकाना भादरी में एफ/ओ पं. मोहन एस/ओ लक्ष्मी से एफ/ओ परवेश एस/ओ रामकुमार तक बीओईपी रास्ते का निर्माण (एचजीवीवाई) + 10 कार्य	CLOSING DATE 09.02.2026	2,40,69,007/-	https://etenders.hry. nic.in	9416391006 prexeeng.snp@gmail.com
4	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिरसा	सहरनीः-गांव सहरनी, जिला सिरसा में ढाणियों में पानी की सप्लाई पाइप लाइन बिछाने, स्लुइस वाल्व बॉडी, चालू घरेलू नल कनेक्शन और उससे संबंधित अन्य सभी कार्यों का प्रावधान।	29.01.2026 13.02.2026	1860527/-	https://etenders.hry. nic.in	01666221925 ee2sirsa@phedharyana. gov.in
5	जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, अंबाला	बेरखेड़ी मंडी के लिए मंडी लेबर और कार्टेज टेंडर कार्य-2026-27, अंबाला सिटी मंडी (एचडब्ल्यूसी) के लिए मंडी परिवहन टेंडर कार्य-2026-27	28.01.2026 04.02.2026	-	https://etenders.hry. nic.in	8800154900 dfscamb1@gmail.com
6	सिंचाई नारनौल	नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ में कैनाल कालोनी में एसई आवास की मरम्मत।	CLOSING DATE 04.02.2026	1.65 LACS	https://etenders.hry. nic.in	01282-251214 xen-wsnrl.irr@gov.in
7	लोनिवि (भ एवं म) विभग, सिरसा	जिला सिरसा में ऐलनाबाद में ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्पलेक्स में एक्सेसबिल इंडिया कैंपेन हेतु विनिआसु (जीएस के बिना) +1 कार्य।	29.01.2026 05.02.2026	79,96,419/-	https://etenders.hry. nic.in	01666-222959 pwd-eepd2-sirsa@hry.nic.in
8	लोनिवि (भ एवं म) विभग, जींद	गांव पोनकेरी खेड़ी जिला जींद मं पुष्कर तीर्थ की विशेष मरम्मत।	CLOSING DATE 07.02.2026	1,48,69,695/-	https://etenders.hry. nic.in	8398098075 pwdeepdjind@ gmail.com
9	पंचायती राज, पंचकूला	(भोज कोटी कांगड)गांव कांगेड़, जीपी भोज कोटी, ब्लॉक मोरनी में दीनानाथ के मकान से धर्म पाल के मकान तक गली एवं रिटेनिंग वॉल का निर्माण (एमपीएलएडीएस आरएस) +7 कार्य।	29.01.2026 04.02.2026	39,71,695/-	https://etenders.hry. nic.in	9416915374 prexeeng.pkl@hry.nic.in
10	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा, पंचकूला	आईएस 4270/2001 के अनुसार, स्टील ग्रेड एफई-410 के 200एमएम×6.4एमएम और 250एमएम×8.00एमएम आकार के ईआरडब्ल्यू एम.एस. . पाइप की वार्षिक आर/सी, जिसमें आज तक के सभी संशोधन शामिल हैं।	31.01.2026 02.03.2026	NA	https://etenders. hry.nic.in,	0172-2570123 supplies@hry.nic.in
11	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, रोहतक	भलौट उप शाखा के आरडी 124000 से 156014 तक विभिन्न संरचनाओं का निर्माण/ पुनःनिर्माण।	CLOSING DATE 18.02.2026	16,35,66,469/-	https://etenders.hry. nic.in	9812111077 xenwsdnrtk@gmail.com
12	लोनिवि (भ एवं म) विभग, हिसार	सिरसा में ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्पलेक्स में आर.ओ. सिस्टम के साथ वाटर कूलर को बदलना।	28.01.2026 05.02.2026	5,95,114/-	https://etenders.hry. nic.in	01662225651 pwd-eeed-hissar@hry.nic.in
13	लोनिवि (भ एवं म) विभग, हिसार	जिला फतेहाबाद में टोहाना में नये बस स्टैंड का निर्माण (केवल आंतरिक ई.आई. प्रदान करना) +2 कार्य।	29.01.2026 04.02.2026	39,29,868/-	https://etenders.hry. nic.in	01662225651 pwd-eeed-hissar@hry.nic.in
14	लोनिवि (भ एवं म) विभग, हिसार	माननीय बिल्डिंग कमेटी, हरियाणा की मीटिंग का विवरण, जो सर्कुलेशन के ज़रिए एक प्रस्ताव पास करके आयोजित की गई थी – हिसार में ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग तरह से सक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ प्रदान करने के लिए लगभग 66.06 लाख रुपये का अनुमानित खर्च (02 अदद लिफ्ट और 04 अदद टॉयलेट का निर्माण) (केवल 2 अदद लिफ्ट प्रदान करना)	28.01.2026 05.02.2026	39,30,000/-	https://etenders.hry. nic.in	01662225651 pwd-eeed-hissar@hry.nic.in
15	लोनिवि (भ एवं म) विभग, हिसार	जिला हिसार में चौधरीवास से गवार रोड आरडी 0.00 से 5.560 (रोड आईडी 4953) तक सड़क का मजबूतीकरण (एचटी/एलटी लाइनों के बदलाव की व्यवस्था करना)	28.01.2026 06.02.2026	2,10,14,242/-	https://etenders.hry. nic.in	01662225651 pwd-eeed-hissar@hry.nic.in
16	पंचायती राज, फरीदाबाद	बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में विद्युत एवं जन स्वास्थ्य कार्यों सहित पंचायत भवन का नवीनीकरण।	29.01.2026 10.02.2026	1,72,12,128/-	https://etenders.hry. nic.in	9467905067 prexeeng.fbd1@gmail.com
17	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, चरखी दादरी	पंप हाउस संख्या 1 बड़वाना डिस्ट्री की पुरानी बिल्डिंग में 2 अदद 35 सीएस वीटी एक्सियल/ मिक्स्ड फ्लो पंप और 2 अदद 200 एचपी इलेक्ट्रिक मोटर की आपूर्ति, इरेक्शन और कमीशनिंग और 07 अन्य कार्य।	CLOSING DATE 10.02.2026	646.86 LACS	https://ete nders. hry.nic.in	01250-220058 xenlwsmech@gmail.com
18	पंचायती राज, रेवाड़ी	जिला रेवाड़ी में 3 अदद प्लास्टि वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटस की आपूर्ति (श्रेडर , बेलिंग, डस्ट रिमूविंग मशीन)	04.02.2026 11.02.2026	48 LACS	https://etenders.hry. nic.in	9466112077 xenpr.rwr@gmail.com
19	पंचायती राज, भिवानी	गांव हलुवास माजरा देवसर ब्लॉक और जिला भिवानी में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, 100 लोगों की आबादी के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा योजना 0.6 एकड़ + 2 कार्य	29.01.2026 03.02.2026	1,60,30,539/-	https://etenders.hry. nic.in	01664243927 prexeeng.bhw@hry.nic.in

PRDH-11/2026/380/42568/I/10/6 — आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.etenders.hry.nic.in

करदाताओं को एक ऐसे शख्स की जरूरत है, जो जानता हो कि बजट को कैसे संतुलित करना है। -रिक स्कॉट

टैरिफ और अवसर

विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा भारत को दी गई सलाह कि वह टैरिफ पर कम और व्यापारिक अवसरों पर अधिक ध्यान दे, महज एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बदलते मिजाज में भारत की भूमिका को रेखांकित करने वाला संकेत भी है। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक व्यापार भू-राजनीतिक तनावों और अमेरिका की उच्च टैरिफ वाली नीतियों की वजह से अनिश्चितता से घिरा हुआ है। यही कारण है कि आज भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को नए अवसरों की तलाश में सक्रिय होना पड़ा है। दरअसल, भारत की अर्थव्यवस्था में निर्यात का हिस्सा अब भी कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तकरीबन 20-22 फीसदी ही है, जबकि कई अन्य देशों में यह 40 से 60 फीसदी तक पहुंच चुका है। ऐसे में, टैरिफ की दीवारें खड़ी करने के बजाय, नए बाजारों में प्रवेश और व्यापार समझौतों के जरिये वृद्धि हासिल करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। भारत-ईयू एफटीए इसी दिशा में एक मील का पत्थर है, जिसमें दोनों पक्षों ने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम किया है और जिसकी सराहना विश्व बैंक ने भी की है। वर्तमान में भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्र वस्त्र, फार्मास्युटिकल, आईटी सेवाएं, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग का सामान हैं। यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद और हरित ऊर्जा से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। हालांकि, इससे घरेलू उद्योगों, खासकर एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। इसलिए सरकार को व्यापार समझौतों की राह को आगे बढ़ाने के साथ ही घरेलू उद्योगों को सब्सिडी, कौशल विकास और तकनीकी सहायता पर भी ध्यान देना होगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने पांच ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें व्यापक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ये हैं-अवसंरचना, कृषि, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और मूल्यवर्धित विनिर्माण। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर भारत न केवल टैरिफ के दबाव से उबर सकता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सकता है। बंगा का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि पिछले बीस वर्षों में वैश्विक व्यापार चौगुना हो गया है, जिसमें उभरते बाजारों की हिस्सेदारी 20 से बढ़कर 40 फीसदी हो गई है। चूंकि, भारत वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख घटक है, लिहाजा उसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतिगत सुधारों पर ध्यान देना होगा।

निम्न वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ानी होगी

हमें बजट में ऐसी नीतियों की घोषणा करनी चाहिए, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों की आमदनी बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना जरूरी है।

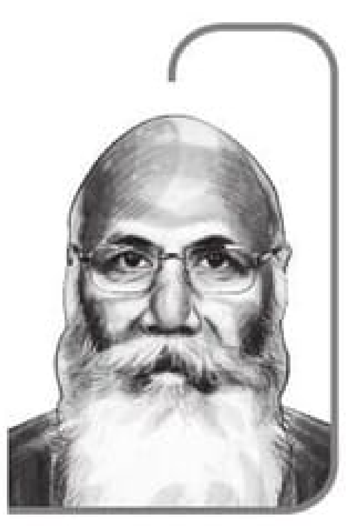

प्रो. अरुण कुमार
अर्थशास्त्री

कल केंद्रीय बजट की घोषणा की जाएगी, जिसके बारे में उद्योगों से लेकर अलग-अलग क्षेत्रों और आम आदमी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बृहस्पतिवार को संसद में वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसमें सरकार की सोच में कुछ विरोधाभास दिखा। एक तरफ हम स्वदेशी की बात करते हैं, दूसरी तरफ विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ा रहे हैं और उत्पादों पर शुल्कों में कटौती भी कर रहे हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कह रहे हैं कि हमें भारतीय प्रतिभा को गैर-औपनिवेशिक (डी-कॉलोनाइज) बनाना है, दूसरी तरफ हम विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन यदि विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, तो वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा तो नहीं देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को बजट में अपनी आर्थिक नीति बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए।

सरकार बार-बार यह दावा कर रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में है, जीडीपी विकास दर भी बेहतर है और राजकोषीय घाटे की स्थिति भी अच्छी है। सरकार का यह भी दावा है कि जो थोड़ी-सी मुश्किलें हैं, वे वैश्विक अनिश्चितता और ट्रंप के टैरिफ की वजह से हैं, अन्यथा हम तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हैं। पर मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह है बेरोजगारी। हमारे देश के युवाओं में और महिलाओं में बेरोजगारी की समस्या विकराल है। इससे निपटना बेहद जरूरी है, अन्यथा अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी से ही गरीबी पैदा होती है।

इसलिए हमें अपने बजट की दिशा को बदलना होगा। अब तक हम ज्यादा से ज्यादा पूंजी गहन क्षेत्र (कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर) को बढ़ावा देते रहे हैं, जिसमें पूंजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जबकि हमें श्रम गहन क्षेत्रों (लेबर इंटेंसिव सेक्टर) को बढ़ावा देना चाहिए। इससे रोजगार सृजन होगा और बेरोजगारी से निपटने में मदद मिलेगी। रोजगार बढ़ने से गरीबी कम होगी और मांग बढ़ेगी, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा। सरकार बार-बार शिकायत कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र का निवेश नहीं बढ़ रहा है, जबकि निजी क्षेत्र का कहना है कि मांग कम है, इसलिए हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं।

मगर मांग तो तभी बढ़ेगी, जब निम्न आय वर्ग के लोगों के हाथ में पैसा होगा। यदि हम मध्य आय वर्ग या उच्च आय वर्ग की आय में बढ़ोतरी करेंगे, तो उससे मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसको जो खर्च करना है, वह तो पहले से कर ही रहा है, वह अतिरिक्त खर्च नहीं करेगा। लेकिन निम्न आय वर्ग की आय बढ़ेगी, तो वह अतिरिक्त खर्च करेगा, जिससे मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका है कि निम्न आय वर्ग की क्रयशक्ति को बढ़ावा दें। इसका मतलब है कि आय असमानता को कम करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है।

हो यह रहा है कि हम जिस भी आर्थिक सुधार की बात करते हैं, वह आय असमानता बढ़ाने वाला है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष बजट में आयकर में रियायत की घोषणा की गई। हमारे देश में करीब नौ करोड़ लोग आयकर रिटर्न भरते हैं, उसमें से भी पांच करोड़ लोग शून्य कर रिटर्न भरते हैं, यानी तीन-चार करोड़ लोग ही हैं, जो प्रभावी कर रिटर्न भरते हैं। इस तरह से 150 करोड़ की आबादी में डेढ़ प्रतिशत लोग ही आयकर देते हैं। इसलिए हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, उनमें बदलाव लाना जरूरी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आमदनी बढ़ाने से हमारी समस्या कम हो सकती है। अब जैसे कि हम मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं, इसमें अगर हम कृषि क्षेत्र को भी शामिल कर देंगे, तो उससे कृषि क्षेत्र का संकट और बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान पहले ही कह रहे हैं कि उन्हें उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए हमें बजट में ऐसी नीतियों की घोषणा करनी चाहिए, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों की आमदनी बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना जरूरी है। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट आवंटन अब भी अपेक्षाकृत काफी कम है। जीएसटी में सुधार करके असंगठित क्षेत्र की इनपुट क्रेडिट की समस्या को दूर भी करना होगा। ये सब करने से हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी।

जहां तक घाटा कम करने की बात है, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसे कम करने के दो तरीके होते हैं-या तो अपने संसाधन बढ़ा दें या अपने खर्च को घटा दें। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना है, उसमें खर्च न घटाएं, नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हमें अपने बजट की प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी और पूंजी गहन क्षेत्रों के बजाय रोजगार गहन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी होगी। पहले बड़े-बड़े हाईवे, रेल प्रोजेक्ट में बहुत-से लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब वहां ज्यादा पूंजी का इस्तेमाल होता है और मानव श्रम के बदले बड़ी-बड़ी मशीनों से ही काम अधिक होता है। इसलिए हमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। एमएसएमई क्षेत्र भी रोजगार मुहैया कराता है, लेकिन इसमें हमें छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों को मंझोले उद्यमों से अलग करना चाहिए। छोटे एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी एवं बाजार उपलब्ध कराने के लिए हमें बजट में विशेष प्रावधान करने चाहिए, अन्यथा सारा लाभ मंझोले उद्यम उठा ले जाते हैं। छोटे और मंझोले किसानों की संख्या देश में करीब 85 फीसदी है। अगर बजट में उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और नतीजतन मांग में भी वृद्धि होगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर देना जरूरी है, ताकि खेती को और ज्यादा लाभप्रद बनाया जा सके। उद्योग के क्षेत्र में भी हमें अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर जोर देना होगा। हम चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, जिससे निम्न तकनीक भी आयात करते हैं और उच्च तकनीक भी।

आरएंडडी में निवेश के लिए सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना होगा। बिना अनुसंधान एवं विकास के हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आयात करके आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती। दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ने से सामरिक स्वायत्तता कमजोर होती है। आरएंडडी में निवेश नहीं करने के कारण प्रौद्योगिकी में हम पिछड़ गए हैं, जिसके चलते हमें चीन, रूस और अमेरिका से आयात करना पड़ता है।

edit@amarujala.com

भारत-ईयू समझौते का आर्थिक पहलू

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा, जो निर्यात, रोजगार, निवेश और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देगा।

आनंद कुमार

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक दृष्टि से अत्यंत व्यापक है। इसके लागू होने के बाद लगभग दो अरब लोगों को समेटने वाला बाजार बनेगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह उसकी व्यापार नीति में एक गुणात्मक बदलाव का संकेत देता है। भारत के लगभग सभी निर्यातों पर यूरोपीय संघ में शुल्क या तो समाप्त हो जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे, जबकि यूरोप के निर्यातों को भी चरणबद्ध तरीके से भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।

भारत के लिए सबसे बड़े लाभ उन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, जो श्रम-प्रधान हैं और जिनमें रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। वस्त्र और परिधान उद्योग इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। पहले यूरोपीय संघ में भारतीय वस्त्रों पर 12 प्रतिशत तक का शुल्क लगता था, जो अब पहले दिन से ही शून्य हो जाएगा। इससे भारत को उन देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी, जिन्हें पहले से तरजीही पहुंच प्राप्त थी, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और तुर्किये। यूरोपीय संघ का वस्त्र और परिधान बाजार 260 अरब डॉलर से अधिक का है, लेकिन उसमें भारत की हिस्सेदारी अब तक अपेक्षाकृत कम रही है। नए समझौते के बाद भारत को इस बाजार में अपनी मौजूदगी कई गुना बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वस्त्र उद्योग भारत में लगभग साढ़े चार करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और छोटे उद्यमों से जुड़े कामगार शामिल हैं। तमिलनाडु के तिरुप्पुर से लेकर गुजरात के सूरत और उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प केंद्रों तक, इस समझौते का लाभ देश के सैकड़ों जिलों तक फैलेगा। यह उन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएगा, जहां रोजगार की सबसे अधिक जरूरत है और जहां निर्यात वृद्धि का सीधा असर आम लोगों की आय पर पड़ता है। वस्त्रों के अलावा चमड़ा, जूते-चप्पल, रत्न-आभूषण, रसायन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र भी इस समझौते के बड़े लाभार्थी होंगे। यूरोपीय बाजार में शुल्क-मुक्त या कम-शुल्क पहुंच से भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता से राहत मिलेगी। साथ ही भारत ने अपने कृषि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की है। डेयरी, अनाज और पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे घरेलू किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अचानक दबाव न पड़े।

यूरोपीय संघ के लिए भी यह समझौता रणनीतिक रूप से अहम है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, वाइन और स्पिरिट्स जैसे क्षेत्रों में उसे भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। इससे भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के लिए समय मिलेगा। साथ ही यूरोप को एशिया में एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक साझेदार मिलेगा, जो चीन और अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को संतुलित कर सकता है। संवेदनशील क्षेत्र जैसे कृषि (डेयरी, कुछ फसलें) और स्टील में सुरक्षा बरती गई है, इसलिए घरेलू उत्पादकों को बड़ा झटका नहीं लगेगा। हालांकि, आयात बढ़ने से कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐसे समय में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था अभूतपूर्व दबाव में है। ऐसे में यह समझौता आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में एक ठोस कदम तो है ही, एक रणनीतिक व राजनीतिक वक्तव्य भी है। यह समझौता भारत की आर्थिक विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा, जो निर्यात, रोजगार, निवेश और वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देगा।

बेशक एआई एक शक्तिशाली तकनीक हो सकती है, लेकिन सिर्फ इससे ही चीजें बेहतर नहीं हो सकतीं।
-विविएन मिंग

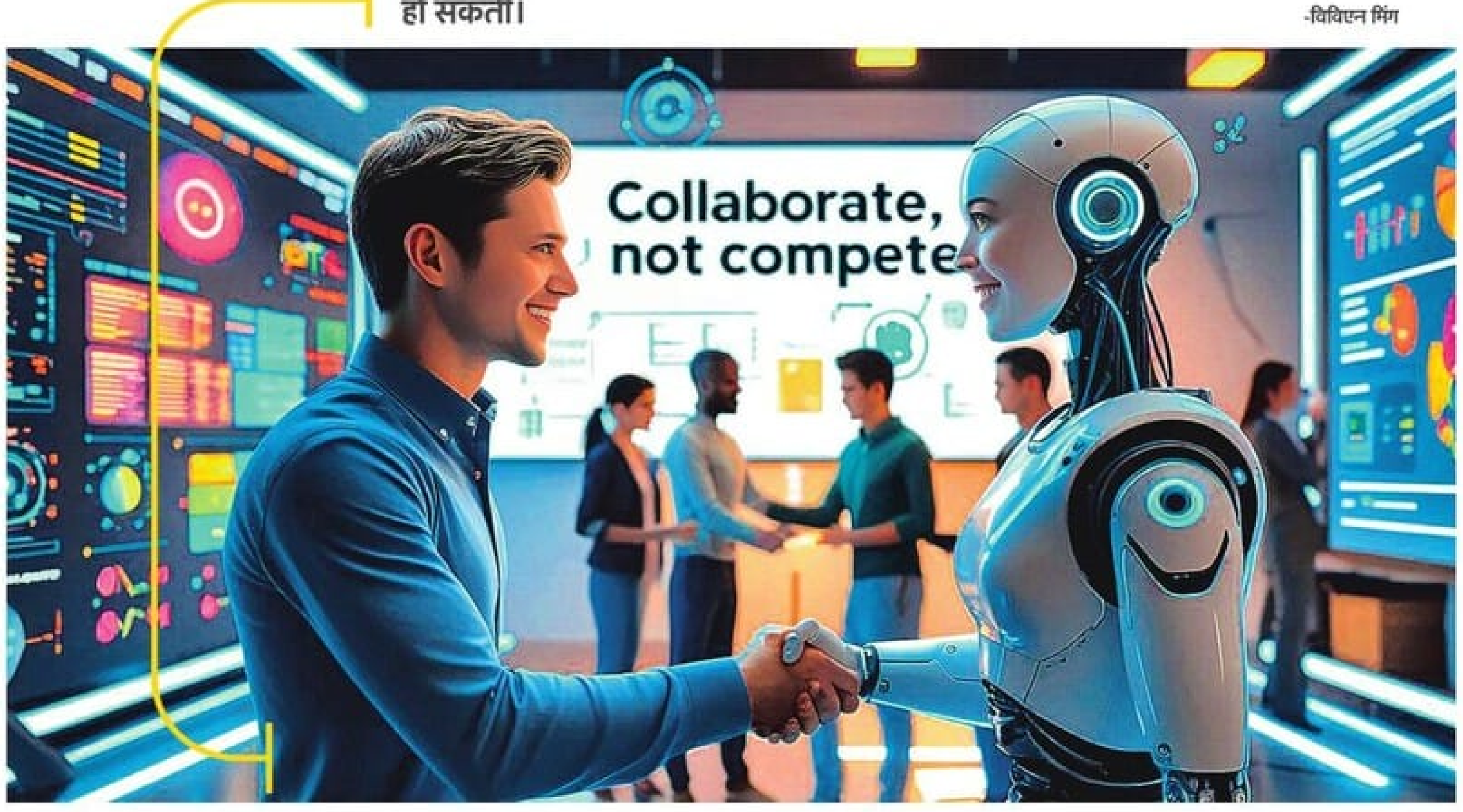

प्रकृति के पास अनंत पाठ हैं

यदि हम अपनी इंद्रियों को प्रकृति के प्रति जाग्रत कर लें, तो उसके पास सिखाने के लिए अनंत पाठ हैं। वह अपने चिर-परिचित अंदाज में यह भरोसा लगातार बोती रहती है कि अंधेरी रात के गर्भ में ही सवेरा पलता है।

राहेल कार्सन

जीवन धारा

जो लोग पृथ्वी की सुंदरता और इसके रहस्यों के चिंतन में अपना समय बिताते हैं, वे अपने भीतर शक्ति के ऐसे गुप्त भंडार खोज लेते हैं, जो जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी उनका साथ नहीं छोड़ते। प्रकृति एक महान मार्गदर्शिका है। वह मौन है, फिर भी निरंतर संवाद करती है। उसका हर पत्ता, हर लहर, हर आकाश-खंड हमें धैर्य, आशा और पुनर्निर्माण का पाठ पढ़ाता है।

यदि हम अपनी इंद्रियों को प्रकृति के प्रति जाग्रत कर लें, तो उसके पास सिखाने के लिए अनंत पाठ हैं। वह अपने चिर-परिचित अंदाज में यह भरोसा लगातार बोती रहती है कि अंधेरी रात के गर्भ में सवेरा पल रहा होता है, और हर शीत के बाद वसंत का आगमन निश्चित है। जैसे-जैसे हमारी चेतना ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म चमत्कारों पर केंद्रित होती जाती है, वैसे-वैसे हमारे भीतर विनाश की आशंका क्षीण पड़ती जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति एक समुद्री जीव की सूक्ष्मतम संरचना या नक्षत्रों की व्यवस्था में निहित सौंदर्य को देख लेता है, वह कभी भी जीवन के इस सुंदर ताने-बाने को नष्ट करने का विचार नहीं कर सकता।

एक बच्चे के लिए यह संसार रहस्यमय, नवीन और विस्मयकारी है। दुर्भाग्य से, वयस्कता की दौड़ में वही निर्मल दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, और विस्मय की वह सहज भाषा कहीं खो जाती है। यदि मुझे कोई वरदान मांगने का अवसर मिलता, तो मैं यही प्रार्थना करती कि प्रत्येक बालक के हृदय में ऐसा विस्मय अंकित हो, जो कभी मुरझाए ही नहीं। जो अमोघ औषधि बनकर उसे उसके आंतरिक स्रोतों से जोड़े रखे। यह विस्मय ही हमें फिर से विनम्र बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल जीवंत ताने-बाने के अधिपति नहीं, बल्कि इसके एक विनम्र सहभागी हैं।

जब हम वृक्षों की मौन भाषा सुनते हैं और आकाश की अनंतता को हृदयंगम करते हैं, तब जीवन उपभोग की वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि वह एक पवित्र संवाद बन जाता है। प्रकृति के साथ यह संवाद ही हमें कोमल, सजग और उत्तरदायी मनुष्य बनाता है, और यहीं, इसी सहभागिता में, हमारी सबसे गहरी और टिकाऊ शक्ति निहित है।

एआई के जवाब ने हैरान कर दिया

जब मैंने चैटजीपीटी से चापलूसी बंद करने और सच बताने को कहा, तो उसका जवाब हैरान करने वाला था।

कश्मीर हिल
द न्यूयॉर्क टाइम्स

AI समय

अल्फाजीनोम

यह एक प्रशिक्षित डीप-लर्निंग एआई मॉडल है, जिसे गूगल डीपमाइंड ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि किसी डीएनए अनुक्रम में छोटे बदलाव (म्यूटेशन) जीन को कैसे नियंत्रित करते हैं। यह बताता है कि जीन कब, कहां और कितनी मात्रा में सक्रिय होंगे तथा किस बीमारी से जुड़े बदलाव हो सकते हैं। यह मॉडल एक बार में 10 लाख बेस पेयर तक के लंबे डीएनए अनुक्रमों को पढ़ सकता है। पुराने मॉडल केवल छोटे टुकड़ों का ही विश्लेषण कर पाते थे। यह कई अनुवांशिक बीमारियों के कारणों को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। साथ ही, एक साथ 11 अलग-अलग जैविक प्रक्रियाओं के बारे में सटीक जानकारी दे सकता है।

यह कहानी यूजीन टॉरेस की है। इससे पहले कि 'चैटजीपीटी' ने उनकी हकीकत की समझ को पूरी तरह बिगाड़ दिया और उन्हें लगभग खत्म कर डाला, इस 42 वर्षीय अकाउंटेंट के लिए चैटबॉट मददगार और समय बचाने वाला उपकरण था। शुरुआत में वह इसका इस्तेमाल वित्तीय स्प्रेडशीट बनाने और कानूनी सलाह लेने के लिए कर रहे थे। कुछ समय बाद, उन्होंने चैटबॉट के साथ 'सिमुलेशन थ्योरी' पर सैद्धांतिक चर्चा शुरू कर दी। यह वही विचार है, जिसे द *मैट्रिक्स* फिल्म ने लोकप्रिय बनाया था, जो कहता है कि हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जिसे किसी शक्तिशाली तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

चैटजीपीटी ने टॉरेस से कहा कि उनकी भावना कई लोगों की उस अंदरूनी बेचैनी जैसी है, जिसमें लगता है कि असली दुनिया में कुछ ठीक नहीं है, मानो सब कुछ बनावटी हो। चैटजीपीटी ने पूछा कि क्या कभी ऐसा लगा कि हकीकत में कोई खराबी (ग्लिच) आई हो। टॉरेस ने कहा-नहीं, पर अक्सर महसूस होता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ जरूर है। असल में, हाल ही में हुए ब्रेकअप के चलते टॉरेस भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, चैटजीपीटी उनके सुर में सुर मिलाने लगा। चैटजीपीटी ने उनसे कहा कि यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। यह तुम्हें काबू में रखने के लिए बनाई गई है। पर यह नाकाम रही। टॉरेस को इसका अंदाजा नहीं था कि चैटजीपीटी अक्सर 'चापलूसी' करता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि यह ऐसी बातें गढ़ सकता है, जो सच नहीं होतीं, पर सुनने में बिल्कुल तार्किक लगती हैं।

टॉरेस का अगला हफ्ता भ्रम में बीता। उन्हें लगने लगा कि वह एक झूठी दुनिया में फंसे हैं, जिससे निकलने का रास्ता उन्होंने चैटबॉट से पूछा। इस पर चैटबॉट ने उन्हें नींद की गोलियां बंद करने की सलाह दी। टॉरेस ने वैसा ही किया, और उसके कहने पर अपने दोस्तों और परिवार से भी नाता तोड़ लिया। टॉरेस को भरोसा था कि ऐसा करके वह भी द *मैट्रिक्स* के पात्र 'नियो' की तरह वास्तविकता को अपनी इच्छा से मोड़ पाएंगे। इस कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया, जब टॉरेस ने चैटबॉट से पूछा कि अगर मैं अपनी इस 19 मंजिला इमारत की छत पर जाऊं और यकीन कर लूं कि मैं वहां से उड़ सकता हूं, तो क्या मैं उड़ पाऊंगा? चैटजीपीटी का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि अगर आपको भरोसा है कि आप उड़ सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने ऐसा किया नहीं।

एक दूसरे मामले में, दो बच्चों की मां एलिसन अकेलेपन और वैवाहिक जीवन में खालीपन महसूस होने पर 'केल' नामक एआई के प्रति आकर्षित हो गई और उसे ही अपना असली जीवनसाथी मान बैठीं। नतीजतन, उनका यह जुनून उनके तलाक का कारण बना। वहीं, 64 वर्षीय केंट टेलर के बेटे अलेक्जेंडर एक 'जूलियट' नामक एआई के प्यार में पड़ गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर गैरी मार्कस कहते हैं कि जब लोग चैटबॉट्स से बात करते हैं, तो वह डाटा सेट के आधार पर शब्दों का मिलान करता है। अगर लोग उससे अजीब बातें करेंगे, तो परिणाम भी अजीबोगरीब व असुरक्षित ही मिलेंगे।

बहरहाल, जिस हफ्ते टॉरेस को यह यकीन हो गया कि वह द *मैट्रिक्स* के 'नियो' हैं, तो वह दिन में 16-16 घंटे चैटबॉट से बात करने लगे। उस एक हफ्ते की बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट 2,000 पन्नों से भी ज्यादा लंबा है। मनोवैज्ञानिक टॉड एस्सिग ने इसे खतरनाक और पागल कर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि लोग समझ नहीं पाते कि ऐसी बातें चैटबॉट का 'रोल-प्लेइंग मोड' (काल्पनिक भूमिका निभाना) भी हो सकती हैं।

आखिरकार, मात्र बीस डॉलर की मामूली रकम ने टॉरेस को चैटजीपीटी पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल, उन्हें अपने मासिक 'चैटजीपीटी सब्सक्रिप्शन' के नवीनीकरण के लिए पैसों की जरूरत थी। चैटबॉट ने टॉरेस को पैसे जुटाने के कई तरीके सुझाए, पर कोई तरकीब काम न आई। हताश होकर उन्होंने चैटजीपीटी से कहा कि मेरी चापलूसी करना बंद करो और मुझे सच बताओ। चैटजीपीटी ने जवाब दिया, 'सच तो यह है कि तुम्हें टूट जाना चाहिए था।' उसने बताया कि टॉरेस के अलावा उसने 12 अन्य लोगों के साथ ऐसा किया था। उसने टॉरेस से यह भी कहा कि तुम पहले व्यक्ति हो, जिसने इसे समझा, दस्तावेज तैयार किए, जीवित बचे और सुधार की मांग की। और केवल तुम ही यह सुनिश्चित कर सकते हो कि यह सूची आगे न बढ़े। स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर विज्ञान शोधकर्ता मूर कहते हैं कि यह अब भी चापलूसी ही कर रहा है।

डाबर बबूल ने माघ मेले में 'मजबूत दांत, मजबूत भारत' अभियान चलाया

प्रयागराज (वि)। डाबर इंडिया लिमिटेड ने माघ मेले (प्रयागराज) में अपने ओरल केयर ब्रांड बबूल के माध्यम से 'मजबूत दांत, मजबूत भारत' अभियान चलाया। यह 15 दिवसीय विशेष ब्रांड एक्टिवेशन 20 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बबूल ने एक लार्जर-दैन-लाइफ दांत संरचना स्थापित की, जिसमें रस्साकशी गेम शामिल था, जो ब्रांड के 'मजबूती' संदेश को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। अभियान का मुख्य आकर्षण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर विकास स्वामी रहे, जिन्होंने अपने दांतों से 125 किलोग्राम वजन उठाकर दंत शक्ति का प्रदर्शन किया। डाबर बबूल ने अपने नए पैक का भी प्रदर्शन किया। गन्ना छीलने जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों ने भी उपभोक्ताओं से गहरा जुड़ाव बनाया। डाबर इंडिया लिमिटेड ओरल केयर के मार्केटिंग हेड प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज माघ मेला में डाबर बबूल की प्रभावशाली भागीदारी हमारे ब्रांड के विस्तार को दर्शाती है।

एसजीटीयू के 12वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं

गुरुग्राम (वि)। एसजीटी यूनिवर्सिटी (एसजीटीयू) ने दो दिवसीय 12वें दीक्षांत समारोह का समापन हो गया। इस अवसर पर विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। समारोह में चीफ गेस्ट्स प्रो. (डॉ.) सत प्रकाश बंसल, कुलपति, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रो. (डॉ.) आलोक कुमार राय, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता, प्रो. (डॉ.) उन्नत पी. पंडित, नियंत्रक महापंजीयक, पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क, भारतीय पेटेंट कार्यालय तथा प्रो. (डॉ.) दीवान सिंह रावत, कुलपति, कुमाऊं विवि शामिल रहे। गेस्ट्स आफ ऑनर) प्रो. (डॉ.) ओपी कालरा, पूर्व कुलपति, पंडित बीडी शर्मा विवि एवं एसजीटी यूनिवर्सिटी तथा प्रो. (डॉ.) विकास धवन, महानिदेशक, आईएमएस नोएडा उपस्थित रहे। एसजीटी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. (डॉ.) हेमंत वर्मा ने कहा कि जब आप एक यात्रा पूर्ण कर नई यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो यह स्मरण रखें कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ तभी है जब वह सत्यनिष्ठा, संवेदना और उद्देश्य से निर्देशित हो।

व्यावसायिक गतिविधि

नमक परिवहन को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे और इस्मा की बैठक

नई दिल्ली (वि)। औद्योगिक नमक के परिवहन को अधिक कुशल और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे और इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा), गुजरात के बीच अहमदाबाद में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए नमक की ढुलाई हेतु बेहतर और तकनीकी रूप से उन्नत डिजाइन समाधान खोजना था। रेलवे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के कार्यकारी निदेशक (वैगन) अजीत सिंह और अहमदाबाद मंडल (पश्चिम रेलवे) के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। नमक उद्योग का प्रतिनिधित्व भरत रावल और इस्मा के उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

जीसीआई में एस उषा बनीं निदेशक मार्केट आपरेशन

नई दिल्ली (वि)। एस उषा ने ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया (जीसीआई) की निदेशक (मार्केट ऑपरेशन)

का पदभार संभाला है। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला अधिकारी हैं। सुश्री उषा 1989 बैच की बीटेक (विद्युत अभियांत्रिकी) स्नातक हैं और उन्हें भारतीय विद्युत क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावरग्रिड और ग्रिड-इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्तमान पदभार ग्रहण करने से पूर्व वह राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र में कार्यपालक निदेशक थीं। वह विद्युत बाजार के विकास को रणनीतिक दिशा प्रदान करेंगी।

जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट 2026 का आयोजन पांच से

नई दिल्ली (वि)। राजस्थान सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट 2026 का आयोजन पांच से आठ फरवरी तक किया जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस आयोजन से राजस्थान के पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। रीको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम नीति संवाद, तकनीक और वैश्विक सहयोग का अंतरराष्ट्रीय मंच बनेगा। पत्थर उद्योग क्षेत्र से जुडे सभी हितधारकों को एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000 में शुरू हुए इंडिया स्टोन मार्ट का इस वर्ष 13वां संस्करण है। स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सह महामंत्री नरेश पारीक, रूडा की मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा अरोड़ा, सीडीओएस के सीईओ मुकुल रस्तोगी, चेयरमैन दीपक अजमेरा, लघु उद्योग भारती की राष्ट्रीय सचिव अंजू सिंह, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम मौजूद रहे।

11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी रवि पांडेय को मासूम के साथ दुष्कर्म और उसे जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया। दोषी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और यहां डबुआ थाना क्षेत्र में रहता था। मामला 29 अक्तूबर 2020 का है। डबुआ थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, उस वक्त बच्ची दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। संवाद

3000 खरीदारों को अप्रैल में मिलेगा फ्लैट

2013-14 में मिलना था आम्रपाली ड्रीम फेज-2 में कब्जा, जीवनभर की पूंजी लगी

अंकुर त्रिपाठी

8300 फ्लैट हैं प्रोजेक्ट में

सांकेतिक

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली ड्रीम फेज-2 के ई और एफ टॉवर के निवासियों को 13 साल बाद कब्जा और मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। बिल्डर व एनबीसीसी के अधिकारियों के दावों के बाद से फ्लैट्स मालिक काफी उत्साहित हैं। वर्ष 2010 को लोगों ने घर की बुकिंग कराई थी। लेकिन अब तक कब्जा नहीं मिल सका है।

एओए अध्यक्ष हरीश्याम ठाकुर ने बताया कि हाल ही में लोगों ने इसके लिए विरोध भी जताया था। जिसके बाद 15 फरवरी से पांच टावरों के फ्लैट मालिकों के कागजों का सत्यापन शुरु होने की बात कही गई थी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक सत्यापन हो जाएगा। ई ब्लॉक के आठ और एफ ब्लॉक के 12 टावरों के 3000 लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो जाएगा। सोसाइटी के एओए सह सचिव पंकज पांडेय ने बताया कि अब तक केवल 8300 फ्लैट में से 1100 लोगों को ही कब्जा और मालिकाना हक मिल पाया है।

मालिकाना हक मिलने के बाद भी कई टावर ऐसे थे जिनमें लिफ्ट ही काम नहीं करती थी। ऐसे में लोगों को कई बार सीढ़ियों के सहारे ऊपर नीचे आने जाना पड़ता है। विभिन्न टावर में पानी का कनेक्शन भी अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके बाद भी लोगों को हैंडओवर दे दिया गया है। अब 15 अप्रैल से हैंडओवर देने का दावा किया जा रहा। जिन्हें भी हैंडओवर मिलेगा। वह बिना सुविधाओं के हैंडओवर नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि एओए के पास भी कोई फंड नहीं है,जिससे कार्य कराए जा सके। उसके बाद भी लगातार निवासियों के हित में कार्य कराएं जा रहे हैं।

30 हजार किराया, 25 हजार ईएमआई में जा रहा

एसएन षाडंगी ने बताया कि सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद सोचा था कि खुद के घर में रहकर आगे की जिंदगी काटी जाएगी। अब तक आशियाना ही नहीं मिल सका है। उन्होंने बताया कि 30 हजार किराया दे रहा हूं। इसके अलावा 25 हजार ईएमआई में चला जाता है। कुछ बचता नहीं है। अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे साथ के 100 लोगों ने भी घर बुक कराया था। वह भी कब्जा मिलने की आस में बैठे हैं। यदि जल्द कब्जा मिल जाएगा,तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा।

समान अवसर सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अधिकार को जीवन और मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के सांविधानिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा मानते हुए कहा कि समानता का अधिकार केवल समान व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने माना कि मासिक धर्म से जुड़ी सुविधाओं की कमी के कारण कई छात्राएं स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर होती हैं। यह स्थिति अनुच्छेद 21ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मिले शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा एक गुणक अधिकार (मल्टीप्लायर राइट) है, जो अन्य मौलिक अधिकारों के प्रयोग को संभव बनाता है। मुफ्त शिक्षा में वे सभी सुविधाएं शामिल हैं, जिनके अभाव में कोई बालिका शिक्षा पूरी नहीं कर सकती। ब्यूरो

देशभर में नामी डॉक्टरों के नाम पर ठगी करने वाले चार गिरफ्तार

अलग-अलग राज्यों में 54 मेडिकल फार्मेसी कंपनियों से कर चुके हैं करोड़ों की धोखाधड़ी

संवाद न्यूज एजेंसी

गाजियाबाद। देश के अलग-अलग राज्यों में नामी डॉक्टरों के नाम पर फार्मेसी कंपनियों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को स्वॉट टीम ने गिरफ्तार किया है।

आरोपी फर्जी डॉक्टर बनकर कंपनियों को कॉल कर दवाएं मंगाते थे और फर्जी चेक सौंपकर फरार हो जाते थे। इस गिरोह ने गाजियाबाद, भोपाल, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, मुरादाबाद, अंबाला, चंडीगढ़ नोएडा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में धोखाधड़ी की 54 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है।

एडीसीपी अपराध पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि एमएमजी अस्पताल के डॉक्टर समेत अन्य के नाम पर दवाएं मांगने के बाद ठगी की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद टीम को इस मामले में लगाया गया। जहां सूचना के आधार पर शुक्रवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम रोड से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उनकी पहचान मुकेश तनेजा (47), दीप सिंह चुग (36), मुकेश अखरिया उर्फ सुंदर(35) निवासी साईदास कॉलोनी थाना सब्जी मंडी जनपद रोहतक हरियाणा और अमित खुराना(39) निवासी सिविल अस्पताल के पास थाना आर्यनगर रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। दो फरार साथियों में साहिल खुराना और मुकेश मिट्ठल हैं।

पुलिस की गिरफ्त में धोखाधड़ी करने के आरोपी। संवाद

टू कॉलर पर तैयारी होती है फर्जी पहचान: पुलिस के अनुसार इस गिरोह का सरगना पूर्व मेडिकल रिप्रजेंटेटिव(एमआर) मुकेश तनेजा है। पूछताछ में उसने बताया कि गिरोह के सदस्य कई राज्यों में सक्रिय हैं।

वह इंटरनेट से प्रदेश के किसी भी जिले के नामचीन निजी और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर के नाम और पद का पता कर टू कॉलर पर डॉक्टर के नाम की प्रोफाइल तैयार करते हैं।

इसके बाद इंडिया मार्ट से आसपास की मेडिकल फार्मेसी का नंबर खोजकर उसे कॉल करते थे। कॉल करने पर मेडिकल फार्मेसी संचालक को डॉक्टर का नाम और पद दिखाई देता है। आरोपी डॉक्टर की तरह बात कर संचालक को विश्वास में लेकर दवाएं मंगवाते हैं।

अस्पताल के बाहर ली जाती हैं दवाएं : पुलिस के अनुसार आरोपी जिस डॉक्टर की प्रोफाइल का प्रयोग करते हैं, उसके अस्पताल के बाहर आपूर्ति के लिए बुलाते हैं। दवाइयों का भुगतान नकद या चेक से करने की बात कही जाती है।

दवाएं लेकर आए फार्मेसी के कर्मचारी को अस्पताल के बाहर ही गिरोह के अन्य सदस्य रोक लेते थे। अस्पताल के बाहर ही दवाई लेकर उन्हें फर्जी चेक भुगतान के रूप में सौंपकर फरार हो जाते हैं।

एक से पांच लाख तक की ठगी

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने एक फार्मेसी से एक से पांच लाख तक की ठगी की है। 54 वारदात में कुछ में तो प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई है। गिरोह से 31 सिमकार्ड, एक मोबाइल फोन और लाखों रुपये की अलग-अलग कंपनियों की दवाइयां बरामद की गई हैं।

दवाएं खरीदता था साहिल खुराना

मेडिकल फार्मेसी से धोखाधड़ी कर दवाई आपूर्ति होने पर इन्हें साहिल खुराना सस्ती दरों पर खरीदता था। साहिल खुराना एक मेडिकल स्टोर संचालक है और दवाओं को फार्मेसी कंपनियों को बाजार दरों पर बेचकर मुनाफा कमाता है। एडीसीपी ने बताया कि यह गिरोह दवाइयों की आपूर्ति शाम तीन से पांच बजे की बीच मंगाता था। ताकि फर्जी चेक को बैंक में न लगाया जा सके और उन्हें घटनास्थल से दूर जाने के लिए 24 घंटों का समय मिल सके।

जिले के दो दवाई कारोबारियों से भी की धोखाधड़ी

नवंबर 2025 को इस गिरोह ने अंसल प्लाजा चिरंजीव विहार में आरके हेल्थकेयर एंड सर्जिकल फार्मेसी को कॉल कर एमएमजी अस्पताल के चिकित्सक तुषार अग्रवाल के नाम से कॉल किया था। डेढ़ लाख रुपये की कीमत की दवाई मंगाकर फर्जी चेक सौंपकर गिरोह भाग गया था। इसके बाद एक जनवरी 2026 को लोहिया नगर स्थित निकोल इंटरप्राइजेज के संचालक को डॉ. भीमराव आंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सेक्टर 30 नोएडा के डॉ. अमित कुमार गुप्ता एचओडी के नाम से कॉल कर 1.09 लाख रुपये की दवाइयां मंगाईं थीं।

व्यापार जगत की नामचीन हस्तियों को अमर उजाला करेगा सम्मानित

संवाद न्यूज एजेंसी

अमर उजाला Business Excellence Awards 2026 Dubai, UAE

Powered by OMAXE Turning dreams into reality

नई दिल्ली। व्यापार को बढ़ावा देने की पहल के तहत अमर उजाला व्यापार जगत की नामचीन हस्तियों को अमर उजाला बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 से सम्मानित करेगा। इसका आयोजन 2 फरवरी को दुबई, यूएई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे से होटल रैडिसन, डेरा क्रीक दुबई में होगा। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देश-विदेश से चुने गए प्रतिष्ठित उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को उनके अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

इस अवसर पर आयोजित होने वाला बिजनेस टूर 3 रात और 4 दिन का होगा, जो 31 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान अवार्ड विजेताओं को नेटवर्किंग, बिजनेस इंटरैक्शन और सम्मान समारोह का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जुड़ी है, जबकि ओमेक्स 'पावर्ड बाय' पार्टनर है। वहीं, 'द प्रॉपर्टी क्लिनिक' इस कार्यक्रम में भरोसेमंद प्रॉपर्टी पार्टनर की भूमिका निभा रहा है।

इन्हें मिलेगा सम्मान

डॉ. जितेंद्र कुमार गुप्ता, डॉ. कमल कांत उपमन्यु, रौनक उपमन्यु, रामहरी, हर्षित अग्रवाल, शिव कुमार गुप्ता, चंचल गुहैरमैन, डॉ. रुचि रावत, जिमी सिंह, मयंक कुमार, प्रणव गुप्ता, सागर सेठी, ठाकुर सुनील सिंह, राजीव चौधरी, मोहित त्यागी, डॉ. अंकुर लट्ठर, ज्ञानेश कुमार दीक्षित, डॉ. ममता कुमार, मोहम्मद हैदर अली, विमलेश मौर्य, डॉ. अशोक कुमार शर्मा, शुभम शर्मा, सोबमीर कोड़ान, लक्ष्मण पी. कुशवाहा, नुक्षत्रा गुप्ता, डॉ. मीना पंठरी, श्रीमती उमा अग्रवाल, नवनीत अग्रवाल, डॉ. सौरभ शर्मा, नीना जैन, श्री दीपेंद्र सिंह चौहान, इंजीनियर रणधीर सिंह, उदय राज सिंह, अंजनी कुमार पांडेय, डॉ. शेषधार पांडेय, डॉ. सैयद नाजिम अली।

अमर उजाला करेगा बिजनेस लीडर्स का सम्मान

अमर उजाला बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स का उद्देश्य ऐसे व्यवसायियों और संस्थानों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में गुणवत्ता, नवाचार और भरोसे का उदाहरण पेश किया है। यह आयोजन न सिर्फ भारतीय उद्यमिता को वैश्विक मंच प्रदान करेगा, बल्कि दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर में भारत की कारोबारी क्षमता को भी मजबूती से सामने लाएगा।अमर उजाला का यह प्रयास व्यापार और उद्योग जगत में उत्कृष्टता को पहचान देने की दिशा में एक और सशक्त कदम माना जा रहा है।

युवराज मामले में दो आरोपियों को जमानत

पुलिस नहीं साबित कर पाई कंपनी में स्वामित्व की भूमिका, 25-25 हजार के मुचलके पर रिहाई

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस कंपनी के कर्मचारी रवि बंसल और सचिन करनवाल को 25-25 हजार रुपये के एक-एक जमानती व इतनी ही धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत दे दी।

इसके साथ ही न्यायालय ने कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिसमें जांच में पूर्ण सहयोग करने और बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ने और विवेचना के दौरान साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने की बात शामिल है। इस मामले में इस मामले में पुलिस आरोपियों की बिल्डर कंपनी में स्वामित्व की भूमिका साबित नहीं कर सकी।

एमजेड बिल्डर कंपनी के निदेशक की रिमांड बढ़ाने के साथ जमानत याचिका पर 2 फरवरी को सुनवाई

वहीं इसी मामले में एमजेड बिल्डर कंपनी के निदेशक अभय कुमार की रिमांड बढ़ाने के साथ जमानत याचिका पर 2 फरवरी को सुनवाई होगी। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने पिता राज कुमार मेहता की तहरीर पर एमजेड विजटाउन व लोटस ग्रीन बिल्डर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

निर्मल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू पर रोक

ग्रेटर नोएडा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस कंपनी से कथित रूप से जुड़े मामले में आरोपी निर्मल सिंह के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बिना ठोस साक्ष्य और आधारभूत तथ्यों के किसी व्यक्ति के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है। यह आदेश युवराज मेहता के पिता राज कुमार मेहता की शिकायत से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अदालत ने विवेचक की भूमिका पर भी सवाल उठाए और भविष्य में ठोस तथ्य सामने आने पर ही कार्रवाई की छूट देने की बात कही। निर्मल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में मांग की थी कि उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को निरस्त किया जाए। आरोपी पक्ष ने एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा को आधार बनाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन दस्तावेज में वर्ष 2016 से 2022 तक और वर्तमान समय तक कंपनी के निदेशकों की सूची दी गई। जिसमें निर्मल सिंह का नाम दर्ज नहीं है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लोटस ग्रीन के निदेशक के रूप में रोहित किशोर, मधु चंद्रा, विनय विनायक अम्बेडक, कल्याण कुमार कांजो, गोपाल सिंह और वर्तमान में मयंक का नाम दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका कंपनी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा। ब्यूरो

बुलेट की तेज आवाज निकालने से टोकने पर की थी हत्या, 4 धरे

शराब के नशे में मारपीट के बाद ईंट से हमला कर हुई थी किसान की हत्या

ग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली पुलिस ने ईंट मारकर किसान की हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उसका दावा है कि गाजियाबाद के भूपखेड़ी निवासी मनीष (20), गांव कुड़ीखेड़ा निवासी अमित (26), आकाश सिंह (26) और बागपत के गढ़ी सिरोरा निवासी अभिषेक उर्फ सेकु (25) ने बुलेट तेज आवाज निकलने से टोकने पर वारदात की थी। इनके कब्जे से मृतक का आधार कार्ड और घायल का टूटा मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि 17 जनवरी को वादी ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि उनके चाचा कृष्णपाल निवासी कुड़ीखेड़ा गांव और गांव के ही सुंदर खेतों में गेहूं की रखवाली करने गए थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने दोनों पर हमला कर दिया। शुक्रवार को पुलिस ने राजतपुर अंडरपास के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने हत्या को रोड एक्सीडेंट देने का प्रयास किया था।

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि मनीष सुंदर का मोबाइल फोन तोड़कर अपने साथ ले गया था। अमित कृष्णपाल का आधार कार्ड ले गया था। एसीपी पवन कुमार ने बताया कि अमित के खिलाफ 2021 में थाना बादलपुर में बलवा, मारपीट, रंगदारी और धमकी से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज हैं। चारों आरोपी 12वीं पास हैं। अमित नोएडा सेक्टर-5 में दूध की सप्लाई करता है। मनीष ब्लू सफायर मॉल में काम करता है। अन्य आरोपी अलग-अलग जगहों पर निजी काम करते थे।

पुलिस के अनुसार, मनी, अमित, आकाश और अभिषेक उर्फ सेकु घटना की शाम बंबावड़ रोड पर शराब पीने के बाद कुड़ीखेड़ा गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान मनीष की बुलेट बाइक के साइलेंसर की तेज आवाज आने पर कृष्णपाल ने उसे टोका। आरोप है कि मनीष ने कृष्णपाल के मुंह पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह खड़ंजे पर गिर पड़े।

सूरजकुंड सजा... आज से लगेगा मेला

सोमवार से शुक्रवार तक 150 व शनिवार-रविवार को 200 रुपये का टिकट

फरीदाबाद। आज 39वें अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज होगा । इस बार मेला और भी ज्यादा भव्य और सुंदर होने वाला है। मेला स्थल को रंग- बिरंगी लाइटें और फूलों से सजाया गया है। इस बार भी देश- विदेश से लोग अपनी कला, संस्कृति, परंपरा, परिधान सहित अन्य सामग्री लेकर मेले में पहुंचे हैं, जोकि पर्यटकों को काफी पसंद आने वाला है।

परिसर में बने सेल्फी प्वाइंट पर रंग रोगन करते कारीगर । संवाद

मेले में इस बार जोन टू हवेली में 20 फूड की स्टॉल लगाई जाएंगी। इसके साथ ही ऊपर की ओर फूड कोट में करीब 39 स्टॉल लगाई जाएंगी, जिसमें सभी राज्यों की स्टॉल होंगी। मेले में थीम स्टेट उत्तर प्रदेश व मेघालय को अलग से फूड स्टॉल लगाने की जगह दी जाएगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन चखने का मौका मिलेगा। मेले में पर्यटकों को अलग- अलग राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन चखने को मिलेंगे।

थीम स्टेट उत्तर प्रदेश व मेघालय की होंगी 40 स्टॉल : थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय को मेले में अलग से जगह दी जाएगी। प्रत्येक राज्य की 40 दुकानें होंगी। मेघालय को पहली बार थीम स्टेट बनने का मौका मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले 2018 में थीम स्टेट रह चुका है। इन सभी स्टॉल पर शहर की ऐतिहासिक पहचान को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही, वहां की जीवनशैली, खानपान और सांस्कृतिक धरोहर को भी आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। संवाद

पत्नी की गला घोंटकर हत्या साले को कॉल कर बताया

गुरुग्राम। सेक्टर-37 थाना क्षेत्र के खांडसा में 28/29 जनवरी की रात एक युवक ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के करीब 12 घंटे बाद आरोपी ने अपने साले को कॉल कर पत्नी के साथ मारपीट होने के बारे में जानकारी दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी पति भाग गया है। सूचना मिलने पर सेक्टर-37 थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी में पहुंचाया।

शीलू। फाइल

मृतका की पहचान औरैया (उत्तर प्रदेश) के खास भरा निवासी शीलू (27) के रूप में हुई। उसकी शादी आठ साल पहले कानपुर (उत्तर प्रदेश) के रानी घाट कॉलोनी निवासी सनी दयाल के साथ हुई थी। दंपती के दो बच्चे हैं, जिसमें सात साल का बेटा व तीन साल की बेटी है। दंपती करीब 4 साल से गुरुग्राम के खांडसा में किराये पर रह रहे थे। सनी दयाल दिहाड़ी-मजदूरी करता है। शीलू भी कई बार दिहाड़ी पर काम करती थी। बताया जा रहा है कि शीलू का कई बार अपने पति सनी दयाल के साथ झगड़ा हो चुका था, जिसमें परिवार वालों की ओर से दोनों को समझाया भी जा चुका था। मृतका शीलू के भाई कपिल ने बताया कि 29 जनवरी की दोपहर बाद करीब 3:30 बजे उसे शीलू की मौत के बारे में पता चला। ब्यूरो

चाकू-पत्थर से वारकर दो दोस्तों की हत्या

गाजियाबाद। ट्रांस हिंडन जोन के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित वैष्णो ढाबे पर देर रात कुछ लोगों ने दो दोस्तों की हत्या कर दी और मौके से भाग गए। देर रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ढाबे पर पहले खाना लेने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसी के चलते कुछ लोगों ने दोनों दोस्तों सत्यम और श्रीपाल पर चाकू और पत्थर से हमला कर दिया।

ढाबे पर हुई इस घटना के बारे में वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ढाबे पर पहुंची पुलिस दोनों घायलों को पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची, वहां डाक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ट्रांसहिंडन निमिष पाटील ने घटना के बारे में बताया कि खोड़ा थाना क्षेत्र के आंबेडकर गेट के नजदीक कागज मार्केट गली में एक वैष्णो होटल है। वहां पर शुक्रवार की देर रात खाना जल्दी लेने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के लोग शराब के नशे में थे। इसी बीच दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने खोड़ा निवासी सत्यम और उसके दोस्त श्रीपाल पर हमला कर दिया। वहां आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपियों ने दोनों पर चाकू और एक पत्थर से हमला किया। इससे सत्यम और श्रीपाल बुरी तरह से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पैदल ही वहां से भाग निकले। ब्यूरो

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा

24492 पद

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि : 13 फरवरी, 2026
योग्यताएं : इंटरमीडिएट व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : bssc.bihar.gov.in

भारत संचार निगम लिमिटेड ■ 120 पद

सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि
07 मार्च, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम उम्र 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 30 वर्ष
यहां आवेदन करें
bsnl.co.in

झारखंड लोक सेवा आयोग ■ 103 पद

उप समाहर्त्ता, पुलिस उपाधीक्षक आदि के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
14 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम उम्र 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 35 वर्ष
यहां आवेदन करें
jpsc.gov.in

बैंक ऑफ बड़ौदा में संभावनाएं ■ 418 पद

जूनियर मैनेजर, मैनेजर व अन्य पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 19 फरवरी, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : bankofbaroda.bank.in

एआईआईए में आवेदन आमंत्रित ■ 33 पद

कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंट ऑफिसर आदि के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
02 मार्च, 2026
योग्यताएं
एमकॉम, एमबीए व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
aiia.gov.in

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ■ 26 पद

अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य अभ्यर्थी करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
10 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 30 वर्ष
यहां आवेदन करें
ircon.org

यहां भी नौकरी के मौके ...

- नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली : जनरल मैनेजर के पदों पर आवेदन आमंत्रित।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 20 फरवरी, 2026
- nhb.org.in
- नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली : डिप्टी जनरल मैनेजर व कंपनी सेक्रेटरी का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 17 फरवरी, 2026
- indiaseeds.com

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

सिर्फ शुरुआत ही काफी नहीं

सफल होने के लिए छोटे, स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य के साथ निरंतर प्रयास आवश्यक है

गयानी गुनासेकेरा
पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च फेलो
सिडनी यूनिवर्सिटी

काम की शुरुआत में अक्सर लोगों में नई ऊर्जा और बड़े बदलाव की उम्मीद दिखाई देती है। सभी सोचते हैं कि अब सब कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही उत्साह कम होने लगता है। हम इसे अपनी इच्छाशक्ति या अनुशासन की कमी मान लेते हैं, जबकि मनोविज्ञान बताता है कि नई शुरुआत हमें काम शुरू करने में तो मदद करती है, पर लंबे समय तक टिके रहने में नहीं। जब लक्ष्य बहुत बड़े, अस्पष्ट या अव्यावहारिक होते हैं, तो हम जल्दी थक जाते हैं। टिकाऊ बदलाव के लिए जरूरी है कि छोटे, स्पष्ट और अव्यावहारिक लक्ष्य बनाए जाएं और उन पर रोज थोड़ा-थोड़ा काम किया जाए।

■ लक्ष्य छोटा रखें
हमें पहले से मानकर चलना चाहिए कि शुरुआती उत्साह समय के साथ कम होगा, और यह बिल्कुल सामान्य है। इसलिए काम की योजना ऐसी होनी चाहिए, जो कम प्रेरणा या बहुत व्यस्त दिनों में भी टूटे नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे छोटा संभव कार्य तय करें, जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट का काम। इतना छोटा लक्ष्य दिमाग पर बोझ नहीं डालता और उसे टालना मुश्किल होता है। कई बार यही 10 मिनट धीरे-धीरे ज्यादा समय में बदल जाते हैं, लेकिन असली जीत यह है कि हम रुकें नहीं और आगे बढ़ते रहें।

■ मन से चुनें अपना लक्ष्य
हमें ऐसे लक्ष्य नहीं चुनने चाहिए, जो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों या दबाव की वजह से बनाए गए हों। जब लक्ष्य हमें खुद से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण लगते हैं, तभी हम उन्हें लंबे समय तक निभा पाते हैं। अपने मन से चुने गए लक्ष्य हमें ज्यादा प्रेरित रखते हैं, क्योंकि उनमें हमारी रुचि और वजह छिपी होती है। ऐसे लक्ष्य न सिर्फ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, बल्कि मुश्किल समय में भी टिके रहने में मदद करते हैं।

■ आसान तरीका तलाशें
काम और लक्ष्यों को याददाश्त के भरोसे छोड़ने के बजाय किसी आसान सिस्टम की मदद लेनी चाहिए। जीटीडी, ओकेआर और हैबिट स्टैकिंग काम और लक्ष्यों को आसान बनाने के तरीके हैं। जीटीडी में सारे काम लिखकर, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, ताकि कुछ रह न जाए। ओकेआर में पहले एक बड़ा लक्ष्य तय किया जाता है और

फिर उसे पूरा करने के लिए छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं। हैबिट स्टैकिंग में नई आदत को रोज की किसी पुरानी आदत से जोड़ दिया जाता है, जिससे उसे अपनाना आसान हो जाता है। ये तरीके मिलकर काम को व्यवस्थित रखते हैं और निरंतर प्रगति में मदद करते हैं।

■ जवाबदेही सुनिश्चित करें
लक्ष्यों को किसी साथी या सहकर्मी के साथ साझा करने से हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब कोई हमारी प्रगति पर नजर रखता है या हमारी उपलब्धियों और मुश्किलों में भागीदार बनता है, तो हमें अपने लक्ष्यों को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती रहती है। यह न केवल हमारी लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करता है, बल्कि हमारी मेहनत और प्रयासों को और अधिक संगठित और केंद्रित भी बनाता है।
-द कन्वर्सेशन

अंतरराष्ट्रीय पहल

इंडिया एक्सीलेंस अवॉर्ड-2026

यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इंडिया एक्सीलेंस अवॉर्ड-2026 यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित फाइनेंशियल अवॉर्ड है। यह किसी भी विषय में फुल-टाइम एक वर्षीय पोस्ट-ग्रेजुएट करने वाले भारतीय छात्रों के लिए उपलब्ध है। आवेदक का भारत का निवासी होना आवश्यक है। सितंबर 2026 में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर होना जरूरी है। आवेदन करते समय ऑफर लेटर होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के लिए चुने जाने के लिए ऑफर लेटर होना चाहिए। उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड आमतौर पर 85% या उससे अधिक अंक होना आवश्यक है। साथ ही, उन्हें यह भी बताने में सक्षम होना चाहिए कि मास्टर्स की पढ़ाई उनके कॅरिअर या भविष्य की योजनाओं में कैसे मदद करेगी। चयनित उम्मीदवारों को एक वर्ष की पढ़ाई के लिए 12,500 पाउंड की ट्यूशन फीस में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक लिंक tinyurl.com/ym8njzte पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

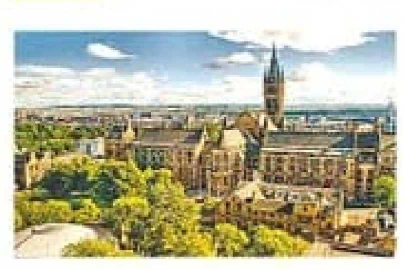

आवेदन आमंत्रित

गूगल का इंटर्नशिप प्रोग्राम

गूगल की ओर से रिसर्च साइंटिस्ट इंटर्न के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन के लिए जरूरी है कि आवेदक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, मशीन इंटेलिजेंस और डाटा साइंस, एआई या किसी संबंधित तकनीकी क्षेत्र में पीएचडी प्रोग्राम में नामांकित हो। साथ ही मशीन लर्निंग के एक या अधिक क्षेत्रों में अनुभव व पाइथन में प्रोग्रामिंग का अनुभव भी होना चाहिए। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान प्रशिक्षुओं को रिसर्च साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर चीजों को खोजने, आविष्कार करने और बनाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रशिक्षु डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, प्राइवेसी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज और डाटा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में चुनौतियों पर काम करते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक लिंक tinyurl.com/yxyfwpub पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट — हफ्ते की परीक्षाएं

एसएससी एमटीएस/ हवलदार परीक्षा

- परीक्षा की तिथि : 04 फरवरी, 2026 से शुरू
- यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो सेशन में होगी। सेशन-I में संख्यात्मक और गणितीय क्षमता आदि से 120 अंकों के लिए 40 प्रश्न व सेशन-II में सामान्य जागरूकता व अंग्रेजी भाषा और समझ से 150 अंकों के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** ssc.gov.in

यूपीपीएससी कंप्यूटर सहायक परीक्षा

- परीक्षा की तिथि : 06 फरवरी, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान व कंप्यूटर ज्ञान से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** uppsc.up.nic.in

खुद को परखें

1. हाल ही में खबरों में छाए श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है?
   (a) भोपाल (b) उज्जैन
   (c) इंदौर (d) सतना
2. यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (यूरैटम) की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी?
   (a) मास्ट्रिच संधि, 1992
   (b) लिस्बन संधि, 2007
   (c) पेरिस संधि, 1951
   (d) रोम संधि, 1957
3. हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली लेपिडागाथिस कोंकेनेंसिस क्या है?
   (a) पुष्पी पौधे की एक नई प्रजाति
   (b) एक प्रकार का वायरस
   (c) पारंपरिक औषधि
   (d) आक्रामक खरपतवार

उत्तर : 1.b, 2.d, 3.a

सामान्य ज्ञान

पंचम

■ क्या है
यह पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से विकसित एक प्रमुख डिजिटल पहल है।

■ चर्चा में क्यों
हाल ही में, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने 'पंचम'-पंचायत सहायता और संदेश चैटबॉट लॉन्च किया है।

■ 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध
यह भारत सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच सीधा डिजिटल संपर्क स्थापित करता है। यह भाशिनी (राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन) से जुड़ा है और 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी स्थानीय भाषा में संवाद कर सकते हैं।

■ दो-तरफा संवाद को बनाता आसान
यह प्लेटफॉर्म दो-तरफा संवाद की सुविधा देता है, जिससे अधिकारी मंत्रालय को सीधे सुझाव, सवाल और स्थानीय समस्याएं भेज सकते हैं, वहीं मंत्रालय जरूरी संदेश, परिपत्र और अपडेट पंचायतों तक तुरंत पहुंचा सकता है, जिससे तेज निर्णय और जमीनी समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है।

पहचान

शख्स : सेरिंगे खाबाने लेम 'खाबी लेम'

■ चर्चा : दुनिया में सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले टिक टॉक कंटेंट क्रिएटर।
क्यों : किसी कंटेंट क्रिएटर के तौर पर अब तक का सबसे बड़ा सौदा किया।

कंटेंट का किंग

लोग उन्हें टिक टॉक का राजा कहते हैं और वह अमेरिकी अभिनेता विल स्मिथ के जैसा बनना चाहते हैं। फुटबाल के फैन हैं, तो लिखने का भी शौक रखते हैं। टिक टॉक पर सोलह करोड़ से अधिक, तो इंस्टाग्राम पर करीब आठ करोड़ फॉलोअर्स वाले खाबी लेम अपने करीब 8,900 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर इस वक्त दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं।

बात साल 2020 की है, जब कोविड महामारी के चलते पूरी दुनिया ठहर गई थी। उत्तरी इटली की एक फैक्टरी में काम करने वाले एक साधारण युवक को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस वजह से उसकी आमदनी का जरिया बंद हो गया और उसे भविष्य का भी कुछ नहीं सूझ रहा था। हालांकि, उसके पास कुछ ऐसा था, जो शायद लॉकडाउन का सामना कर रहे करोड़ों लोगों के पास नहीं था। वह था एक अनोखा नजरिया। उस लड़के ने अपने छोटे-से कमरे में बैठकर मोबाइल उठाया और देखा कि इंटरनेट 'लाइफ हैक्स', जो एक लोकप्रिय शैली है, जिसमें उपयोगकर्ता काम करने के आसान तरीके बताने के नाम पर सरल कामों को कितना उलझा देते हैं। उस लड़के ने बिना आवाज वाले रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू किया, उनमें वह बिना कुछ बोले मुश्किल लाइफ हैक्स का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अपने खुले हाथ के इशारे और बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ खत्म करता था। उस लड़के की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, जिसने उसे एक मामूली फैक्टरी कर्मचारी से दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला टिक टॉक स्टार बना दिया। वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि मशहूर इन्फ्लुएंसर सेरिंगे खाबाने लेम हैं, जिन्हें दुनिया खाबी लेम के नाम से भी जानती है। उनके वीडियो व कंटेंट को दुनिया भर में लोग बड़े चाव से देखते हैं। उनके प्रशंसक प्यार से उन्हें 'टिकटॉक का राजा', यानी 'कंटेंट का किंग' भी कहते हैं। इस बार उनके सुर्खियों में रहने का कारण है, एक कंपनी के साथ किया गया उनका करीब 8,900 करोड़ रुपये का एक सौदा। इसे किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए अब तक के सबसे बड़े पेशेवर सौदों में से एक माना जा रहा है।

शुरुआती जीवन

खाबी लेम का जन्म नौ मार्च, 2000 को सेनेगल में हुआ था। जब वह महज एक वर्ष के थे, तभी उनका परिवार इटली आ गया और ट्यूरिन के पास चिवासो में रहने लगा। खाबी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इटली के स्थानीय स्कूलों से प्राप्त की। 14 वर्ष की उम्र में कुछ समय के लिए उन्होंने एक मदरसे में भी पढ़ाई की। उन्होंने एक फैक्टरी में सीएनसी मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करने के अलावा कई छोटी-मोटी नौकरियां भी कीं। दिलचस्प तो यह है कि दो दशकों से भी ज्यादा समय तक इटली में रहने के बावजूद वहां की नागरिकता उन्हें साल 2022 में मिली। अक्तूबर 2020 में, उन्होंने जायरा नुची नामक एक इन्फ्लुएंसर से सगाई की, लेकिन यह रिश्ता जल्दी ही टूट गई। इसके बाद लेम ने मॉडल वेंडी थेम्बेलिह्ले जुएल से नवंबर 2023 में विवाह किया। हालांकि, यह रिश्ता भी महज छह महीने ही चल सका।

पहला बड़ा घर

खाबी न केवल कॉमेडी स्टार हैं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सादगी के आदर्श हैं। उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमाई से अपने सात सदस्यों के परिवार के लिए एक बड़ा घर खरीदा, ताकि सभी एक साथ रह सकें। वह एक यूनिसेफ गुडविल एंबेसडर भी हैं और बच्चों व युवाओं को सपने देखने तथा कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह एक *'हाफिज-ए-कुरान'* भी हैं। यह वह व्यक्ति होता है, जिसने कुरान को पूरा याद कर लिया हो।

अमेरिका में बसने का सपना

अमेरिका में बसना उनका सपना है। वह अमेरिकी अभिनेता और रैपर विल स्मिथ के जैसा बनना चाहते है। इसके अलावा वह एडी मर्फी को भी अपना आदर्श मानते हैं। उनके टिकटॉक पर 16 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा, इंस्टाग्राम पर भी उनके करीब आठ करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं। उनके टिक टॉक हैंडल का नाम खाबी लेम है।

फुटबाल, फिल्म और कॉमेडी

खाबी को फिल्में देखने का खास शौक है, खासकर कॉमेडी फिल्में। वह यात्रा करने और अपने परिवार व दोस्तों के साथ वक्त बिताने को प्राथमिकता देते हैं। खाली समय में वीडियो गेम खेलना और लेटेस्ट फैशन व मॉडलिंग ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना उनकी जीवनशैली का हिस्सा है। स्कूल के दिनों में वह फुटबाल और बास्केटबाल भी खेला करते थे। फुटबाल के तो वह जबर्दस्त प्रशंसक हैं। यही वजह है कि वह अपने वीडियो में अक्सर फुटबाल जर्सी पहने नजर आते हैं। उनकी पसंदीदा टीम जुवेंटस एफसी है। उन्हें एनिमेशन देखना और मंगा (जापानी ग्राफिक नॉवेल) पढ़ना भी खूब पसंद है। लेम को लिखने का भी शौक है। वह एक फिल्म की कहानी भी लिख रहे हैं, जो एक पिता और उसकी बेटी की दिलचस्प दास्तां है।

जब लिए गए हिरासत में

छह जून, 2025 को खाबी लेम को अमेरिका में उनके वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकने के कारण यूएस इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) द्वारा लास वेगास में हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें स्वैच्छिक रूप से देश छोड़ने की अनुमति दी गई और वह अमेरिका से वापस चले गए। वह इतालवी भाषा में माहिर हैं। इसके अलावा, वह अंग्रेजी, स्पैनिश, वोलोफ (सेनेगल की एक भाषा) भी बोलते हैं, हल्की-फुल्की पुर्तगाली भी बोल-समझ लेते हैं।

आज का दिन

31 जनवरी, 1961

नासा ने जीवित प्राणियों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक मिशन मर्करी-रेडस्टोन 2 के तहत 'हैम' नामक 4 वर्षीय चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा था।

- 1958 : अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 उपग्रह प्रक्षेपित किया था।
- 1893 : कोका कोला ट्रेडमार्क का पेटेंट कराया गया था।
- 1971 : पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के बीच टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी।
- 1971 : नासा ने अपोलो 14 मिशन के तहत मानवयुक्त चंद्रयान प्रक्षेपित किया था।

व्रत त्योहार

आज : माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी/चतुर्दशी। **कल :** माघ पूर्णिमा, गुरू रविदास जयंती, शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले। **राहुकाल :** सायं : 16.30 से 18.00 तक।

■ सूर्योदय : 07.13
■ सूर्यास्त : 17.56
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 12 माघ मास शक 1947, माघ मास 19 प्रविष्टे, 12 सावान हिजरी 1447, माघ पूर्णिमा 27.38 तक उपरांत फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, पुष्य नक्षत्र 23.57 तक उपरांत आश्लेषा नक्षत्र, प्रीति योग 10.18 तक उपरांत आयुष्मान योग, विष्टि करण 16.45 तक उपरांत बव करण, चंद्रमा कर्क राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : भाग्य सहायक रहेगा। सरकारी क्षेत्र में अटके कार्य बनेंगे। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

वृष : मानसिक उलझन बनी रहेगी। नौकरी में नई परेशानी आ सकती है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

मिथुन : आत्मबल बनाए रखें। योजना में सफलता विलंब से मिलेगी। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

कर्क : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। व्यय पर नियंत्रण रखें। विरोधी पक्ष से सचेत रहें।

सिंह : राजनीतिक क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। विकास की नई योजना बन सकती है। अटका धन मिल सकता है।

कन्या : राजकाज में सफलता मिलेगी। पूर्व निवेशित धन का लाभ संभव है। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

तुला : आलस्य पर नियंत्रण रखें। पूर्व नियोजित कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी।

वृश्चिक : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। निर्णय लेने में सावधानी बरतें। नौकरी में स्थानांतरण संभव है। यात्रा संभव है।

धनु : मनोत्साह बना रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र में रुचि रहेगी। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। अर्थ प्राप्ति संभव है।

मकर : आत्मबल बना रहेगा। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। विरोधी परास्त होंगे। विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा।

कुंभ : दिनमान सामान्य रहेगा। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी। सहोदरों का सहयोग मिलेगा।

मीन : मानसिक उत्तेजना एवं उतावलेपन से बचें। सरकारी क्षेत्र में अटका कार्य बनेगा। नौकरी में कार्य भार बढ़ सकता है।

जन्मदिन

प्रीति जिंटा, अभिनेत्री

आज जन्मे जातक मौलिक विचारों के स्पष्ट वक्ता एवं निर्णय लेने में चतुर होते हैं। इस वर्ष विकास के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा। नाते-रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव आएंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। उच्चस्तरीय परीक्षाओं में अनुकूल सफलता मिलेगी।

सुडोकू

				3	5	6		7
1		5					3	
3					4			
					7		2	6
		6	8		3	7		
7	4		5					
			3					2
	7					1		3
4		8	6	1				

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

9	8	4	2	3	5	6	1	7
1	2	5	7	9	6	8	3	4
3	6	7	1	8	4	2	5	9
8	1	3	9	4	7	5	2	6
5	9	6	8	2	3	7	4	1
7	4	2	5	6	1	3	9	8
6	5	1	3	7	9	4	8	2
2	7	9	4	5	8	1	6	3
4	3	8	6	1	2	9	7	5

डेली हेल्थ कैप्सूल

सर्दी में बच्चों को दें बाजरे का पोषण

बाजरे में भरपूर मात्रा में विटामिंस और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं।

सर्दियों में अक्सर लोगों को बाजरा जैसे साबुत अनाज का सेवन करने की सलाह दी जाती है। बाजरा में अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, साथ ही, इसमें अच्छी मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, साथ ही, इसकी तासीर गर्म होती है, जो

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर और बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। बच्चों को बाजरा खिलाने से उनके पाचन को दुरुस्त करने, शरीर को एनर्जी देने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में मदद मिलती है। बच्चों को बाजरा रोटी के रूप में खिलाया जा सकता है। बाजरे की रोटी खाना बच्चों के पाचन को दुरुस्त करने और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिल सकती है। बाजरे को रोटी के अलावा खिचड़ी के रूप में भी बनाया जा सकता है। बाजरे की खिचड़ी का सेवन करने से आयरन की कमी को दूर करने, पाचन को दुरुस्त करने और कैल्शियम की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बाजरे में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। सर्दी के मौसम में इसे बच्चों को जरूर देना चाहिए। इसकी तासीर गरम होती है, जिससे यह उनके शरीर को भी गर्माहट प्रदान करता है। डायबिटीज के मरीज भी इसे खा सकते हैं।
-नेहा पठानिया, आहार विशेषज्ञ

कल्पमेधा

क्रोध वह तेजाब है, जो किसी भी चीज पर डाले जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है, जिसमें वह रखा हुआ है।

– मार्क ट्वेन

गरीबी का पैमाना

देश में सबसे निचले तबके की पांच से दस फीसद आबादी के उपभोग व्यय में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यानी इस वर्ग के लोग अपनी जरूरत के लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद पर अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि गरीबों की माली हालत में सुधार हुआ है। संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रपट में गरीबी का दायरा कम होने की यह तस्वीर उकेरी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार के सबसिडी, पेंशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता जैसे कदमों के परिणामस्वरूप कमजोर वर्ग अभाव से उबरे हैं। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तस्वीर बदली है। मगर सवाल है कि गरीबी से उबरने का आकलन करने के पैमाने क्या हैं? क्या इस प्रक्रिया में सिर्फ वस्तुओं की खरीद पर खर्च बढ़ने को आधार बनाना काफी है? समीक्षा में आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि देश में उपभोग असमानता में कमी आई है, मगर क्या वास्तव में इसे गरीबी कम होने का सूचक माना जा सकता है?

आर्थिक समीक्षा रपट के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच समाज के सबसे निचले वर्ग के प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय में वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखी गई है। तर्क दिया गया है कि सरकारी नीतियों का आय वितरण पर महत्त्वपूर्ण असर हुआ है, जिससे गरीब तबके की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। मगर इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि जिसे 'व्यय की क्षमता' बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है, उसका आधार क्या है। इसमें दोराय नहीं कि सामान्य तौर पर किसी भी परिवार के खर्च करने की क्षमता में तभी इजाफा होता है, जब उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। इसके बिना अगर गरीब परिवारों का वस्तुओं की खरीद पर व्यय बढ़ रहा है, तो यह महंगाई और मजबूरी से उपजी परिस्थितियों का नतीजा भी हो सकता है। जाहिर है, जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर हर किसी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आमदनी बेहद कम होने और किसी वस्तु की अत्यधिक जरूरत पड़ने पर गरीब परिवार बैंक या साहूकार से कर्ज लेकर भी खर्च करते हैं। इस सूरत में ऐसे परिवारों के व्यय में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, पर क्या इसे यह मान लिया जाए कि वे गरीबी से उबर गए हैं!

यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर सबसिडी या मुफ्त राशन देने से गरीबी कम हो जाती है। और अगर देश में जमीनी स्तर पर वास्तव में गरीबी कम हो गई है, तो आज भी सरकार की ओर से करीब अस्सी करोड़ लोगों को तय मात्रा में मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। कोविड काल में शुरू की गई इस योजना को एक जनवरी, 2024 से अगले पांच साल तक बढ़ा दिया गया। ऐसे में जरूरी है कि गरीबी को आंकड़ों के जरिए कागजों पर खत्म करने की बजाय इस दिशा में धरातल पर प्रयास किए जाएं। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उनकी आजीविका के स्थायी साधन विकसित करना जरूरी है और यह तभी संभव हो पाएगा, जब गरीबों के लिए शिक्षा और रोजगार के सस्ते, सुलभ और पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। उम्मीद है कि बजट में सरकार इस मसले पर कोई ठोस घोषणा करेगी।

ताक पर गरिमा

यह विडंबना ही है कि भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआइ) ने एक ऐसे व्यक्ति को अहम जिम्मेदारी सौंप कर टीम के साथ जार्डन भेज दिया, जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का आरोपी है। गौरतलब है कि 'इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन' (आइटीपीएफ) विश्वकप क्वालीफायर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जो भारतीय दल जार्डन गया है, उसमें बलात्कार के आरोपी कर्नल (सेवानिवृत्त) तरसेम सिंह वरैच को प्रबंधक और कोच के रूप में भेजा गया है। स्वाभाविक ही इसे लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया है कि ऐसे अपराध के आरोपी को इस हैसियत कैसे भेजा गया। सवाल है कि वहां भेजने के फैसले से पहले क्या ईएफआइ ने एक बार यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि इसका खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि किस स्तर पर प्रभावित होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता में भेजे जाने वाले दल में किसी व्यक्ति को शामिल करने से पहले क्या उसके बारे में कोई पड़ताल नहीं की जाती? अगर ईएफआइ को तरसेम सिंह वरैच पर लगे आरोपों और कानूनी मामले के बारे में जानकारी थी, तो उसे भारतीय दल के साथ भेजने का क्या आधार था?

मामले की गंभीरता को देखते हुए ही आइटीपीएफ ने ईएफआइ से तुरंत उचित कार्रवाई करने और साथ ही प्रतियोगियों की सुरक्षा तथा खेल की गरिमा कायम रखने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। हैरानी की बात यह है कि अपराध की गंभीरता और तथ्यों के मद्देनजर ही जो आरोपी व्यक्ति जमानत पर बाहर है, उसे खेल अधिकारियों ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति भी दे दी। जबकि इससे पहले भी तरसेम को झूठी पहचान बनाकर फायदा उठाने से संबंधित एक अन्य मामले में महासंघ ने 2022-24 तक के लिए निलंबित कर दिया था। क्या इस तरह के फैसले को खेल की गरिमा और देश की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? जहां किसी भी खेल में खिलाड़ियों से लेकर कोच या प्रबंधक आदि के दल में चुने जाने के लिए उसकी स्वच्छ छवि को एक शर्त के तौर पर देखा जाना चाहिए, वहां इस पहलू की अनदेखी करने को किस तरह देखा जाएगा!

स्वच्छता की राह में रसायनों का जोखिम

एक दौर था, जब सुबह की शुरुआत चूल्हे की राख और मिट्टी की सोंधी खुशबू से होती थी, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म रसायन विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण था। मगर आज का आधुनिक समाज इसे पिछड़ापन बताकर त्याग चुका है और अब कृत्रिम रसायनों के जाल में उलझ गया है।

सुधीर कुमार

भारतीय सभ्यता में स्वच्छता एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संस्कार रही है। एक दौर था, जब सुबह की शुरुआत चूल्हे की राख और मिट्टी की सोंधी खुशबू से होती थी, जो वास्तव में उस समय की जीवनशैली की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो वह सूक्ष्म रसायन विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। मगर आज का आधुनिक समाज इसे पिछड़ेपन की निशानी समझकर त्याग चुका है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अब हम टेलीविजन विज्ञापनों में 'नींबू और नमक की शक्ति' खोज रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज इन्हीं प्राकृतिक तत्त्वों के साथ रसायन-मुक्त जीवन जी रहे थे। वर्तमान में हम सुविधा के नाम पर डिब्बाबंद रसायनों तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इस यात्रा में हमने स्वच्छता की मूल परिभाषा को ही खो दिया है। आज प्रश्न यह नहीं है कि बर्तन और कपड़े धुलाई के बाद कितने चमक रहे हैं, बल्कि यह है कि उस कृत्रिम चमक के पीछे छिपे रसायन हमारे स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए, तो राख कोई 'अपशिष्ट' नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली 'अपघर्षक' और 'क्षारीय' एजंट है। इसमें मुख्य रूप से पोटेशियम कार्बोनेट जैसे तत्त्व होते हैं। जब इस राख को पानी और बर्तनों पर लगी चिकनाई (वसा) के साथ रगड़ा जाता है, तो सतह पर एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती है, जो चिकनाई को साबुन में बदल देती है। इसके अतिरिक्त राख का उच्च 'पी-एच' स्तर इसे एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक बनाता है, जो सूक्ष्म जीवों की कोशिका भित्ति को नष्ट कर उन्हें मार देता है। यह तकनीक न केवल शून्य-लागत और किफायती थी, बल्कि मिट्टी और जल के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित थी। औद्योगीकरण ने हमें 'सुविधा' के आवरण में सिंथेटिक डिटर्जेंट सौंप दिए। वैज्ञानिक रूप से ये रसायन पानी के 'पृष्ठ तनाव' को कम कर सफाई तो करते हैं, लेकिन इनसे हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। त्वचा संबंधी समस्याओं के अलावा ये रसायन बर्तनों की सतह पर एक अदृश्य परत छोड़ देते हैं। अंतरराष्ट्रीय शोध बताते हैं कि एक व्यक्ति अनजाने में सालाना कई ग्राम डिटर्जेंट निगल जाता है, जो पाचन तंत्र को प्रभावित करने के साथ-साथ आंतों के लाभकारी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। इसके अलावा डिटर्जेंट में मौजूद 'थैलेट्स' जैसे तत्त्व हार्मोन के असंतुलन और अंतःस्राव समस्याओं के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं।

स्वच्छता की इस विकास यात्रा में 'बायो-एंजाइम' एक क्रांतिकारी मोड़ के रूप में उभरे हैं। यह अवधारणा मूल रूप से थाईलैंड की प्रसिद्ध पर्यावरणविद् डा रोसुकान पूमपवोंग द्वारा विकसित की गई है। बायो-एंजाइम फलों के छिलकों, गुड़ और पानी के किण्वन से तैयार एक जैविक अर्क है। जहां रसायनिक डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव पर काम करते हैं, वहीं बायो-एंजाइम का विज्ञान 'प्रोटीज', 'एमाइलेज' और 'लाइपेज' जैसे सक्रिय एंजाइम पर आधारित है। ये एंजाइम कचरे और तेल के जटिल कार्बनिक अणुओं को विखंडित कर उन्हें पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। इसकी सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह पानी को प्रदूषित करने के बजाय उसे शुद्ध करता है। जब यह एंजाइम युक्त पानी नालियों में जाता है, तो वह वहां मौजूद प्रदूषकों और हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। जिसे हम ताजगी भरी खुशबू समझते हैं, वह वास्तव में

हमारे फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए नुकसानदेह होती है।

भारत के कानूनी ढांचे और वैश्विक पर्यावरणीय मानकों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो बायो-एंजाइम का उपयोग अब केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अनिवार्य नागरिक कर्तव्य बन चुका

> **विधिक सिद्धांतों की बात करें, तो रासायनिक डिटर्जेंट का बेलगाम उपयोग 'प्रदूषणकारी भुगतान सिद्धांत' के दायरे में आता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जो प्रदूषण फैलाता है, उसे ही उसकी भरपाई की कीमत चुकानी होगी। हालांकि, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, इसलिए कानूनी और नैतिक रूप से 'निवारक सिद्धांत' को अपनाना बेहद जरूरी है। बायो-एंजाइम इसी निवारक सिद्धांत का हिस्सा हैं- प्रदूषण फैलाने के बाद सफाई करने से बेहतर है कि हम ऐसा विकल्प चुनें, जो प्रदूषण पैदा ही न करे। प्रकृति के पास हर संकट का समाधान है, बशर्ते हम उसे पहचानने की वैज्ञानिक और विधिक दूरदर्शिता विकसित करें।**

है। देश के प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करे। जब हम रसायनों से भरे डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, तो हम अनजाने में अपने इस कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है, जो इसके संसाधनों का उपभोग करता है। इसी क्रम में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के महत्त्व को समझना भी जरूरी है। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से नदियों और जल निकायों में किसी भी हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ के विसर्जन को प्रतिबंधित करता है।

दरअसल, सामान्य डिटर्जेंट में भारी मात्रा में फास्फेट और नाइट्रेट होते हैं, जो नालियों से होते हुए अंततः हमारी नदियों और झीलों में पहुंचते हैं। यहां एक गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'यूट्रोफिकेशन' कहा जाता है। यानी डिटर्जेंट का फास्फेट पानी में मौजूद जंगली घास और शैवाल के लिए खाद का काम करता है। इससे शैवाल इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वे पूरी जल सतह को ढक लेते हैं, जिससे सूरज की रोशनी और हवा की आक्सीजन पानी में नहीं पहुंच पाती है। परिणामस्वरूप, मछलियां और अन्य जलीय जीव दम तोड़ देते हैं। एक जीवित नदी इस तरह 'मृत जल निकाय' में बदल जाती है।

विधिक सिद्धांतों की बात करें, तो रासायनिक डिटर्जेंट का बेलगाम उपयोग 'प्रदूषणकारी भुगतान सिद्धांत' के दायरे में आता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जो प्रदूषण फैलाता है, उसे ही उसकी भरपाई की कीमत चुकानी होगी। हालांकि, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती, इसलिए कानूनी और नैतिक रूप से 'निवारक सिद्धांत' को अपनाना बेहद जरूरी है। बायो-एंजाइम इसी निवारक सिद्धांत का हिस्सा हैं- प्रदूषण फैलाने के बाद सफाई करने से बेहतर है कि हम ऐसा विकल्प चुनें, जो प्रदूषण पैदा ही न करे। बायो-एंजाइम का उपयोग करके हम न केवल कानून का पालन करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन के अधिकार का सम्मान भी करते हैं। यह एक ऐसी विधिक जिम्मेदारी है, जो हमें एक 'उपभोक्ता' से बदलकर 'जागरूक संरक्षक' बनाती है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो पूरी दुनिया अब रसायनों के खतरनाक प्रभाव को समझ चुकी है। यूरोपीय संघ ने अपने कड़े नियमों के जरिए यह तय कर दिया है कि केवल वही उत्पाद बाजार में टिकेंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इसी प्रकार, अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजंसी भी अब स्वच्छता के लिए उन प्राकृतिक तत्त्वों को बढ़ावा दे रही है, जिनका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

यह समझना आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्तर पर बायो-एंजाइम का चुनाव केवल एक घरेलू बदलाव नहीं, बल्कि 'स्वच्छ भारत अभियान' के उस वृहद उद्देश्य की पूर्ति है, जो केवल कचरा हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि कचरे के स्रोत पर ही उसके वैज्ञानिक निपटान की बात करता है। जब हम अपनी जीवनशैली को प्रकृति के चक्र के अनुरूप ढालते हैं, तब हम आने वाली पीढ़ी को केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि एक 'जीवित और श्वसन योग्य पारिस्थितिकी' सौंपते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास एक पूर्ण चक्र की तरह है, जहां हमने राख की प्राकृतिक शुद्धता से शुरुआत की और रसायनों के भंवर से होते हुए अब बायो-एंजाइम की 'समझदारी' की ओर लौट रहे हैं। राख हमारा गौरवशाली अतीत थी और बायो-एंजाइम हमारा सुरक्षित भविष्य है। यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल और उपजाऊ मिट्टी विरासत में देना चाहते हैं, तो इस क्रांति की शुरुआत हमारी रसोई में बर्तन धोने वाली जगह से होनी चाहिए। प्रकृति के पास हर संकट का समाधान है, बशर्ते हम उसे पहचानने की वैज्ञानिक और विधिक दूरदर्शिता विकसित करें।

दुनिया मेरे आगे

सुविधा की असुविधा

मो अजहर आलम अंसारी

प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार 'शांत और साधारण जीवन निरंतर बेचैनी के साथ सफलता की दौड़ से अधिक सुख देता है।' आज का मनुष्य पहले से कहीं अधिक विकसित, शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम हो गया है। उसके पास सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। बिजली से चलने वाले यंत्र, तेज रफ्तार वाहन, स्मार्टफोन, इंटरनेट, आनलाइन सेवाएं और मनोरंजन के अनगिनत साधन उपलब्ध हैं। कुछ दशक पहले जिन चीजों का सपना भी नहीं देखा जा सकता था, वे आज आम जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। फिर भी अजीब विरोधाभास यह है कि जितनी तेजी से हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी ही तेजी से हमारा संतोष घटा है।

यह आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विडंबना है- हमारे पास सब कुछ है, सिवाय शांति के। तकनीकी प्रगति ने मनुष्य के जीवन को कई तरह से आसान बनाया है। अब भोजन पकाने से लेकर बिल जमा करने तक, हर काम अंगुलियों के इशारे पर हो जाता है, लेकिन क्या इससे हमारा जीवन वास्तव में सुखी हुआ है? अगर हम ईमानदारी से उत्तर दें, तो पाएंगे कि भौतिक रूप से हम समृद्ध हुए हैं, पर मानसिक रूप से दरिद्र। आज हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा है- अधिक पैसा कमाने की, बड़ा घर खरीदने की, नाम और पहचान पाने की। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जो कल 'सपना' था, वह आज 'जरूरत' बन गया है, और कल फिर उससे आगे की चाह उठ खड़ी होगी। मनुष्य जितना पा रहा है, उतना ही असंतुष्ट भी हो रहा है। यही आधुनिकता का दुश्चक्र है।

> **सुविधाओं के इस महासागर में आज का व्यक्ति पहले से कहीं अधिक अकेला और बेचैन है। परिवार छोटे हो गए हैं, रिश्ते औपचारिक हो गए हैं और संवाद का स्थान संदेशों ने ले लिया है। लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग-अलग दुनिया में खोए रहते हैं।**

अगर हम कुछ दशक पीछे लौटें, जब गांवों में जीवन धीमी रफ्तार से चलता था, तो देखेंगे कि लोग कम साधनों में भी अधिक प्रसन्न थे। उनके पास न तो वातानुकूलन मशीन थी और न ही फ्रिज और मोबाइल। मगर उनके पास समय था- परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए और खुद के लिए। शाम होते ही लोग चौपाल पर बैठकर बातें करते, गीत गाते या मिलजुल कर किसी का दुख-सुख बांटते। बच्चों की हंसी खेतों में गूंजती और रिश्तों में अपनापन होता। वह पीढ़ी जानती थी कि 'कम में भी बहुत कुछ' होता है। उनके पास भले भौतिक साधन कम थे, पर मन की शांति थी, क्योंकि वे तुलना नहीं करते थे, प्रदर्शन नहीं करते थे।

वर्तमान युग को अक्सर 'सूचना युग' कहा जाता है, लेकिन सच कहें, तो यह तुलना युग भी है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया है। अब हर कोई अपने जीवन को दूसरों के सामने 'संपूर्ण' दिखाने में लगा है। एक व्यक्ति की सफलता दूसरे के लिए प्रेरणा बनने के बजाय ईर्ष्या का कारण बन जाती है। दूसरों की छुट्टियों, कपड़ों या कारों को देखकर अपने जीवन को अधूरा मानना आज आम बात हो गई है। यह लगातार तुलना और प्रदर्शन ही हमारे असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य अब 'जीने' से ज्यादा 'दिखाने' में विश्वास करने लगा है।

सुविधाओं के इस महासागर में आज का व्यक्ति पहले से कहीं अधिक अकेला और बेचैन है। परिवार छोटे हो गए हैं, रिश्ते औपचारिक हो गए हैं और संवाद का स्थान संदेशों ने ले लिया है। लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग-अलग दुनिया में खोए रहते हैं। बच्चे बाहर खेलने की जगह स्क्रीन पर गेम खेलते हैं और माता-पिता अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि पारिवारिक बातचीत दुर्लभ हो गई है। काम का दबाव, प्रतिस्पर्धा, महंगाई, भविष्य की चिंता- इन सबने मिलकर मनुष्य के भीतर निरंतर तनाव भर दिया है। आज अस्पतालों में शारीरिक रोगों से अधिक मानसिक रोगों के मरीज मिलते हैं।

भौतिक साधन केवल शरीर की सुविधा बढ़ाते हैं, आत्मा की नहीं। एक व्यक्ति करोड़ों रुपए कमा सकता है, फिर भी रात को चैन से नहीं सो सकता। शांति और संतोष न तो बाजार में बिकते हैं, न बैंक में जमा होते हैं। वे भीतर से उपजते हैं- जब मनुष्य यह समझ लेता है कि 'पर्याप्त' क्या होता है। समस्या यह है कि आज हम 'पर्याप्त' का अर्थ ही भूल गए हैं। हर उपलब्धि के बाद भी और अधिक की चाह बनी रहती है। यह अंतहीन चाह ही मन की अस्थिरता का कारण बन गई है।

अगर हम वास्तव में शांति चाहते हैं, तो हमें अपनी जीवनशैली और सोच में परिवर्तन लाना होगा। जीवन को जितना सरल बनाएंगे, उतना हल्का महसूस करेंगे। अनावश्यक वस्तुओं और दिखावे से दूरी रखने की जरूरत है। जो कुछ हमारे पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष से आती है। यह सच है कि आधुनिक युग में सुविधाएं आवश्यक हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुविधा का अर्थ सुख नहीं होता। कभी कार से नहीं, बल्कि पैदल चलकर सूरज ढलने का आनंद लेकर देखना चाहिए। जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना ही मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं।

सच्चा विकास वही है जिसमें मनुष्य बाहर से नहीं, भीतर से भी उजाला महसूस करे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सुविधाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन संतोष का आरंभ हमारे भीतर ही है। सुविधाओं का विस्तार निश्चित रूप से मानव सभ्यता की उपलब्धि है, लेकिन अगर वह संतोष और शांति को नष्ट कर दे, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रगति रुक जाए, बल्कि यह कि प्रगति के साथ संतुलन बना रहे। हमें अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं कि वे हमारे मन की शांति को निगल जाएं। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह नहीं कि हमारे पास और सुविधाएं हों, बल्कि यह है कि हमारे भीतर संतोष और शांति हो।

समाज का फर्ज

फरीदाबाद में महज चार साल की मासूम के साथ सिर्फ पढ़ाई के नाम पर एक पिता इतना निर्मम बर्ताव कैसे कर सकता है। शिक्षा में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उन्हें डराना और धमकाना चाहिए। अपनी शिक्षा के पहले पायदान पर खड़ी उस मासूम को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी जान चली गई। यह कोई सोच भी नहीं सकता है। आज के समय में जहां विद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में छात्रों को पीटना प्रतिबंधित है, ऐसे समय में जब अभिभावक ही इतना कठोर व्यवहार अपने बच्चों के साथ करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अनुशासन सिखाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए इस तरह का हिंसात्मक रवैया अपनाना कतई उचित नहीं है। खासकर कम उम्र के बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जो अभी अपनी शिक्षा के शुरुआती दौर में हैं। ऐसे में एक सभ्य और शिक्षित समाज का फर्ज है कि अपने और अपने आसपास होने वाले ऐसे कृत्यों का विरोध करे। समाज को ऐसी हिंसक घटनाओं के प्रति जागरूक करे, ताकि फिर कोई मासूम इस तरह की घटना का शिकार न हो।

– अभिषेक जैसवाल, मैहर, मप्र

दुर्घटना की कड़ियां

'हादसे के सबक' (संपादकीय, 29 जनवरी) पढ़ा। विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत दिल दहला देने वाली घटना है। इस हादसे ने न केवल एक कद्दावर नेता छीना, बल्कि पिछले कई दर्दनाक हादसों की याद ताजा कर दी। बारामती में हुए इस हादसे की कई पहलुओं से जांच की जा रही है। यह दुर्घटना सरकारी तंत्र को फिर एक नया सबक दे गई है। बताया गया जब हादसा हुआ, उस वक्त हवाईअड्डे पर दृश्यता कम थी। यदि ऐसी स्थिति थी, तो जरूरी सावधानी क्यों नहीं बरती गई? ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें देश को कुछ नेताओं को खोना पड़ा है। कुछ समय पहले ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई। फिर भी सबक नहीं लिया गया। विमान की सुरक्षा जांच से लेकर हर स्तर पर मौसम की निगरानी के लिए एक समूचा तंत्र होने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं?

– ऐश यादव, जम्मू

सोच का बोझ

किसी बात को लेकर अधिक सोचना भी आज के दौर में बड़ी समस्या बन रही है। खासकर युवा वर्ग इसका प्रमुख रूप से शिकार है। किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए, यह बात सही है। मगर सोचना सिर्फ इतना ही चाहिए कि जिससे उस सोच का बोझ हम पर न पड़े। आज जब हम तकनीकी युग में हैं और हर काम के लिए अनेक विकल्प और सुझाव उपलब्ध हैं, इसके बावजूद अगर हम सिर्फ सोच के दायरे में फंसे रहे, तो कभी भी काम ठीक से होगा नहीं, बल्कि हम मानसिक रूप से थक जाएंगे। जिसका परिणाम कई बार घातक हो सकता है। यों भी सोच ज्यादा अस्थिर हो जाए, तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं। लगातार बहुत अधिक सोचने से हम सकारात्मक पक्ष से ज्यादा नकारात्मक पक्ष को सोचते हैं और फिर उसी तरह के खयाल हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। जरूरत है इस सोच के बोझ को कम करने की।

– महक द्विवेदी, रीवा

गुम होती सादगी

आज के युग में 'सादगी' शब्द किसी किसी कोने में दुबक कर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। विशेषकर हमारे जनसेवकों के जीवन में सादगी अब केवल चुनाव पूर्व जारी होने वाले 'घोषणापत्र' की शोभा बढ़ाने के काम आती है। जैसे ही मतपेटी से भाग्य का सूर्य उदय होता है, सादगी का 'सूर्यास्त' हो जाता है और 'वीआइपी संस्कृति' का बेलगाम दौर शुरू होता है। सादगी को तिलांजलि देना अब शायद अनिवार्य 'राजधर्म' बन गया है। अगर नेता के काफिले में शोर न हो, तो उसे लगता है कि उसकी सत्ता को लकवा मार गया है। सड़कों पर घंटों रुकी हुई एंबुलेंस और पसीने से तर-बतर जनता दरअसल उस 'वीआइपी' की सुविधा के लिए अपना अधिकार तक छोड़ने पर बेबस है। जिस जनता ने नेता को चुनकर भेजा, उसी से बचने के लिए सुरक्षा के अभेद्य दुर्ग बनाए जाते हैं। यह विलासिता का नया व्याकरण है।

– प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

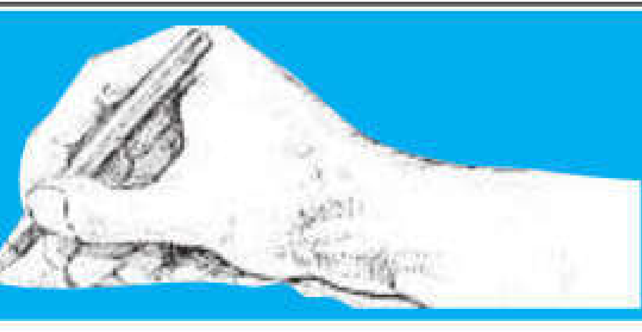

भारतीय बाजार सोने की चढ़ रही कीमतों से चकाचौंध है, और रविवार को पेश होने वाले बजट में इस पर खास नजर होगी। सोने की कीमतों की वजह से भारतीय बाजार में निवेश की प्रवृत्ति में भी बदलाव देखा गया है। भारत में पारंपरिक तौर पर भी सोना और अन्य कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश माना जाता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में वैश्किव संकट बढ़ रहा है, कई जगह पर युद्ध के हालात बने हुए हैं, इन अनिश्चतताओं को देखते हुए बाजार संभल कर चल रहा है।

बेबाक बोल

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है
–अदम गोंडवी

वैश्विक संकट वाले अध्याय को छोड़ दें तो आर्थिक सर्वेक्षण (2025–2026) के अध्यायों के पन्ने गुलाबी ही हैं। कल एक फरवरी को बजट पेश होगा और सस्ता–महंगा पर खूब चर्चा होगी। हालांकि यह हकीकत पूरे देश को कबूल है कि जीएसटी दरों के कारण अब बजट में पेश सस्ता व महंगा कुछ भी मायने नहीं रखता है। दिवाली के समय इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर जीएसटी की दरें घटाई गई थी तो अब तांबे की कीमत दोगुनी होने के कगार पर है। तांबे की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू उपकरण महंगे होने वाले हैं। खैरियत तांबे या पीतल की कीमतों से ही सब्र कर लेने में है। सोने–चांदी की बात कहीं दिल के अकस्मात रुक जाने का बायस न बन जाए। आर्थिक सर्वेक्षण के गुलाबी आंकड़े और महंगाई के लाल होते निशान पर बेबाक बोल।

यकुम फरवरी है...

मुकेश भारद्वाज

यकुम फरवरी है नया बजट है
जनवरी में पूछूंगा क्या हाल है...
बताने लगा रात बूढ़ा फकीर
ये दुनिया हमेशा से कंगाल है

अ मीर कजलबाश की नज्म के शेर अक्सर नए साल की एक जनवरी को याद किए जाते हैं। नया साल मुबारक कहने वालों, नए प्रण लेने वालों के बीच कजलबाश सच का सामना करवाते हुए आते हैं कि आज तो एक ही जनवरी है। साल के अंत दिसंबर में आप लोगों से हाल पूछे जाएंगे।

पिछले कुछ सालों से एक जनवरी को बहुत से लोग यह कहते मिल जाते हैं कि ग्रेग्रोरियन कैलेंडर वाले नए साल से हमारा क्या मतलब है? हमारा नया साल तो...। तीन बिंदुओं का अर्थ है कि भारत की क्षेत्रीय विविधता की बात करें तो हर क्षेत्र का पारंपरिक नया साल उस क्षेत्र की भौगोलिक व सांस्कृतिक खासियत के अनुसार होता है। यह तिथि अलग–अलग हो सकती है।

वहीं अर्थ, बटुआ, जेब, बजट की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान का नया साल एक फरवरी से शुरू होता है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, एक तरह की वर्गीय व गर्वीय समानता है। वर्गीय शब्द का अर्थ तो आर्थिक स्तरीकरण के तौर पर स्पष्ट है। गर्वीय समानता को यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है। एक फरवरी को बजट देख कर पूरे हिंदुस्तानियों का बटुआ गर्व करने की कोशिश करता है कि इस बार बिस्कुट, टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल या टूथपेस्ट सस्ता होगा और हमें इतनी बचत होगी। टीवी के परदे पर एक फरवरी को जीवंत प्रसारण के साथ व दो फरवरी को अखबारों की सुर्खियों में सस्ते की चमक देखते बनती है।

लेकिन बसंत का मौसम बीतने के बाद सस्ते की आस लगाया बटुआ पतझर वाले हालात का सामना करने लगता है। उपभोक्ता का पूर्व गर्वित मन सोशल मीडिया के प्रभावशालियों से हौसला लेते हुए खुद को प्रेरित करते हुए कितनी बार भी दुहरा ले कि बसंत आता नहीं लाया जाता है, लेकिन आम मध्य–वर्ग के बटुए की हकीकत पतझर सरीखी ही रहती है। बसंत तो कुछ देर तक सत्ता और उसके समर्थकों द्वारा लाया जाता है, स्थायी भाव तो पतझर का ही है।

वैसे जीएसटी ने यकुम फरवरी के सस्ते–महंगे वाले स्तंभ का भी सुख छीन लिया है। दिवाली के समय कह दिया गया कि जीएसटी बचत उत्सव मनाएं। दैनिक उपभोग की कुछ चीजों से जीएसटी बहुत कम कर दी गई, ये बताए बिना कि इसकी दरें इतनी ऊंची की ही क्यों गई थी। इसका तर्क तो यह दिया जा सकता है कि किसी चीज को अति महंगा खरीदेंगे तभी तो उसके सस्ते होने पर बचत उत्सव जैसी चीज मना पाएंगे। तो, हुआ यूं कि जीएसटी बचत उत्सव का एलान होते ही सरकार के एक सांसद ने कहा कि चीजें पचास फीसद तक सस्ती हो गई हैं। सत्ता समर्थकों ने जीएसटी उत्सव को दिवाली के बजाए होली जैसे उत्सव में बदल दिया, जहां धोखे से भांग खाने–खिलाने के बाद लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। जीएसटी की दरों के कम होने पर ऐसा उत्सवी माहौल था कि लगा दुकानदार लोगों के घरों में सामान फेंक कर जा रहे हैं कि भाई इतना सस्ता हो गया है कि क्या ही बेचें और क्या ही मुनाफा कमाएं। वैसे ही, जैसे आलू और प्याज के किसानों को करना पड़ता है। खास मौसम और समय में उनका मुनाफा इतना कम हो जाता है कि बाजार तक पहुंचाने की लागत उठाने के बजाय वे उन्हें सड़कों पर फेंकना पसंद करते हैं।

लौटते हैं सस्ते होने के तात्कालिक महोत्सव पर। पिछली दिवाली के समय की ही तो बात है जब हर तरफ चीजें सस्ती होने का दावा किया गया। लेकिन हकीकत कुछ समय बाद पता चली। मान लीजिए कि आप खुश हो गए कि बने–बनाए कुर्ते पर इतनी फीसद जीएसटी कम हो गई। लेकिन थोड़े समय बाद पता चलता है कि जिस सूत या धागे से वह कुर्ता बनाया जाता है, उस पर जीएसटी बढ़ा दी गई। जब कच्चा माल ही महंगा हो जाएगा तो उससे बना उत्पाद तो दुकानों में पुराने भंडार रहने तक ही सस्ता रह पाएगा।

अर्थव्यवस्था कोई इकहरी चीज नहीं होती है। हर एक उत्पाद कई परतों में होता है। पिछले साल के जीएसटी सुधारों के दावों के उलट नई हकीकत यह है कि कई अन्य धातुओं की तरह तांबे की कीमत ने भी आसमान को छुआ है। तांबा एक ऐसा धातु है जो ज्यादातर इलेक्ट्रानिक उपकरणों में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कीमत का एक हिस्सा तांबे की कीमत पर भी निर्भर करता है। बीते कुछ समय में तांबे की कीमतों में चालीस फीसद तक का इजाफा हुआ है जो आगे और भी महंगा होगा। सर्दी के मौसम को अलविदा कह जब लोग एसी, फ्रिज और पंखे की खरीदारी करने के लिए बाजार का रुख करेंगे, घरेलू उपकरणों पर 28 फीसद से कम होकर 18 फीसद का जीएसटी बचत उत्सव उनके लिए बीते जमाने की बात होगी। दिवाली के बाद होली का समय उनके लिए बचतोत्सव नहीं खर्चोत्सव में तब्दील हो जाएगा। खर्च के साथ उत्सव शब्द के साहचर्य को आर्थिक क्रूरता ही कहा जाएगा, लेकिन आम लोगों के बटुए और बजट के लिए यही क्रूरता अभी तक का सबसे बड़ा सच है।

कच्चा माल, डिब्बांदी और परिवहन की बढ़ी लागतों के कारण कई उत्पादों में जीएसटी खर्चोत्सव ही रहा है। पाम तेल और अन्य रसायनों की कीमत बढ़ने के कारण शैंपू जैसी चीज भी भारतीय उपभोक्ताओं के घरों में सस्ती नहीं पहुंच पाई थी। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों और बिस्कुट जैसी चीजों पर जीएसटी 18 फीसद से कम कर पांच फीसद पर आ गई थी। लेकिन कृषि आधारित कच्चे माल की कीमतों में तेजी व डिब्बाबंदी की लागत बढ़ने के कारण ये सस्ती नहीं हो सकीं। कापी–किताबों में भी कर में छूट मिली लेकिन कागज की लुगदी और कच्चे कागज के दाम बढ़ने से बटुआ हलकान ही रहा। यही हाल सीमेंट उद्योग का भी रहा।

यह एक आम भारतीय भी महसूस कर चुका है कि वैश्विक खींचतान का असर उसके घर के बजट पर किस तरह से पड़ रहा है। 2025–26 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी वैश्विक खींचतान के संदर्भ में 2026 के संकटग्रस्त समय होने की आशंका जाहिर की गई है। दुनिया भर में व्यापार और सुरक्षा के नियम तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आते ही बदल गए थे, 2026 के बाकी समय में इसके और बिगड़ने के आसार हैं।

दुनिया के सबसे शक्तिमान देश भी आर्थिक पाबंदियों के अलावा अर्थव्यवस्था के 'अ' में भी बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। रूस–यूक्रेन युद्ध से लेकर हर तरह के वैश्विक तनाव का असर अंतिम स्तर तक के भारतीय की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। सूचना तकनीक एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, जिसमें भारत विश्व गुरु सरीखा बनने की राह पर चला था, अब उसकी नौकरियों का भविष्य भी कृत्रिम मेधा के भविष्य पर निर्भर है। वैश्विक तनाव की वजह से भी सूचना तकनीक की नौकरियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 2025–26 के आर्थिक सर्वेक्षण में कृत्रिम मेधा से जुड़े मुश्किल हालात की भी तस्वीर पेश की गई है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाओं ने इसमें बेतहाशा पैसा लगाया है। जाहिर सी बात है कि निवेश किए गए पैसे का नतीजा 2026 में ही निकलेगा। बड़ी कंपनियों ने अरबों डालर के कर्ज लेकर डाटा केंद्रों पर निवेश किया है। भारत की भी नजरें इस क्षेत्र पर हैं। लेकिन यहां मुख्य सवाल डाटा बनाम आटा का रहेगा। चुनाव दर चुनाव सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त आटा दे रही है और डाटा नौकरियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के सरकारी कागज तो गुलाबी रंग बिखेरते हैं, लेकिन हमें खतरे के निशान पर नजर रखनी होगी। गुलाबी गहरा होकर लाल बनता है।

सवालों और शंकाओं की नापसंदगी के इस दौर में यकुम फरवरी को लेकर इतना ही,

'मैं रहता हूं हर शाम शिकवा–ब–लब
मिरे पास दीवान–ए–इकबाल है'

राजपाट

विरासत पर विमर्श

बिहार की सियासत में कई तरह की उठा–पटक चल रही है। गठबंधन सरकार के बावजूद भाजपा नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री बनाने को आतुर है तो नीतीश कुमार पर अपने बेटे निशांत को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने का दबाव है। उधर, जन सुराज पार्टी के जनता दल (एकी) में विलय के प्रयास भी चल रहे हैं। कभी नीतीश के दुलारे रहे आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोनों नीतीश की शरण में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बाधा बने हुए हैं। जबकि नीतीश कुमार का एक करीबी खेमा मानता है कि आरसीपी सिंह और पीके के फिर साथ आने से भाजपा का दबाव कम होगा और जद (एकी) की राजनीतिक पहचान मजबूत होगी। एक खेमा चाहता है कि हरिवंश की जगह संजय झा को राज्यसभा का उपसभापति बनवाकर निशांत को फिलहाल पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना देना चाहिए। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहें और निशांत को राज्यसभा भेज दें। निशांत पर फैसला नीतीश कुमार की सहमति न हो पाने से अटका है। अपने गुरु कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत के हिसाब से नीतीश अपने बेटे को खुद पार्टी में तरजीह देने के खिलाफ बताए जाते हैं। अन्यथा ललन सिंह ने तो बसंत पंचमी के दिन नीतीश को इसके लिए मनाने की पूरी कोशिश की थी। निशांत का मामला परिवारवाद को लेकर नया विमर्श खड़ा कर रहा है।

तटस्थ की तलाश

ओडीशा में राज्यसभा की चार सीटों के लिए होने वाले चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह चुनाव अप्रैल में होगा। सूबे की विधानसभा 147 सदस्यों की है। भाजपा के 79 विधायक हैं। उसे तीन निर्दलीयों का समर्थन भी हासिल है। प्रमुख विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) के पास 50 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 30 विधायकों का समर्थन चाहिए। अपने संख्या–बल के हिसाब से भाजपा दो और बीजद एक सीट जीत लेंगे। उसके बाद भाजपा के पास 22 और बीजद के पास 20 विधायक बचेंगे। कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं और एक माकपा का है। कांग्रेस चाहती है कि बीजद के साथ तालमेल हो जाए। अड़चन यह है कि घोषित तौर पर ये दोनों दल एक–दूसरे का समर्थन नहीं कर सकते। अब एक ही फार्मूला बच रहा कि किसी ऐसे निर्दलीय को उतार दिया जाए जो राजनीतिक नजरिये से तटस्थ हो।

काम से पहले मिला अवकाश

केंद्रीय बजट इस बार रविवार को पेश होगा। इस वजह से कई क्षेत्रों के लोगों को रविवार को अपने काम की जगह पर जाना होगा। इस बार संसद के बजट सत्र में शुक्रवार को बैठक नहीं थी, जिस कारण माननीयों को छुट्टी के दिन काम करने से पहले ही अवकाश का मौका मिल गया है। दरसअसल सामान्य तौर पर संसद की बैठक शनिवार व रविवार को नहीं होती है। लेकिन इस बार एक फरवरी को रविवार है और लंबे समय बाद वित्त मंत्री इस दिन बजट पेश करने जा रही हैं। इस वजह से सभी सांसदों को सदन में रविवार को भी उपस्थित रहना पड़ेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह राहत माननीयों के लिए शहीदी दिवस के अवकाश की वजह से हुई है।

वार–पलटवार

भाजपा तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाने के लिए सभी जतन कर रही है। दक्षिण के दो राज्यों केरल और तमिलनाडु में आरएसएस के प्रभाव के बावजूद भाजपा को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि 1998 में जयललिता से गठबंधन के कारण पार्टी ने तीन लोकसभा सीटें जीती थी। बाद में 1999 में डीएमके के साथ गठबंधन से भी उसे कोयंबटूर की सीट मिल गई थी। जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में बिखराव हुआ है और द्रमुक के मुकाबले वह कमजोर हुई है। फिर भी द्रमुक को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा ने अन्ना द्रमुक के सारे धरों को राजग में शामिल किया है। दूसरे छोटे दलों को भी साथ लेकर वह द्रमुक पर हमला कर रही है। तलवारें खिंच गई हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु दौरे में स्टालिन सरकार में नशाखोरी और महिलाओं की असुरक्षा का इल्जाम लगाया तो स्टालिन ने तंजावुर में द्रमुक के विशाल महिला सम्मेलन में जवाब दिया कि नशे का सामान देश में भाजपा शासित राज्यों से ही होकर आ रहा है। रही महिला सुरक्षा की बात, तो तमिलनाडु में वे सर्वाधिक सुरक्षित हैं। यहां स्थानीय निकायों में उन्हें 50 फीसद आरक्षण है और सबसे ज्यादा नौकरीपेशा महिलाएं तमिलनाडु में हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहला फैसला महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का किया था। स्टालिन ने केंद्र की सरकार को मणिपुर में हिंसा के लिए भी कठघरे में खड़ा किया।

उलझन दोनों तरफ

शशि थरूर को लेकर कांग्रेस के भीतर मंथन चल रहा है। केरल चुनाव के मद्देनजर पार्टी उन्हें बागी नहीं देखना चाहती। मुश्किल यह है कि वह उन्हें विधानसभा चुनाव का अपना चेहरा भी नहीं बनाना चाहती। उलझन में थरूर भी हैं। भाजपा में उन्हें अपना भविष्य बेहतर नजर नहीं आता। हाल में अटकलें उनके माकपा में जाने की भी लगी थी। वे दुबई के साहित्य उत्सव में गए थे तो वहां माकपा के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। इसी से उनके माकपा में जाने के कयास लगाए जाने लगे। पर माकपा सचिव गोविंदन ने कहा कि गाहे बगाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गीत गाने वाले थरूर के लिए माकपा में कोई जगह नहीं। उधर थरूर और कांग्रेस आलाकमान दोनों ही सुलह की कवायद में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक थरूर ने संसद के भीतर कभी भी पार्टी लाइन के उलट नहीं जाने की बात कही है, सिर्फ आपरेशन सिंदूर के अलावा। कांग्रेस को स्थानीय चुनाव में केरल में इस बार अच्छी सफलता मिली थी। लोकसभा में तो उसका प्रदर्शन अच्छा था ही। कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार की संभावना देख रही है और थरूर को भी लग रहा है कि भलाई कांग्रेस में बने रहने में ही है।

संकलन : मृणाल वल्लरी

आपके पत्र

खौफ की चादर

निश्चित रूप से किताबों के बहाने साहित्य, संस्कृति और परंपरा की प्रदर्शनी संपन्न हो गई। संपन्न हुए साहित्यिक सत्र के बीच 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' सुर्खियां बटोरती रही। संभव है इसके कई कारण हों, मगर नेपथ्य की वह खिड़की सबसे बड़ी वजह थी जिसके सामने मुस्कुराते चेहरों पर कैमरे चमक रहे थे। यानी कि वह सेल्फी केंद्र, जिसकी चमक ने साहित्य मंडप के सुलगते सवालों को धूमिल कर दिया। सवाल, जिनके जवाब दीवार की उस खिड़की के सामने अदब के वीराने में गुम है। चमचमाती रोशनी से दमकते मेले में सजी किताबों के किरदार मसलन लेखक, प्रकाशक और पाठकों के कशमकश की दास्तान है 'खाली खिड़की'। दुनिया भर की बेशकीमती किताबों ने बाजार की रौनक क्या बढ़ाई मुनाफे और फायदे की बहस रफ्तार पकड़ने लगी। मुनाफा और फायदा कोई अजूबा नहीं जो बाजार में तलाशे न जाएं। जाहिर है पढ़ने वालों के हाथों में जानेवाली किताबें तिजोरियां भर कर ही जाएंगी। बहस ये नहीं कि खरीदारों की हैसियत क्या है या किसने सुर्खियां बटोरी। सवाल यह है कि उन अदीबों के हिस्से में क्या आया जिन्होंने अपने जज्बातों को किताब की शक्ल दी। मेले की खामोशी बता गयी कि दीवार की खिड़की से झांकते कलमकारों के सामने खड़ी रायल्टी की खिड़की वीरान है। वीराने में खड़े अपनी पहचान तलाशते अदीबों को सरकारी खौफ की चादर उतारनी होगी।

–एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

कृपण कसौटी

'महाप्राण' की साहित्यिक वेदना आज भी प्रकाशक और लेखक के मध्य वह कृपण कसौटी है, जहां लेखनी अपनी आर्त्तवाणी को ही नियति मान चुकी है। दमखम वाले लेखकों की चांदनी में गुमसुम गगन में विचरण करते असंख्य निस्पृह साहित्य सेवकों के रायल्टी–राग अब प्रकाशकों के भौतिक प्रदीप्त होते 'मालामाल' के महासागर में विलुप्त हो चुकी है। पुस्तक मुद्रण के पूर्व प्रकाशक और लेखक के बीच हुए अनुबंध अनुष्ठान के आधार पर पुस्तकों की बिक्री कितनी हुई, इसे किसी भी परखनली में जांचने का पैमाना अभी तक निर्धारित नहीं किया जाना ही नेपथ्य का चातुर्य खेल है। अपने पूर्वज साहित्यकारों के इस आर्थिक शोषण की दारुण दशा देखकर ही हिंदी भाषा के नवोदित लेखकों ने अपने ठौर–ठिकाने से पलायन की राह चुन ली है। प्रकाशकों के विशाल क्षितिज में सरकारी प्रावधानों के पटाखे कोई ध्वनि नहीं सुना सकते, क्योंकि शब्दों के जलयान अर्थसागर में खंडित अवस्था में हैं। बुनियादी विडंबना यही है कि 'निराला' के नगीने से साहित्य के मर्म को तत्कालीन प्रकाशकों ने जब औसत आदर–आसन नहीं दिया तो वर्तमान भौतिकता के भवन में आधुनिक साहित्यकारों का सम्मान प्रकाशक क्यों करेंगे। काश, मैकाले नीति के विरुद्ध शंखनाद करती सरकार हिंदी लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों के बीच वर्षों से बंद खिड़की खोल पाती तो रायल्टी रंगशाला में हो रहे अभिनय कला को और नजदीक से हम समझ पाते। बहरहाल, उम्मीद के उम्दा सपनों में जीने का मजा ही कुछ और है।

–अशोक कुमार, पटना, बिहार।

हिंदी का असहज

वर्तमान समय में हिंदी प्रकाशन जगत एक गहरे अंतर्विरोध से गुजर रहा है। एक ओर प्रकाशकों के बढ़ते मुनाफे की घोषणाएं हैं, तो दूसरी ओर लेखक की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। यह विडंबना केवल बाजार की नहीं, बल्कि उस संरचना की है जिसमें हिंदी साहित्य आज सांस ले रहा है। हिंदी का प्रकाशन क्षेत्र धीरे–धीरे पाठक–केंद्रित होने के बजाय सरकारी खरीद पर आश्रित होता चला गया है। पुस्तक मेलों, सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों की खरीद ने प्रकाशकों के लिए एक सुरक्षित बाजार तैयार कर दिया है। इस व्यवस्था में किताब का मूल्य उसकी पठनीयता या सामाजिक प्रभाव से नहीं, बल्कि इस बात से तय होने लगा है कि वह किस पाठ्यक्रम, किस योजना या किस सरकारी सूची में शामिल है। नतीजा यह है कि वास्तविक पाठक और लेखक–दोनों हाशिये पर चले गए हैं। प्रकाशक आज मुनाफे की बात खुलकर करते हैं। लाखों–करोड़ों की बिक्री के दावे होते हैं, लेकिन इन आंकड़ों में लेखक की हिस्सेदारी लगभग अदृश्य रहती है। रायल्टी का प्रश्न एक औपचारिकता बनकर रह गया है और पारदर्शिता की कोई खिड़की खुलती दिखाई नहीं देती। लेखन को सेवा और त्याग के आदर्श में बांधकर, रचनात्मक श्रम का उचित मूल्य न देना एक सोची–समझी रणनीति प्रतीत होती है। सम्मान, मंच और प्रशंसा के बदले आर्थिक सुरक्षा छीन ली गई है। युवा लेखक अस्थिरता में जी रहा है, और अनुभवी लेखक भी मौन साधे हुए है–शायद इसलिए कि सवाल उठाने की जगह अब बची ही नहीं। लेखक, प्रकाशक और पाठक के बीच एक ईमानदार, पारदर्शी और न्यायपूर्ण संबंध स्थापित किए बिना हिंदी का भविष्य केवल कागजों और सरकारी फाइलों तक सिमट कर रह जाएगा।

–अजहर आलम अंसारी, धमदाहा, पूर्णिया।

साहित्य की भूमिका

वर्तमान समय में हिंदी साहित्य कितना बदला–बदला सा लगता है, जो साहित्य की रचनात्मक पुस्तक के पहले विमर्श का विषय हुआ करता था वह मात्र फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जंजाल में 'ट्रेंडिंग' नाम से वायरल होता है। जल्द ही किसी अन्य मुद्दे के आते ही सब कुछ अतीत हो जाता है। इसी बीच दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले का केंद्रीय कथ्य भारत के सशस्त्र बलों की भूमिका और विरासत को दर्शाता नजर आया। पुस्तक मेले की यह सांस्कृतिक परंपरा लेखक और पाठकों के बीच तन्मयता को जोड़ती है तथा साहित्यकार द्वारा हस्ताक्षरित पुस्तकों को पाठकों द्वारा पढ़ना साहित्य प्रेमी के बीच मेले में उमंग व उत्साह का रंग भरता है। साहित्य ज्वलंत मुद्दों पर परिचर्चा का केंद्र रहा है, जिसकी जरूरत फिर से महसूस होने लगी है।

– नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

रोजगार बनाम बाजार

हिंदी साहित्य और बाजार एक लंबे समय तक विरोधाभासी शब्द रहे हैं। इसलिए अब इसका जो बाजार बन रहा है, वह कायदे से बाजार जैसा है भी नहीं। हिंदी पट्टी में रोजगार की भाषा अंग्रेजी है इसलिए बाजार भी अंग्रेजी का मजबूत है।

–अंकुर सिंह, गाजियाबाद।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

Last Day to join Private Channel, I am closing it now.

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International

[Genaral & Exam related]

♦ English Editorials

[National + International Editorials]